

THE HINDU REVIEW



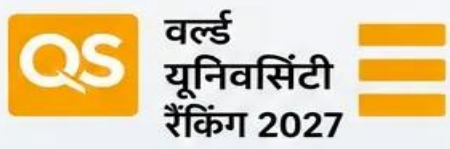
JUNE 2026

— महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स —

मासिक कैप्सूल



1 क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027



2 प्रधानमंत्री मोदी का ऐतिहासिक स्लोवाकिया दौरा



3 प्रधानमंत्री मोदी का फ्रांस दौरा



4 हुरुन इंडिया 500 रिपोर्ट 2026



5 इंडियन एथलेटिक्स अवॉर्ड्स 2025



6 आरबीआई मौद्रिक नीति समिति बैठक जून 2026



भारतीय रिजर्व बैंक
मौद्रिक नीति



7 52वां जी7 शिखर सम्मेलन 2026



इंडेक्स

जून 2026 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स.....	3
राष्ट्रीय समाचार.....	13
सरकारी योजनाएँ.....	19
अंतरराष्ट्रीय समाचार.....	21
बैंकिंग और वित्त.....	27
अर्थव्यवस्था और व्यापार.....	31
समझौता ज्ञापन और समझौते.....	34
नियुक्तियाँ और इस्तीफे.....	38
पुरस्कार.....	40
शिखर सम्मेलन और कार्यक्रम.....	42
रैंकिंग.....	44
रक्षा.....	47
विज्ञान प्रौद्योगिकी.....	50
खेल.....	52
पुस्तकें और लेखक.....	55
निधन.....	55
महत्वपूर्ण दिन.....	57
स्टेटिक टेकअवे.....	58

जून 2026 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स

QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027: भारत दुनिया में 5वें स्थान पर पहुंचा

QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत ने दुनिया भर में पांचवां स्थान हासिल किया है और लिस्ट में लगभग 52वें स्थान पर है। यह देश के बढ़ते एकेडमिक प्रभाव, बढ़ती रिसर्च क्षमताओं को दिखाता है और इससे दुनिया भर में नाम बेहतर होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (IIT) दिल्ली दुनिया भर में 118वें स्थान पर सबसे ऊंची रैंक वाला भारतीय संस्थान बनकर उभरा है, जो भारतीय टीम में सबसे आगे है।

QS रैंकिंग में भारत की अब तक की सबसे मज़बूत मौजूदगी

QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 ने 106 देशों के 1,500 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन को इवैल्यूएट किया है, जो इसे हायर एजुकेशन के लिए सबसे कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल असेसमेंट में से एक बनाता है।

साथ ही, पिछले कुछ सालों में भारत का रिप्रेजेंटेशन काफी बढ़ा है। 2017 एडिशन में सिर्फ़ 14 इंस्टीट्यूशन से, देश में अब 2027 में 52 रैंक वाली यूनिवर्सिटी हैं, जो एक दशक में 271 परसेंट की शानदार बढ़ोतरी है।

इस उपलब्धि से भारत सिर्फ़ इन देशों से पीछे है,

- संयुक्त राज्य अमेरिका (184 संस्थान)
- यूनाइटेड किंगडम (93 संस्थान)
- चीन (85 संस्थान)
- जर्मनी (60 संस्थान)

भारत अब दुनिया में पाँचवें सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन वाले हायर एजुकेशन सिस्टम के तौर पर रैंक करता है।

IIT दिल्ली भारत का टॉप रैंक वाला इंस्टीट्यूशन बना

भारतीय संस्थानों में, IIT दिल्ली ने दुनिया भर में 118वीं रैंक हासिल की है।

इंस्टीट्यूट ने भारत की लीडिंग यूनिवर्सिटी का अपना स्टेटस बनाए रखा और QS रैंकिंग में किसी भारतीय इंस्टीट्यूशन की अब तक की सबसे अच्छी ग्लोबल रैंकिंग के बराबर पहुंच गया।

शीर्ष प्रदर्शन करने वाले भारतीय संस्थानों में शामिल हैं,

- आईआईटी दिल्ली
- आईआईटी बॉम्बे
- आईआईटी मद्रास
- आईआईटी खड़गपुर
- भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी)

ये इंस्टीट्यूशन टीचिंग, रिसर्च, इनोवेशन और इंडस्ट्री एंगेजमेंट जैसे एरिया में एक्सीलेंस के ज़रिए इंडिया की ग्लोबल एकेडमिक रेप्युटेशन को मज़बूत कर रहे हैं।

QS रैंकिंग 2027 में टॉप ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़

ग्लोबल रैंकिंग में यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम के इंस्टीट्यूशन का दबदबा बना हुआ है।

दुनिया भर के टॉप 20 विश्वविद्यालय

रैंक	विश्वविद्यालय	देश
1	मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (एमआईटी)	संयुक्त राज्य अमेरिका
2	स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय	संयुक्त राज्य अमेरिका
3	इम्पीरियल कॉलेज	लंदन, यूनाइटेड किंगडम
4	ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय	यूनाइटेड किंगडम
5	विदेश महाविद्यालय	संयुक्त राज्य अमेरिका
6	कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय	यूनाइटेड किंगडम
7	कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (कैलटेक)	संयुक्त राज्य अमेरिका
8	यूसीएल	यूनाइटेड किंगडम
8	ईटीएच	ज्यूरिख, ETH
10	सिंगापुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय (एनयूएस)	सिंगापुर
11	हांगकांग विश्वविद्यालय	हांगकांग एसएआर
12	नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (एनटीयू)	सिंगापुर
13	पेकिंग विश्वविद्यालय	चीन
14	सिंचुआ विश्वविद्यालय	चीन
15	पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय	संयुक्त राज्य अमेरिका
16	येल विश्वविद्यालय	संयुक्त राज्य अमेरिका
16	कॉर्नेल विश्वविद्यालय	संयुक्त राज्य अमेरिका
18	चीनी विश्वविद्यालय, हांग कांग	हांगकांग एसएआर
19	यूएनएसडब्ल्यू	सिडनी, ऑस्ट्रेलिया
20	जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय	संयुक्त राज्य अमेरिका
20	यूनिवर्सिटी ऑफ़ कैलिफोर्निया, बर्केले	संयुक्त राज्य अमेरिका

यह रैंकिंग एशियाई यूनिवर्सिटीज़ की बढ़ती ताकत को भी दिखाती है, खासकर सिंगापुर, चीन, हांगकांग, साउथ कोरिया और जापान की।

भारत की बढ़ती अनुसंधान शक्ति

रैंकिंग की सबसे खास बातों में से एक भारत की बढ़ती रिसर्च परफॉर्मेंस है। QS के अनुसार, भारत के पास अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रिसर्च आउटपुट बेस है, जो साइंटिफिक पब्लिकेशन और एकेडमिक योगदान में हुई बड़ी बढ़ोतरी को दिखाता है।

अनुसंधान उपलब्धियाँ

- प्रति फैकल्टी साइटेशन के मामले में ग्यारह भारतीय यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में शामिल हैं।
- भारत साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और हेल्थकेयर फील्ड में अपनी ग्लोबल रिसर्च का दायरा बढ़ा रहा है।
- एकेडेमिया, इंडस्ट्री और सरकार के बीच बढ़ते सहयोग से इनोवेशन को बढ़ावा मिल रहा है।

एम्प्लॉयर की साख में मज़बूत प्रदर्शन

भारतीय संस्थान भी दुनिया भर के एम्प्लॉयर्स के बीच पहचान बना रहे हैं। QS रैंकिंग से पता चलता है कि,

एम्प्लॉयर रेप्युटेशन के लिए दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में छह भारतीय यूनिवर्सिटी शामिल हैं।

यह मेट्रिक यह मापता है कि एम्प्लॉयर अलग-अलग इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएट को कैसे देखते हैं और यह इंडियन हायर एजुकेशन की क्वालिटी में इंडस्ट्री के भरोसे को दिखाता है।

एम्प्लॉयर की अच्छी रेप्युटेशन बहुत ज़रूरी होती जा रही है, क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसी यूनिवर्सिटीज़ ढूँढ रहे हैं जो बेहतर करियर के मौके और ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट देती हों।

भारत की तुलना दूसरे बड़े एजुकेशन सिस्टम से कैसे की जाती है

कई स्थापित हायर एजुकेशन सिस्टम से तुलना की जाती है तो भारत का सुधार रेट सबसे अलग दिखता है।

प्रदर्शन तुलना

देश की रैंकिंग	संस्थानों में सुधार
चीन	85 72%
भारत	52 52%
यूके	93 35%
जर्मनी	60 16%
यूएसए	184 13%

जबकि अमेरिका और जर्मनी में कई संस्थानों की रैंकिंग में गिरावट आई है, भारत ने बड़े एजुकेशन सिस्टम में सबसे ज़्यादा सुधार दर दर्ज की है।

भारत के उदय के कारक

QS ने भारत की तरक्की का श्रेय कई खास वजहों को दिया।

भारत में दुनिया की सबसे युवा आबादी है, जिससे हायर एजुकेशन की बहुत ज़्यादा मांग है।

बढ़े हुए एनरोलमेंट और हायर एजुकेशन तक आसान पहुंच ने देश के एकेडमिक इकोसिस्टम को मजबूत किया है।

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 जैसी पहलों ने भी इंस्टीट्यूशनल सुधारों, इंटरनेशनलाइज़ेशन, मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग और रिसर्च में बेहतरीन काम को बढ़ावा दिया है।

भारतीय संस्थान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ तेज़ी से पार्टनरशिप कर रहे हैं जिससे एकेडमिक क्वालिटी और रिसर्च का असर बढ़ेगा।

PM मोदी का ऐतिहासिक स्लोवाकिया दौरा: भारत और स्लोवाकिया ने संबंधों को व्यापक साझेदारी तक बढ़ाया

माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाक प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के बुलावे पर 15 जून 2026 को स्लोवाकिया का ऐतिहासिक स्टेट विज़िट किया। यह विज़िट एक अहम पड़ाव था क्योंकि 1993 में देश को आज़ादी मिलने के बाद यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला विज़िट था। इस विज़िट ने भारत-स्लोवाकिया रिश्तों में एक नया चैप्टर खोला, जिससे दोनों देशों के रिश्ते एक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप तक बढ़े और डिफेंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, लेबर मोबिलिटी, कल्चर, हेल्थकेयर और रिसर्च में कई एग्रीमेंट पर साइन हुए।

भारत और स्लोवाकिया ने संबंधों को व्यापक साझेदारी तक बढ़ाया

इस दौर का एक सबसे बड़ा नतीजा यह हुआ कि दोनों देशों के रिश्तों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप तक बढ़ाने का फैसला हुआ।

इस नए फ्रेमवर्क का मकसद स्ट्रेटैजिक, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल और कल्चरल सेक्टर में सहयोग को गहरा करना है।

दोनों देश मौजूदा सहयोग के तरीकों को मज़बूत करने और नई टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, सिक््योरिटी, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में सहयोग के नए मौके तलाशने पर सहमत हुए हैं।

यह कदम आपसी विश्वास और लंबे समय के जुड़ाव के लिए एक साझा नज़रिए को दिखाता है।

यात्रा के दौरान साइन किए गए मुख्य समझौते

भारत और स्लोवाकिया ने अलग-अलग सेक्टरों को कवर करने वाले 11 ज़रूरी एग्रीमेंट्स और मेमोरेंडम्स पर साइन किए हैं।

इन एग्रीमेंट्स में लेबर माइग्रेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी, हायर एजुकेशन और रिसर्च, ऑडियो-विजुअल प्रोडक्शन, डिफेंस कोऑपरेशन, क्वांटम कम्प्युनिकेशन और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन में सहयोग शामिल है।

एक बड़ी बात यह हुई कि कोसिसे की टेक्निकल यूनिवर्सिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए पहली ICCR चेंयर बनाई गई, जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और एकेडमिक सहयोग पर बढ़ते फोकस को दिखाता है।

पिएस्तानी के बीच सहयोग, साथ ही स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, स्कॉलरशिप और जॉइंट रिसर्च के लिए IIT दिल्ली और स्लोवाक टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बीच पार्टनरशिप शामिल हैं।

दोनों देशों के बीच हुए समझौते और समझौता ज्ञापन

एस.नं.	समझौता/पहल
1	श्रम प्रवास पर समझौता ज्ञापन
2	रक्षा सहयोग पर आशय पत्र
3	डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर समझौता ज्ञापन
4	उच्च शिक्षा और अनुसंधान पर समझौता ज्ञापन
5	ऑडियो-विजुअल निर्माण पर समझौता ज्ञापन
6	कोसिसे तकनीकी विश्वविद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ICCR चेंयर
7	क्वांटम संचार और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा पर समझौता ज्ञापन

एस.नं.	समझौता/पहल
8	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ नेचुरोपैथी और स्लोवाक हेल्थ स्पा पिएस्तानी के बीच समझौता ज्ञापन
9	आईआईटी दिल्ली-स्लोवाक तकनीकी विश्वविद्यालय सहयोग समझौता
10	टूर ऑपरैटर्स के बीच पर्यटन सहयोग
11	INSA और SAS के बीच वैज्ञानिक सहयोग

यात्रा के दौरान प्रमुख घोषणाएँ

PM मोदी के दौरे के दौरान तीन बड़ी डिप्लोमैटिक घोषणाएं भी की गईं।

घोषणा घोषणा	महत्व
द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक साझेदारी तक बढ़ाना	विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग का विस्तार
आतंकवाद का मुकाबला करने पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना	सुरक्षा सहयोग बढ़ाता है
कांसुलरी वार्ता की स्थापना	लोगों से लोगों के बीच और कूटनीतिक जुड़ाव में सुधार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार मिला

माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 15 जून 2026 को ब्रातिस्लावा की अपनी पहली ऑफिशियल यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय सम्मान , यानी द ऑर्डर ऑफ़ द व्हाइट डबल क्रॉस (1st क्लास) से सम्मानित किया गया। यह अवॉर्ड पीटर पेलेग्रिनी ने भारत और स्लोवाकिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में मोदी के योगदान के लिए दिया।

प्रधानमंत्री मोदी को स्लोवाकिया का सर्वोच्च सम्मान मिला

ब्रातिस्लावा में एक सेरेमोनियल इवेंट के दौरान, प्रेसिडेंट पीटर पेलेग्रिनी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को द ऑर्डर ऑफ़ द व्हाइट डबल क्रॉस (1st क्लास) से सम्मानित किया, जो स्लोवाकिया की तरफ से विदेशी नागरिकों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सिविलियन और मिलिट्री स्टेट डेकोरेशन है।

आभार जताते हुए, PM मोदी ने यह अवॉर्ड भारत के लोगों को समर्पित किया और इसे भारत और स्लोवाकिया के बीच पक्की दोस्ती का प्रतीक बताया।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह पहचान दोनों देशों के बीच प्यार, भरोसे और आपसी सम्मान को दिखाती है।

ऑर्डर ऑफ़ द व्हाइट डबल क्रॉस क्या है?

ऑर्डर ऑफ़ द व्हाइट डबल क्रॉस स्लोवाकिया का सबसे बड़ा नेशनल अवॉर्ड है जो सिर्फ़ विदेशी नागरिकों को दिया जाता है।

यह सम्मान उन जाने-माने लोगों को दिया जाता है जिन्होंने स्लोवाकिया और दूसरे देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करने, इंटरनेशनल सहयोग को बढ़ावा देने और आपसी समझ को आगे बढ़ाने में बहुत अच्छा योगदान दिया है।

यह सम्मान मिलने से PM मोदी उन चुनिंदा ग्लोबल लीडर्स के ग्रुप में शामिल हो गए हैं जिन्हें स्लोवाकिया ने उनके डिप्लोमैटिक योगदान के लिए मान्यता दी है।

पुरस्कार का महत्व

यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी दूसरे देश से मिला 33वां इंटरनेशनल सम्मान है, जो भारत के बढ़ते ग्लोबल असर और डिप्लोमैटिक पहुंच को दिखाता है।

यह अवॉर्ड बाइलेटरल रिश्तों में ऐतिहासिक पल के साथ भी मेल खाता है, क्योंकि यह देश की आज़ादी के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा है।

यह पहचान ट्रेड, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इनोवेशन, एजुकेशन और लोगों के बीच लेन-देन जैसे एरिया में इंडिया-स्लोवाकिया कोऑपरेशन की बढ़ती अहमियत को दिखाती है।

भारत-स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत करना

इस दौरे के दौरान, भारत और स्लोवाकिया ने अपने रिश्ते को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप तक बढ़ाया और आपसी सहयोग में एक नया चैप्टर शुरू किया। खास सेक्टर्स को कवर करने वाले 11 एग्रीमेंट्स और MoUs पर साइन किए हैं, जिनमें शामिल हैं,

- श्रमिक प्रवास
- रक्षा सहयोग
- डिजिटल प्रौद्योगिकियां
- उच्च शिक्षा और अनुसंधान
- नवाचार और प्रौद्योगिकी साझेदारी

इन एग्रीमेंट से सहयोग गहरा होने और इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट के नए मौके बनने की उम्मीद है।

स्लोवाकिया की ऐतिहासिक यात्रा

प्रधानमंत्री मोदी का स्लोवाकिया दौरा ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि यह देश की आज़ादी के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला ऑफिशियल दौरा है।

यह दौरा उनके बड़े यूरोपियन आउटरीच का हिस्सा है, जिसका मकसद ट्रेड, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, इनोवेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यूरोपियन पार्टनर्स के साथ सहयोग बढ़ाना है।

स्लोवाकिया का सबसे बड़ा नेशनल अवॉर्ड मिलना, दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्तों और भविष्य में सहयोग के लिए दोनों देशों के साझा कमिटमेंट को और दिखाता है।

PM मोदी के फ्रांस दौरे की बड़ी उपलब्धि: भारत-फ्रांस के बीच 13 अहम समझौते, Innovation Roadmap 2030 पर बनी सहमति

भारत और फ्रांस ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे के दौरान 13 खास नतीजों की घोषणा करके अपनी लंबे समय से चली आ रही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत किया है। इन एग्रीमेंट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनोवेशन, ट्रेड, डिजिटल पेमेंट्स, एजुकेशन, हेल्थकेयर, रेलवे, डिफेंस और स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसे कई सेक्टर शामिल होंगे।

भारत-फ्रांस सामरिक संबंधों में नया अध्याय

नए नतीजे भारत-फ्रांस स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एक अहम पड़ाव हैं। दोनों देशों ने ज़रूरी और नई टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इनोवेशन इकोसिस्टम और स्ट्रेटेजिक सेक्टर में सहयोग के महत्व पर ज़ोर दिया है।

ये एग्रीमेंट दोनों देशों में बिज़नेस, रिसर्च, स्टार्टअप और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के लिए नए मौके बनाते हुए, बाइलेटरल कोऑपरेशन को बढ़ाने के बड़े मकसद से भी जुड़े हैं।

13 मुख्य नतीजों की लिस्ट

1. टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च और एजुकेशन में सहयोग को गाइड करने के लिए इंडिया-फ्रांस इनोवेशन रोडमैप 2030 को अपनाना
2. AI गवर्नेंस और ज़िम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस करने के लिए एक जॉइंट इंडिया-फ्रांस AI वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा।
3. NSTI, कानपुर में एरोनॉटिक्स और उससे जुड़े सेक्टर में स्किलिंग के लिए नेशनल सेंटर ऑफ़ एक्सिलेंस बनाने के लिए MoU
4. डिजिटल पेमेंट सहयोग को मज़बूत करने के लिए फ्रांस में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के इस्तेमाल को बढ़ाया जाएगा।
5. फ्रांस के लीडिंग स्टार्टअप कैंपस स्टेशन F में 10 और इंडियन स्टार्टअप का इनक्यूबेशन
6. भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) और फ्रांस के INRIA के बीच डिजिटल विज्ञान केंद्र की स्थापना
7. अकादमिक सहयोग को गहरा करने के लिए यूनिवर्सिटी पेरिस-सैकले में "एआई, इनोवेशन और कल्चर" पर ICCR इंडिया चेयर
8. डिजिटल हेल्थ रिसर्च में सहयोग के लिए ICMR और फ्रांस के हेल्थ डेटा हब के बीच लेटर ऑफ़ इंटेन्ट
9. अगले पांच सालों में आपसी व्यापार को दोगुना करने के लिए एक हाई-लेवल मैकेनिज्म बनाने पर सहमति
10. सप्लाय चेन और ज़रूरी सेक्टर में सहयोग बढ़ाने के लिए इकोनॉमिक सिक्योरिटी डायलॉग शुरू करना
11. भारत में रेलवे और हाई-स्पीड रेल के विकास पर इरादे की घोषणा
12. दोनों देशों के बीच क्लासिफाइड जानकारी के एक्सचेंज और प्रोटेक्शन पर जनरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट
13. माइक्रोप्रैक्टिटी रिसर्च और ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन पर ISRO और फ्रांस के CNES के बीच लेटर ऑफ़ इंटेन्ट

भारत-फ्रांस इनोवेशन रोडमैप 2030 का अनावरण किया गया

सबसे ज़रूरी घोषणाओं में से एक इंडिया-फ्रांस इनोवेशन रोडमैप 2030 को अपनाना था।

यह रोडमैप सहयोग को गाइड करने के लिए लॉन्ग-टर्म फ्रेमवर्क का काम करेगा,

- प्रौद्योगिकी विकास
- अनुसंधान और नवाचार
- वैज्ञानिक सहयोग
- शिक्षा और कौशल विकास
- स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र

इस पहल का मकसद इनोवेशन से होने वाली ग्रोथ को मज़बूत करना और दोनों देशों को नई टेक्नोलॉजी में लीडर बनाना भी है।

ये समझौते क्यों ज़रूरी हैं?

ये 13 नतीजे मिलकर दिखाते हैं कि भारत-फ्रांस के रिश्ते पारंपरिक डिप्लोमैटिक और डिफेंस रिश्तों से आगे बढ़ रहे हैं।

ये एग्रीमेंट फ्यूचर-ओरिएंटेड सेक्टर पर फोकस करते हैं, जैसे,

- कृत्रिम होशियारी
- डिजिटल नवाचार
- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी
- स्वास्थ्य सेवा अनुसंधान
- स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र
- आर्थिक सुरक्षा
- हरित और सतत विकास

वे मिलकर काम करने वाली लीडरशिप के साथ ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आकार देने के लिए दोनों देशों के शेयर्ड विज़न को भी मज़बूत करते हैं।

हरुन इंडिया 500 रिपोर्ट 2026: टॉप 10 कंपनियों का टोटल वैल्यूएशन में 27% हिस्सा

लेटेस्ट हरुन इंडिया 500 रिपोर्ट 2026 के मुताबिक, भारत के कॉर्पोरेट लैंडस्केप पर बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनियों के चुने हुए ग्रुप का दबदबा बना हुआ है। यह रिपोर्ट एक्सिस बैंक और बरगंडी प्राइवेट के साथ पार्टनरशिप में जारी की गई है और यह रिपोर्ट बताती है कि भारत की टॉप दस सबसे वैल्यूएबल कंपनियाँ मिलकर रैंकिंग में शामिल 500 फर्मों की कुल वैल्यूएशन का 27% हिस्सा हैं। हालांकि, पिछले साल कॉर्पोरेट जायंट्स की यह कुल वैल्यू ₹ 97 ट्रिलियन से घटकर ₹ 86 ट्रिलियन हो गई, क्योंकि वे भारत की कॉर्पोरेट इकॉनमी की बैकबोन बनी हुई हैं।

हरुन इंडिया 500 रिपोर्ट क्या है?

हरुन इंडिया 500 भारत की सबसे वैल्यूएबल कंपनियों की उनके मार्केट वैल्यूएशन के आधार पर सालाना रैंकिंग है।

यह रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर के रूप में काम करती है,

- कॉर्पोरेट धन सृजन
- क्षेत्रीय रुझान
- निवेशक भावना
- दीर्घकालिक व्यावसायिक प्रदर्शन
- भारत का विकसित होता आर्थिक परिदृश्य

2026 एडिशन में यह बताया गया है कि कैसे कंपनियों का छोटा ग्रुप भारत में कॉर्पोरेट वैल्यू क्रिएशन पर हावी है।

टॉप 10 कंपनियाँ ₹ 86 ट्रिलियन की वैल्यू को कंट्रोल करती हैं

इस रिपोर्ट के अनुसार, दस सबसे कीमती भारतीय कंपनियों की कुल कीमत लगभग ₹ 86 ट्रिलियन (लगभग \$908 बिलियन) है।

मुख्य हाइलाइट्स में शामिल हैं,

- टॉप 10 कंपनियों का हरुन इंडिया 500 की कुल वैल्यू में 27% हिस्सा है।
- इसके अलावा, कंबाईंड वैल्यूएशन पिछले साल के ₹ 97 ट्रिलियन से कम हो गया।
- पिछले दशक में टॉप 10 कंपनियों की कुल वैल्यू 3.5 गुना बढ़ी है।
- सात कंपनियों ने लगातार पांच साल तक टॉप 10 में अपनी जगह बनाए रखी है।

ये नतीजे भारत की सबसे बड़ी कंपनियों के बीच कॉर्पोरेट वेल्थ के कंसंट्रेशन को भी दिखाते हैं।

हुरुन इंडिया 500 रिपोर्ट में टॉप टेन फर्म

रैंक	कंपनी	मूल्य (करोड़ रुपये में)	मुख्यालय	सीईओ/एमडी
1	रिलायंस इंडस्ट्रीज	19,36,239	मुंबई	मुकेश अंबानी
2	एचडीएफसी बैंक	11,87,800	मुंबई	शशिधर जगदीशन
3	भारती एयरटेल	11,49,650	नई दिल्ली	शाश्वत शर्मा
4	आईसीआईसीआई बैंक	9,04,460	मुंबई	संदीप सूरज बख्शी
5	टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज	8,95,080	मुंबई	कुंचितम कृतिवासन
6	बजाज फाइनेंस	5,83,050	पुणे	राजीव जैन
7	लार्सन एंड टूब्रो	5,52,170	मुंबई	एस.एन. सुब्रमण्यम
8	भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज	4,86,140	मुंबई	आशीष कुमार चौहान
9	इन्फोसिस	4,79,270	बेंगलुरु	सलिल पारेख
10	सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज	4,33,880	मुंबई	कीर्ति गणोरकर

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा

मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज इस रैंकिंग में लीडर बनी हुई है।

मुख्य बातें

- वैल्यूएशन: ₹ 19.36 ट्रिलियन
- साल के दौरान सबसे ज्यादा एक्सल्यूट वैल्यू क्रिएटर
- ₹ 1.8 ट्रिलियन से अधिक की वृद्धि हुई
- टॉप 10 कंपनियों की वैल्यूएशन का लगभग पांचवां हिस्सा इसी कंपनी का है।

रिलायंस की लगातार लीडरशिप उसके एनर्जी, टेलीकॉम, रिटेल, डिजिटल सर्विसेज और नई टेक्नोलॉजीज में फैले अलग-अलग तरह के बिज़नेस मॉडल को दिखाती है।

एचडीएफसी बैंक दूसरे स्थान पर बना हुआ है

वैल्यूएशन में गिरावट के बावजूद HDFC बैंक दूसरे स्थान पर बना रहा। हालांकि इस साल इसकी वैल्यूएशन में 17% की गिरावट आई, फिर भी यह बैंक भारत की सबसे वैल्यूएबल कंपनियों में से एक है और यह देश के फाइनेंशियल सेक्टर का मुख्य पिलर है।

भारती एयरटेल एक बड़ी विजेता के रूप में उभरी

इस साल की रैंकिंग में सबसे बड़ी सफलता की कहानियों में से एक भारतीय एयरटेल है।

यह तीसरे स्थान पर पहुंच गया है और इसका वैल्यूएशन ₹ 11.5 ट्रिलियन तक पहुंच गया है।

इसके अलावा, पिछले पांच सालों में वैल्यूएशन 198% बढ़ा है। कंपनी की बढ़त भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में बढ़ते इन्वेस्टर के भरोसे को दिखाती है।

फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपना दबदबा मज़बूत किया

रिपोर्ट से पता चलता है कि फाइनेंशियल सर्विसेज भारत में कॉर्पोरेट वेल्थ क्रिएशन के सबसे मज़बूत ड्राइवर्स में से एक बनी हुई हैं। रैंकिंग में खास तौर पर शामिल बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में शामिल हैं,

आईसीआईसीआई बैंक

₹ 9 ट्रिलियन से ज्यादा वैल्यूएशन के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है।

बजाज फाइनेंस

बजाज फाइनेंस भी पहली बार टॉप 10 में शामिल हुआ है।

प्रमुख उपलब्धियों में शामिल हैं,

- एक साल में वैल्यूएशन 37% बढ़ा
- ₹ 5.83 ट्रिलियन वैल्यूएशन पर पहुंचा
- साल के दौरान प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएटर

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई)

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया भी टॉप टियर में शामिल हो गया है और यह भारत के कैपिटल मार्केट और रिटेल इन्वेस्टिंग इकोसिस्टम के तेज़ी से बढ़ने को दिखाता है।

ये डेवलपमेंट दिखाते हैं कि कैसे फाइनेंशियलाइजेशन भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी की खास थीम बन गया है।

आईटी दिग्गज पिछड़ रहे हैं

यह रिपोर्ट ट्रेडिशनल IT सर्विस कंपनियों से दूर इन्वेस्टर की पसंद में आए बड़े बदलाव को भी दिखाती है।

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस)

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भी पांचवें स्थान पर खिसक गई है।

साल के दौरान इसकी वैल्यूएशन में भी 44% की गिरावट आई है और पिछले पांच सालों में इसमें 2% की गिरावट आई है।

इन्फोसिस

इन्फोसिस नौवें स्थान पर आ गई है।

और पांच साल के समय में इसकी वैल्यूएशन में 36% की गिरावट आई है।

IT कंपनियाँ अपनी जगह क्यों खो रही हैं?

IT कंपनियों की किस्मत बदलने में कई वजहें हैं।

- धीमी वैश्विक प्रौद्योगिकी व्यय
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उदय
- घरेलू विकास विषयों की ओर बदलाव

इन सेक्टरों को भारत के लंबे समय के आर्थिक विस्तार से फायदा उठाने की बेहतर स्थिति में देखा जा रहा है।

एब्सोल्यूट वैल्यू क्रिएशन के हिसाब से टॉप 15 कंपनियाँ

रैंक 2025	5-साल की रैंक (2021)	कंपनी	उद्योग	मूल्य 2025 (₹ करोड़)	5 साल का बदलाव (₹ करोड़)
1	3	भारती एयरटेल	दूरसंचार	11,49,650	7,63,917
2	11	अडानी पावर	ऊर्जा	4,27,840	3,85,896
3	4	आईसीआईसीआई बैंक	वित्तीय सेवाएं	9,04,460	3,66,727
4	8	भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई)	वित्तीय सेवाएं	4,86,340	3,18,140
5	7	लार्सन एंड टूब्रो	निर्माण इंजीनियरिंग	5,52,170	3,01,937
6	2	एचडीएफसी बैंक	वित्तीय सेवाएं	11,87,800	2,82,161
7	15	महिंद्रा एंड महिंद्रा	ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक	3,85,190	2,74,944
8	1	रिलायंस इंडस्ट्रीज	ऊर्जा	19,36,230	2,70,849
9	10	सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज	स्वास्थ्य देखभाल	4,33,880	2,35,911
10	16	अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र	परिवहन और रसद	3,81,840	2,30,302
11	28	श्रीराम फाइनेंस	वित्तीय सेवाएं	2,20,530	1,81,853
12	12	टाइटन कंपनी	उपभोक्ता वस्तुओं	3,89,320	1,70,916
13	22	बजाज ऑटो	ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक	2,79,330	1,70,051
14	13	एक्सिस बैंक	वित्तीय सेवाएं	3,94,160	1,52,890
15	6	बजाज फाइनेंस	वित्तीय सेवाएं	5,83,050	1,51,745

एब्सोल्यूट वैल्यू क्रिएशन क्या है?

एब्सोल्यूट वैल्यू क्रिएशन, तय समय में कंपनी के मार्केट वैल्यूएशन में हुई कुल बढ़ोतरी को मापता है।

परसेंटेज ग्रोथ के उलट, जो छोटी फर्मों के लिए फायदेमंद है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्रिएशन उन कंपनियों को हाईलाइट करता है जिन्होंने शेयरहोल्डर्स के लिए रुपये में सबसे ज़्यादा वेल्थ बनाई है।

यह मेट्रिक खास तौर पर उपयोगी है क्योंकि यह दिखाता है ,

- दीर्घकालिक व्यावसायिक वृद्धि
- निवेशक विश्वास
- बड़े पैमाने पर धन सृजन
- सतत बाजार नेतृत्व

हरुन इंडिया 500 रैंकिंग साल 2021 और 2025 के बीच वैल्यूएशन गेन को ट्रैक करती है।

इंडियन एथलेटिक्स अवाइर्स 2025: नीरज चोपड़ा और पारुल चौधरी ने टॉप ऑनर्स जीते

पहले इंडियन एथलेटिक्स अवाइर्स 2025 में, ओलंपिक मेडल जीतने वाले जेवलिन श्रोअर नीरज चोपड़ा को नई दिल्ली में हुए समारोह में बेस्ट मेल एथलीट ऑफ़ द ईयर चुना गया। साथ ही, नेशनल रिकॉर्ड होल्डर पारुल चौधरी को फीमेल एथलीट ऑफ़ द ईयर का अवार्ड मिला।

यह अवार्ड एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ़ इंडिया (AFI) ने ऑर्गनाइज़ किया था और यह उन एथलीट्स, कोच, ऑफिशियल्स, स्टेट एसोसिएशनस और कंट्रीब्यूटर्स को पहचान देता है जिन्होंने देश में एथलेटिक्स की ग्रोथ में अहम रोल निभाया है।

नीरज चोपड़ा ने जीता साल का बेस्ट मेल एथलीट

भारत के सबसे मशहूर ट्रैक एंड फील्ड एथलीट और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने बेस्ट मेल एथलीट ऑफ़ द ईयर का अवार्ड जीतकर अपने शानदार करियर में एक और बड़ा सम्मान जोड़ लिया।

दो बार के ओलंपिक मेडलिस्ट ने चोट की मुश्किलों के बावजूद सबसे ऊंचे लेवल पर परफॉर्म करना जारी रखा।

टोक्यो में 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप से पहले लगी पीठ की चोट से उबरने के बाद, चोपड़ा ने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में मज़बूती से वापसी की है।

उनकी एक बड़ी कामयाबी तब मिली जब वे जेवलिन थ्रो में 90-मीटर का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय एथलीट बने और दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर का शानदार थ्रो किया।

पारुल चौधरी को सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट चुना गया

डिस्टेंस रनर और स्टीपलचेज़ स्पेशलिस्ट पारुल चौधरी को बेस्ट फीमेल एथलीट ऑफ़ द ईयर का टाइटल दिया गया।

पारुल ने बहुत सफल सीज़न का आनंद लिया और एशियन चैंपियनशिप में महिलाओं की 3000m स्टीपलचेज़ और 5000m दोनों इवेंट्स में गोल्ड मेडल जीते।

वह भारत की सबसे अच्छी लंबी दूरी की रनर में से एक हैं और मिडिल और लंबी दूरी की एथलेटिक्स में बेंचमार्क सेट करती रहती हैं।

पीटी उषा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड विजेताओं में शामिल

सेरेमनी का सबसे इमोशनल पल तब आया जब मशहूर स्पिंटर और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट पीटी उषा को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला।

उन्हें भारत की सबसे महान एथलीटों में से एक माना जाता है, और भारतीय खेलों में PT उषा का योगदान कई दशकों तक रहा है।

उन्होंने एथलीट्स की कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है और स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन और एथलीट डेवलपमेंट में योगदान देना जारी रखा है। लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड पाने वालों में ये लोग भी शामिल थे,

- गुरबचन सिंह रंधावा - पूर्व एशियाई खेलों के डेकाथलॉन चैंपियन
- बहादुर सिंह चौहान - पूर्व राष्ट्रीय एथलेटिक्स कोच
- अंजू बाँबी जॉर्ज - वर्ल्ड चैंपियनशिप में लॉन्ग जंप में ब्रॉन्ज़ मेडलिस्ट

उभरते हुए एथलीटों को पहचान मिली

इंडियन एथलेटिक्स अवाइर्स का फोकस अगली पीढ़ी के टैलेंट को बढ़ावा देने पर भी था।

- बेस्ट इमर्जिंग मेल एथलीट: शाहनवाज़ खान
 - सर्वश्रेष्ठ उभरती महिला एथलीट: पूजा सिंह
- दोनों एथलीटों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और उन्हें भारतीय एथलेटिक्स का भविष्य का सितारा माना जा रहा है।

अन्य प्रमुख पुरस्कार विजेता

कई लोगों और ऑर्गनाइज़ेशन को इस खेल में उनके योगदान के लिए पहचान मिली है।

- साल के बेस्ट कोच: परवीर सिंह
 - साल के बेस्ट टेक्निकल ऑफिसर: डॉ. कुलदीप सिंह
 - बेस्ट स्टेट एसोसिएशन ऑफ द ईयर: तमिलनाडु एथलेटिक्स एसोसिएशन
 - एथलेटिक्स को सपोर्ट करने वाला बेस्ट स्टेट: ओडिशा सरकार
- ये अवॉर्ड न सिर्फ एथलीट्स को बल्कि उन कोच, एडमिनिस्ट्रेटर्स, अधिकारियों और इंस्टीट्यूशन्स को भी दिए जाते हैं जो एक मज़बूत एथलेटिक्स इकोसिस्टम बनाने में मदद करते हैं।

इंडियन एथलेटिक्स अवाइर्स 2025 विनर्स लिस्ट

वर्ग	विजेता
वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट	नीरज चोपड़ा
वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट	पारुल चौधरी
सर्वश्रेष्ठ उभरते पुरुष एथलीट	शाहनवाज़ खान
सर्वश्रेष्ठ उभरती महिला एथलीट	पूजा सिंह
वर्ष का सर्वश्रेष्ठ कोच	परवीर सिंह
सर्वश्रेष्ठ तकनीकी अधिकारी	डॉ. कुलदीप सिंह
सर्वश्रेष्ठ राज्य संघ	तमिलनाडु एथलेटिक्स एसोसिएशन
सर्वश्रेष्ठ राज्य सहायक एथलेटिक्स	ओडिशा सरकार
लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड	पीटी उषा, गुरबचन सिंह रंधावा, बहादुर सिंह चौहान, अंजू बाँबी जॉर्ज

आरबीआई मौद्रिक नीति बैठक जून 2026

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में 3 जून से 5 जून, 2026 तक आयोजित मौद्रिक नीति समिति (MPC) की 61वीं बैठक के बाद अपने नवीनतम मौद्रिक नीति निर्णयों की घोषणा की।

बढ़ती जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता, एनर्जी की बढ़ी हुई कीमतों, ग्लोबल सप्लाय चैन में रुकावटों और महंगाई की चिंताओं के बीच, कमिटी ने न्यूट्रल पॉलिसी रख जारी रखते हुए मौजूदा पॉलिसी रेट को बनाए रखने का फैसला किया।

यह फैसला RBI के आर्थिक विकास को सपोर्ट करने और महंगाई के जोखिमों के प्रति सतर्क रहने के संतुलित नज़रिए को दिखाता है।

RBI मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग जून 2026: मुख्य फैसले

घरेलू और ग्लोबल मैक्रोइकोनॉमिक डेवलपमेंट का रिब्यू करने के बाद, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने एकमत से यह फैसला किया:

- रेपो रेट को 5.25% पर अपरिवर्तित रखें
- स्टैंडिंग डिपॉज़िट फ़ैसिलिटी (SDF) रेट 5.00% पर बनाए रखें
- मार्जिनल स्टैंडिंग फ़ैसिलिटी (MSF) रेट को 5.50% पर बनाए रखें
- तटस्थ नीति रख जारी रखें

इस फैसले से पता चलता है कि RBI अभी आगे कोई बदलाव करने से पहले वेट-एंड-वाँच अप्रोच अपना रहा है।

मौद्रिक नीति समिति के सदस्य

मीटिंग में ये लोग शामिल हुए:

- श्री संजय मल्होत्रा - गवर्नर, आरबीआई
- डॉ. नागेश कुमार
- श्री सौगत भट्टाचार्य
- प्रो. राम सिंह
- डॉ. पूनम गुप्ता
- श्री इंद्रनील भट्टाचार्य

सभी सदस्यों ने एकमत से रेपो रेट को अपरिवर्तित रखने के पक्ष में मतदान किया।

रेपो रेट क्या है?

रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिज़र्व बैंक कमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देता है।

रेपो रेट के असर में बदलाव:

- ऋण ब्याज दरें
- जमा दरें
- मुद्रास्फीति के स्तर
- आर्थिक विकास
- खर्च करता उपभोक्ता

कम रेपो रेट आम तौर पर उधार लेने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है, जबकि ज़्यादा रेपो रेट महंगाई को कंट्रोल करने में मदद करता है।

RBI ने रेपो रेट में कोई बदलाव क्यों नहीं किया?

RBI ने कहा कि बदलते ग्लोबल हालात की वजह से ग्रोथ और महंगाई दोनों का रिस्क बढ़ गया है।

बताई गई मुख्य चिंताओं में शामिल हैं:

- पश्चिम एशिया में लंबे समय तक संघर्ष
- कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें
- आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान
- वस्तु की कीमत में वृद्धि
- वैश्विक वित्तीय बाजार में अस्थिरता

हालांकि अभी महंगाई कंट्रोल में है, लेकिन भविष्य में कीमतों का दबाव अभी भी अनिश्चित है।

RBI ने यह नतीजा निकाला कि आगे मॉनेटरी पॉलिसी में बदलाव करने से पहले और क्लैरिटी की ज़रूरत है।

वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण

RBI ने कहा कि ग्लोबल इकॉनमी में अनिश्चितता बढ़ती जा रही है।

मुख्य ग्लोबल डेवलपमेंट में शामिल हैं:

- ऊर्जा बाजार में अस्थिरता
- कच्चे तेल के भंडार में गिरावट
- बढ़ती वस्तु कीमतें
- उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में सख्त होती मौद्रिक स्थितियां
- अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना

महंगाई का दबाव बना रहने की वजह से ग्लोबल सेंट्रल बैंकों के सावधान रहने की उम्मीद है।

भारत का घरेलू आर्थिक परिदृश्य

ग्लोबल अनिश्चितता के बावजूद, भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत बनी हुई है।

मुख्य घरेलू इंडिकेटर्स ने दिखाया:

- स्थिर आर्थिक गतिविधि
- मजबूत निजी खपत
- निरंतर निवेश गति
- व्यापारिक निर्यात में वृद्धि
- मजबूत सेवा निर्यात

हालाँकि, ज़्यादा इनपुट कॉस्ट और स्प्ललाई में रुकावट के असर दिखने लगे हैं।

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आरबीआई ग्रोथ का अनुमान

सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, RBI ने अनुमान लगाया:

वास्तविक GDP वृद्धि: 6.6%

तिमाही-वार अनुमान:

- Q1: 6.6%
- Q2: 6.3%
- Q3: 6.5%
- Q4: 6.8%

सेंट्रल बैंक ने बताया कि ग्रोथ रिस्क अभी भी बने हुए हैं, क्योंकि:

- वैश्विक आपूर्ति व्यवधान
- वित्तीय बाजार की अस्थिरता
- मौसम संबंधी अनिश्चितताएँ

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान

खाने-पीने की चीज़ों और एनर्जी की ज़्यादा कीमतों की वजह से RBI ने महंगाई की उम्मीदों को बढ़ा दिया है।

अनुमानित CPI मुद्रास्फीति:

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 5.1%

तिमाही-वार अनुमान:

- Q1: 4.2%
- Q2: 5.1%
- Q3: 5.9%
- Q4: 5.4%

कोर इन्फ्लेशन का अनुमान इस प्रकार है:

4.7% RBI ने कहा कि फ्यूल की बढ़ती कीमतों और प्रोडक्शन कॉस्ट पर दूसरे दौर के असर की वजह से महंगाई और बढ़ सकती है।

RBI ने महंगाई के बड़े जोखिमों की पहचान की

मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने कई उभरते रिस्क पर रोशनी डाली।

इसमें शामिल है:

- पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी
- उच्च परिवहन लागत
- औद्योगिक इनपुट की बढ़ती कीमतें
- वैश्विक ऊर्जा झटके
- आपूर्ति श्रृंखला की अड़चनें
- कमजोर मानसून की स्थिति

पूरी इकॉनमी में महंगाई के फैलने की संभावना एक बड़ी चिंता बनी हुई है।

पॉलिसी आउटलुक पर मॉनसून और अल नीनो का असर

RBI ने मौसम की स्थिति को भी एक बड़ा जोखिम बताया है।

चिंताओं में शामिल हैं:

- दक्षिण-पश्चिम मानसून की कमी
- अल नीनो की स्थितियाँ
- कृषि उत्पादन पर दबाव
- ग्रामीण मांग अनिश्चितता

हालाँकि, बचाव के उपाय जैसे:

- फसल विविधीकरण
- जल संरक्षण
- जलवायु-प्रतिरोधी कृषि
- कम अवधि की फसलें

उम्मीद है कि इससे कुछ रिस्क कम होंगे।

आर्थिक स्थिरता को समर्थन देने वाले सरकारी उपाय

RBI ने सरकार की कई पहलों को माना, जिनसे लचीलापन मजबूत हुआ।

इसमें शामिल है:

- एमएसएमई के लिए समर्थन
- निर्यात संवर्धन उपाय
- घरेलू ऊर्जा उत्पादन विस्तार
- आयात विविधीकरण
- बुनियादी ढांचा निवेश

ये उपाय ग्लोबल झटकों से होने वाली कमज़ोरी को कम करने में मदद कर रहे हैं।

न्यूट्रल रख का क्या मतलब है?

न्यूट्रल रख का मतलब है कि RBI फ्लेक्सिबल बना रहेगा।

सेंट्रल बैंक यह कर सकता है:

- अगर महंगाई बढ़ती है तो दरें बढ़ाएँ
- अगर ग्रोथ कमज़ोर होती है तो रेट कम करें
- अगर हालात ठीक रहे तो रेट बनाए रखें

इस तरीके से RBI को भविष्य में होने वाले डेवलपमेंट पर जल्दी रिस्पॉन्ड करने में मदद मिलती है।

RBI मॉनेटरी पॉलिसी जून 2026 क्यों जरूरी है?

जून 2026 का पॉलिसी फैसला इसलिए जरूरी है क्योंकि यह RBI की बैलेंसिंग की स्ट्रेटेजी को दिखाता है:

- मुद्रास्फीति नियंत्रण
 - आर्थिक विकास
 - वित्तीय स्थिरता
 - वैश्विक अनिश्चितता
 - घरेलू मांग
- डेटा पर निर्भर रहेगी।

अगली RBI MPC मीटिंग कब है?

भारतीय रिज़र्व बैंक ने घोषणा की है कि अगली मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की मीटिंग इस तारीख को होगी:

3 अगस्त से 5 अगस्त, 2026

जून 2026 की मीटिंग के मिनट्स 19 जून 2026 को जारी किए जाएंगे। RBI की नई पॉलिसी में सावधानी भरा उम्मीद दिखाया गया है—आने वाले महीनों में महंगाई के दबाव और बाहरी झटकों के लिए तैयारी करते हुए ग्रोथ को सपोर्ट किया गया है।

52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026: मुख्य परिणाम

52वां G7 समिट फ्रांस के एवियन-लेस-बेन्स में फ्रांस की अध्यक्षता में हुआ। इस समिट में दुनिया की बड़ी एडवांस्ड इकॉनमी के लीडर्स के साथ-साथ बुलाए गए पार्टनर देश भी शामिल हुए, ताकि जियोपॉलिटिकल झगड़े, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल इकॉनमिक स्टेबिलिटी, एनर्जी सिक्योरिटी और सप्लाई चेन रेजिलिएंस जैसी जरूरी ग्लोबल चुनौतियों पर चर्चा की जा सके। 2026 के समिट की थीम थी "नई पार्टनरशिप बनाना और इंटरनेशनल सॉलिडैरिटी को फिर से बनाना", जो तेज़ी से बिखरते ग्लोबल ऑर्डर में मज़बूत इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत पर ज़ोर देता है।

भारत ने समिट के हाई-लेवल आउटरीच सेशन में हिस्सा लिया और इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ग्लोबल साउथ की चिंताओं और उम्मीदों को बताने के लिए किया। चर्चा के दौरान, भारत ने इनक्लूसिव ग्लोबल गवर्नेंस, इन्फ्लेक्शन डेवलपमेंट, क्लाइमेट जस्टिस, डेवलपिंग देशों के लिए मज़बूत रिप्रेजेंटेशन, और ट्रेडिशनल डेवलपमेंट पार्टनरशिप को इकालिटी और आपसी भरोसे पर आधारित रिश्तों में बदलने पर ज़ोर दिया।

समिट यूक्रेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट एक्शन, मज़बूत सप्लाई चेन और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ पार्टनरशिप पर कई जरूरी फैसलों के साथ खत्म हुआ। इसने ग्लोबल इकॉनॉमिक और जियोपॉलिटिकल मामलों में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर भारत की बढ़ती अहमियत को भी पक्का किया।

G7 समिट 2026 चर्चा में क्यों है?

गवर्नेंस, ग्लोबल आर्थिक अनिश्चितताओं, और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ पार्टनरशिप को मज़बूत करने की ज़रूरत पर चर्चा हुई। एक इनवाइटेड पार्टनर के तौर पर भारत की एक्टिव भागीदारी ने डेवलपिंग देशों के बीच उसके बढ़ते डिप्लोमैटिक असर और लीडरशिप को और हाईलाइट किया।

इस समिट में फ्रांस का G7 प्रेसिडेंट के तौर पर आखिरी साल भी शामिल था, इससे पहले कि 2027 में प्रेसिडेंट का पद यूनाइटेड स्टेट्स को ट्रांसफर हो जाए।

52वें G7 शिखर सम्मेलन का विषय

समिट का ऑफिशियल थीम था:

"नई पार्टनरशिप बनाना और इंटरनेशनल सॉलिडैरिटी को फिर से बनाना।" यह थीम G7 देशों के देशों के बीच भरोसा फिर से बनाने, मल्टीलेटरल सहयोग को मज़बूत करने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने और सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टनरशिप के ज़रिए आम ग्लोबल चुनौतियों का सामना करने के सामूहिक कमिटमेंट को दिखाती है।

G7 आउटरीच सेशन क्या हैं?

आउटरीच सेशन G7 होस्ट देश द्वारा ऑर्गनाइज़ की गई स्पेशल मीटिंग होती हैं, जिसमें बुलाए गए देश और इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन G7 मेंबर्स के साथ हिस्सा लेते हैं।

ये सेशन इस आलोचना को दूर करने के लिए शुरू किए गए थे कि G7 मुख्य रूप से डेवलपड इकॉनमी को रिप्रेजेंट करता है, जबकि उभरते और डेवलपिंग देशों को बाहर रखा गया है। भारत, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया और दूसरे देशों को क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी, ग्लोबल गवर्नेंस, डेवलपमेंट फ़ाइनेंस, टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल इकॉनमिक ग्रोथ जैसे मुद्दों पर अपने विचार शेयर करने के लिए बुलाया गया है।

इन आउटरीच सेशन में भारत की भागीदारी ग्लोबल डिजीजन-मेकिंग में इसकी बढ़ती अहमियत को दिखाती है।

52वें G7 शिखर सम्मेलन के मुख्य नतीजे**यूक्रेन के लिए समर्थन मज़बूत करना**

G7 नेताओं ने यूक्रेन के लिए अपने पक्के सपोर्ट को फिर से दोहराया और मिलिट्री, फाइनेंशियल और मानवीय मदद जारी रखने का वादा किया। उन्होंने चल रहे संघर्ष के बीच यूक्रेन की डिफेंस क्षमताओं को बढ़ाने और देश की एनर्जी रेजिलिएंस को मज़बूत करने का वादा किया।

समिट में मिडिल ईस्ट में बदलते सिक्योरिटी हालात पर भी चर्चा हुई, अमेरिका और ईरान के बीच शुरुआती डिप्लोमैटिक बातचीत का स्वागत किया गया, और लेबनान में सीज़फ़ायर के लिए कोशिश करने की अपील की गई।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए वैश्विक ढांचा

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चर्चा के मुख्य विषयों में से एक बनकर उभरा। G7 लीडर्स AI टेक्नोलॉजी के सेफ, सिक्योर और ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल को पक्का करने के लिए कॉमन टेक्निकल और एथिकल फ्रेमवर्क बनाने पर सहमत हुए। प्रपोज़्ड फ्रेमवर्क का मकसद साइबर सिक्योरिटी, गलत जानकारी, प्राइवेसी, ट्रांसपेरेंसी और ज़िम्मेदार AI गवर्नेंस से जुड़ी चिंताओं को दूर करते हुए इनोवेशन को बढ़ावा देना है।

नेताओं ने इस बात पर ज़ोर दिया कि AI दुनिया भर के समाजों के लिए सुलभ, भरोसेमंद और फ़ायदेमंद बना रहना चाहिए।

लचीली वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं का निर्माण

हाल के जियोपॉलिटिकल संकटों और महामारी से सामने आई कमज़ोरियों को पहचानते हुए, G7 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क में विविधता लाने और एक देश की सप्लाई चेन पर बहुत ज़्यादा निर्भरता कम करने पर सहमत हुआ।

नेताओं ने भारत, वियतनाम और मेक्सिको जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप बढ़ाने का वादा किया। इन कोशिशों से ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क मजबूत होने, आर्थिक मजबूती में सुधार होने और ज़रूरी मिनरल और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन बेहतर होने की उम्मीद है।

जलवायु कार्रवाई और पर्यावरण सुरक्षा

क्लाइमेट चेंज समिट की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक रहा।

G7 ने G7 2030 नेचर कॉम्पैक्ट के तहत हुई प्रोग्रेस का रिव्यू किया और ऑफिशियली लैंड डिग्रेडेशन, डेज़र्टिफिकेशन और सूखे को सिस्टमिक ग्लोबल सिक्योरिटी खतरों के तौर पर माना।

नेताओं ने बायोडायवर्सिटी बचाने, सस्टेनेबल खेती, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट अडैप्टेशन और एनवायरनमेंट को ठीक करने में मज़बूत इंटरनेशनल सहयोग पर ज़ोर दिया।

वैश्विक दक्षिण के साथ अधिक जुड़ाव

समिट का मुख्य फोकस डेवलपिंग देशों के साथ सहयोग बढ़ाना था।

भारत और दूसरे बुलाए गए देशों ने ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंस में सुधारों की वकालत की, जिसमें ट्रेडिशनल डोनर-रिसीपिएंट मॉडल की जगह भरोसे, कोलेबोरेशन और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आधारित बराबर पार्टनरशिप को लाया जाना चाहिए।

डेवलपिंग देशों ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन और ज़्यादा इनक्लूसिव ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर की भी मांग की।

G7 समिट में भारत के मुख्य संदेश**वैश्विक विश्वास का पुनर्निर्माण**

भारत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि देशों के बीच भरोसा कम होना, ग्लोबल चुनौतियों को हल करने में सबसे बड़ी रुकावटों में से एक बन गया है। इसमें कहा गया कि इंटरनेशनल सहयोग को फिर से बनाने के लिए ट्रांसपेरेंसी, बातचीत, आपसी सम्मान और साझा जिम्मेदारी ज़रूरी हैं।

साझेदारी-आधारित विकास

भारत ने पारंपरिक मदद पर आधारित रिश्तों से आगे बढ़ने की ज़ोरदार वकालत की।

इसके बजाय, इसने बराबरी, आपसी फ़ायदे, कैपेसिटी बिल्डिंग और लंबे समय तक सहयोग पर आधारित डेवलपमेंट पार्टनरशिप की मांग की।

वैश्विक दक्षिण के लिए मज़बूत आवाज़

भारत ने फिर कहा कि विकासशील देशों को सिर्फ़ फ़ाइनेंशियल मदद के बजाय इंटरनेशनल फ़ैसले लेने वाली संस्थाओं में ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है।

इसमें मौजूदा जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक हकीकत को बेहतर ढंग से दिखाने के लिए ग्लोबल गवर्नेंस में सुधार की मांग की गई।

भारत-अफ्रीका विकास साझेदारी

भारत ने साउथ-साउथ कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थकेयर, एजुकेशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी-बिल्डिंग इनिशिएटिव के ज़रिए अफ्रीकी देशों के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे सहयोग पर ज़ोर दिया।

देश ने पूरे अफ्रीका में सस्टेनेबल और लोकल डेवलपमेंट को सपोर्ट करने का अपना कमिटमेंट दोहराया।

G7 के बारे में

ग्रुप ऑफ़ सेवन (G7) दुनिया की बड़ी एडवांस्ड इकॉनमी का एक इनफॉर्मल ग्रुप है।

इसके सदस्यों में शामिल हैं:

- कनाडा
- फ्रांस
- जर्मनी
- इटली
- जापान
- यूनाइटेड किंगडम
- संयुक्त राज्य अमेरिका

यूरोपियन यूनियन भी G7 चर्चाओं में भाग लेता है।

फॉर्मल इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन के उलट, G7 का कोई परमानेंट सेक्रेटरीएट या कानूनी तौर पर ज़रूरी अथॉरिटी नहीं है। फ़ैसले आम सहमति से लिए जाते हैं।

जी7 के उद्देश्य

G7 के मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं:

- वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना
- सतत आर्थिक विकास का समर्थन
- वित्तीय संकटों के प्रति प्रतिक्रियाओं का समन्वय
- जलवायु परिवर्तन पर ध्यान
- वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करना
- खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना
- लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना
- नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थन करना
- भू-राजनीतिक और सुरक्षा नीतियों का समन्वय

G7 कैसे काम करता है?

प्रेसीडेंसी हर साल सदस्य देशों के बीच रोटेट होती है।

अध्यक्षता करने वाला देश सालाना समिट होस्ट करता है, एजेंडा तय करता है, और पूरे साल मिनिस्टीरियल मीटिंग्स को कोऑर्डिनेट करता है।

पार्टनर देशों और इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन को अक्सर ग्लोबल पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए आउटरीच सेशन में बुलाया जाता है।

हालांकि G7 के फ़ैसले कानूनी तौर पर ज़रूरी नहीं हैं, लेकिन वे इंटरनेशनल इकोनॉमिक, डिप्लोमैटिक और सिक्योरिटी पॉलिसी पर काफी असर डालते हैं।

भारत-जी7 संबंधों का विकास

पिछले दो दशकों में G7 के साथ भारत का जुड़ाव लगातार बढ़ा है। यह पार्टनरशिप 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 2005 से 2009 के बीच कई G8 समिट में हिस्सा लिया।

2019 से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 आउटरीच समिट्स में रेगुलर बुलाया जाता रहा है, जो भारत के बढ़ते जियोपॉलिटिकल महत्व को दिखाता है।

जैसे-जैसे उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ने के साथ पारंपरिक G7 अर्थव्यवस्थाओं का ग्लोबल इकोनॉमिक हिस्सा कम हुआ है, भारत एक तेज़ी से महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल पार्टनर बन गया है।

G7 के लिए भारत क्यों महत्वपूर्ण है?

भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी इकॉनमी में से एक बनकर उभरा है और इसके पास एक बड़ा कंज्यूमर मार्केट, बढ़ता हुआ मैन्युफैक्चरिंग बेस और बहुत स्किलड वर्कफोर्स है।

यह क्लाइमेट जस्टिस, डेवलपमेंट फाइनेंस, फूड सिक्योरिटी और ग्लोबल गवर्नंस रिफॉर्म जैसे मुद्दों पर ग्लोबल साउथ की लीडिंग आवाज़ के तौर पर काम करता है।

भारत, क्वाड जैसे इनिशिएटिव के ज़रिए इंडो-पैसिफिक रीजन में भी अहम भूमिका निभाता है और रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी में भी अहम योगदान देता है।

इसकी बढ़ती डिजिटल इकॉनमी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI), यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), रिन्यूएबल एनर्जी लीडरशिप, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और प्रोडक्शन लिंकड इंसेंटिव (PLI) स्कीमों भारत को इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, और सप्लाय चैन डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक आकर्षक पार्टनर बनाती हैं।

भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उसे पश्चिमी देशों और रूस जैसे देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने में भी मदद करती है, जिससे उसकी डिप्लोमैटिक अहमियत बढ़ती है।

भारत के समक्ष चुनौतियाँ

बढ़ते ग्लोबल असर के बावजूद, भारत को कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

पश्चिमी देशों और रूस, दोनों के साथ मज़बूत रिश्ते बनाए रखते हुए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में बैलेंस बनाना एक मुश्किल डिप्लोमैटिक काम है।

डेवलपड इकॉनमी में बढ़ते ट्रेड प्रोटेक्शननिज़्म से इंडिया के एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस पर असर पड़ सकता है।

यूरोप और पश्चिम एशिया में जियोपॉलिटिकल झगड़े भारत की एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रेड रूट और सप्लाय चैन के लिए खतरा बने हुए हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तेज़ी से हो रहे डेवलपमेंट के लिए मज़बूत डेटा प्रोटेक्शन, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और एथिकल गवर्नंस की ज़रूरत है। भारत को अपने क्लाइमेट कमिटमेंट्स को तेज़ी से बढ़ती इकॉनमी की डेवलपमेंट की ज़रूरतों के साथ बैलेंस करना होगा, साथ ही क्लाइमेट जस्टिस और डेवलपड देशों से फाइनेंशियल सपोर्ट की भी वकालत करनी होगी।

G7 की सीमाएँ

हालांकि G7 प्रभावशाली बना हुआ है, लेकिन इसे कई स्ट्रक्चरल सीमाओं का सामना करना पड़ रहा है।

इसकी मेंबरशिप एडवांसड इकॉनमी तक ही सीमित है, जिससे उभरती ताकतों का रिप्रेजेंटेशन कम हो जाता है।

फोरम के पास कानूनी तौर पर फैसले लेने का अधिकार नहीं है।

कई विकासशील देश इसके पश्चिमी-केंद्रित एजेंडे की आलोचना करते हैं।

G7 के पास प्रतिबंध लगाने या जॉइंट घोषणाएं जारी करने के बावजूद बड़े जियोपॉलिटिकल झगड़ों को सुलझाने की सीमित क्षमता है।

भारत और चीन जैसे देशों के आगे बढ़ने के साथ ग्लोबल GDP में इसका हिस्सा धीरे-धीरे कम हुआ है, जिससे G20 जैसे बड़े प्लेटफॉर्म का महत्व बढ़ गया है।

ट्रेड, क्लाइमेट पॉलिसी और चीन के साथ रिश्तों पर सदस्य देशों के बीच मतभेद अक्सर पॉलिसी कोऑर्डिनेशन को कम कर देते हैं।

राष्ट्रीय समाचार**कैबिनेट की मंजूरी**

- कैबिनेट ने दिल्ली-NCR क्लीन मोबिलिटी स्कीम को मंजूरी दी: केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली-NCR इलाके में एयर पॉल्यूशन कम करने के लिए ₹9,585 करोड़ के फाइनेंशियल खर्च वाली दो साल की स्कीम को मंजूरी दी है। इसके तहत पुराने BS-IV और पहले के ट्रकों और बसों को BS-VI या इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EVs) से बदला जाएगा। इस स्कीम को नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड (NCRPB) से फंड किया जाएगा और इसे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय लागू करेंगे। लगभग 2.07 लाख कमर्शियल गाड़ियों को इंटररेस्ट सब्सिडी, फ्यूल वाउचर, टैक्स में छूट, OEM डिस्काउंट और पूरी तरह से डिजिटल इम्प्लीमेंटेशन पोर्टल से फायदा होने की उम्मीद है।

- कैबिनेट ने ₹10,000 करोड़ के ATF प्राइस स्टेबिलाइज़ेशन फंड को मंजूरी दी: सेंट्रल कैबिनेट ने वेस्ट एशिया संकट की वजह से फ्यूल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच शेड्यूलड इंडियन एयरलाइंस के लिए एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों को स्थिर करने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) को ₹10,000 करोड़ तक की एक बार की बजटीय मदद को मंजूरी दी। यह मदद बिना ब्याज के एडवांस के तौर पर दी जाएगी, जिससे ATF की अनुमानित कीमत पक्की होगी, एयरलाइंस को फ्यूल की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी से बचाया जा सकेगा, किराए में उतार-चढ़ाव कम होगा और घरेलू और इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी बनी रहेगी। यह सिस्टम 36 महीने तक चालू रहेगा और इंटरनेशनल फ्यूल की कीमतें नॉर्मल होने पर सालाना रिब्यू और फंड की रिकवरी होगी।

- सिविल एविएशन मिनिस्टर ने ATF सपोर्ट का स्वागत किया: सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने कैबिनेट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ₹10,000 करोड़ का ATF स्टेबिलाइजेशन सिस्टम फ्यूल की लागत में अनिश्चितता को कम करके एयरलाइंस को बड़ी राहत देगा, जबकि यात्रियों को ज्यादा स्टेबल हवाई किराए से फायदा होगा। उन्होंने बताया कि पिछली सरकारी कोशिशों में ECLGS के तहत ₹5,000 करोड़ का सपोर्ट, घरेलू ATF की कीमतों में बढ़ोतरी पर रोक, एयरपोर्ट चार्ज में कमी, और दिल्ली और महाराष्ट्र द्वारा ATF पर कम VAT शामिल थे।
- कैबिनेट ने मध्य प्रदेश में NH-347B हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी: कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) ने हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल (HAM) के तहत मध्य प्रदेश में NH-347B के हिवरखेड़ी - रोशनी - आशापुर - रूढ़ी सेक्शन के अपग्रेडेशन और देशगांव - जुलवानिया सेक्शन को चौड़ा करने को मंजूरी दी। इस पर कुल ₹4,415.60 करोड़ खर्च होंगे। 233.65 km का यह प्रोजेक्ट बैतूल, खंडवा, खरगोन और बड़वानी में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा, भीड़ कम करेगा, सड़क सुरक्षा में सुधार करेगा, कई इकोनॉमिक और लॉजिस्टिक्स हब को जोड़ेगा और 42 लाख से ज्यादा पर्सन-डे रोजगार पैदा करेगा।
- कैबिनेट ने तेलंगाना में NH-63 और NH-563 को चौड़ा करने की मंजूरी दी: CCEA ने तेलंगाना में NH-63 के आर्मूर - जगतियाल - मंचेरियाल सेक्शन और NH-563 के जगतियाल - करीमनगर सेक्शन को चार लेन का चौड़ा करने की मंजूरी दी, जिसमें कुल ₹7,597.16 करोड़ का निवेश होगा। 190.76 km का यह प्रोजेक्ट, HAM और BOT (टोल) मॉडल के तहत पूरा किया जाएगा, इससे यात्रा का समय दो घंटे से ज्यादा कम हो जाएगा, लॉजिस्टिक्स बेहतर होगा, भीड़ कम होगी, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ेगी और 77 लाख से ज्यादा मैन-डे रोजगार पैदा होंगे।
- कैबिनेट ने बिहार में खगड़िया -पूर्णिमा हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी: CCEA ने बिहार में NH-31 और NH-231 के खगड़िया -पूर्णिमा सेक्शन को BOT (टोल) मॉडल के तहत ₹3,936.05 करोड़ की लागत से चार लेन का बनाने को मंजूरी दी। 143.53 km के इस प्रोजेक्ट में 6.73 km का ग्रीनफील्ड पूर्णिमा बाईपास शामिल है, जिसका मकसद यात्रा का समय लगभग दो घंटे कम करना, ज़रूरी इकोनॉमिक और लॉजिस्टिक्स नोड्स से कनेक्टिविटी को मज़बूत करना और 73 लाख से ज्यादा पर्सन-डे रोजगार पैदा करना है।
- कैबिनेट ने ओडिशा कोस्टल हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी: CCEA ने हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल के तहत ओडिशा में रामेश्वर- पारादीप कोस्टल हाईवे के कंस्ट्रक्शन को मंजूरी दी, जिसकी कुल लागत ₹8,300.79 करोड़ होगी। 160.18 km के इस कॉरिडोर में रामेश्वर से कोणार्क तक चार लेन का सेक्शन और कोणार्क से पारादीप तक दो लेन का पक्का शोल्डर सेक्शन शामिल है। इससे पूरे ओडिशा में कनेक्टिविटी बेहतर होगी, यात्रा का समय 2.5 घंटे कम होगा, पोर्ट कनेक्टिविटी मज़बूत होगी और 120 लाख से ज्यादा मैन-डे रोजगार पैदा होंगे।
- कैबिनेट ने अहमदाबाद मेट्रो फेज़ 2A को मंजूरी दी: केंद्रीय कैबिनेट ने अहमदाबाद मेट्रो रेल फेज़ 2A को मंजूरी दी, जिसमें कोटेश्वर रोड को अहमदाबाद एयरपोर्ट से जोड़ने वाले पाँच स्टेशनों वाला 6.032 km का कॉरिडोर शामिल है, जिसकी कुल लागत ₹2,169.04 करोड़ है। पूरा होने के बाद, अहमदाबाद-गांधीनगर मेट्रो नेटवर्क 77.63 km तक बढ़ जाएगा, जिससे एयरपोर्ट कनेक्टिविटी बेहतर होगी, ट्रैफिक जाम कम होगा, टिकाऊ शहरी ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा, और कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन के दौरान लगभग 2,500 नौकरियाँ पैदा होंगी।
- केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रस्ताव पास किया: केंद्रीय कैबिनेट ने 10 जून 2026 को एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताते हुए एक प्रस्ताव पास किया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक चुने गए प्रधानमंत्री बने, उन्होंने लगातार 4,399 दिन ऑफिस में पूरे किए और जवाहरलाल नेहरू का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। प्रस्ताव में NDA सरकार के 12 सालों में उनके नेतृत्व की तारीफ़ की गई, जिसमें गरीबी कम करने, इंफ्रास्ट्रक्चर, राष्ट्रीय सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, स्टार्टअप ग्रोथ, सामाजिक कल्याण, आर्थिक सुधारों और भारत की ग्लोबल स्थिति में उपलब्धियों को बताया गया, साथ ही विकसित भारत 2047 के विज़न को पाने का भरोसा जताया गया।
- कैबिनेट ने अमरावती में GPRA प्रोजेक्ट को मंजूरी दी: CCEA ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में ₹1,234.91 करोड़ की लागत से जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन (GPRA) कैम्पस बनाने को मंजूरी दी। 17 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए मॉडर्न नागरिक सुविधाओं और GRIHA 4-स्टार ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड के साथ 1,504 रेजिडेंशियल यूनिट्स दी जाएंगी। इस प्रोजेक्ट से कंस्ट्रक्शन के दौरान हर साल लगभग 7 लाख मैन-डे और ऑपरेशन के दौरान हर साल 50,000 मैन-डे मिलने की उम्मीद है।
- कैबिनेट ने अमरावती में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स को मंजूरी दी: CCEA ने अमरावती में ₹1,299.08 करोड़ की लागत से सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल पूल ऑफिस अकोमोडेशन (CGGPOA) के कंस्ट्रक्शन को मंजूरी दी। इस ऑफिस कॉम्प्लेक्स में लगभग 8,000 सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों के रहने की जगह होगी, सस्टेनेबल ग्रीन बिल्डिंग फीचर्स के साथ मॉडर्न ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, इंटर-डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बेहतर होगा, और कंस्ट्रक्शन के दौरान लगभग 7 लाख मैन-डेज़ का रोजगार पैदा होगा।
- कैबिनेट ने NIIF में अतिरिक्त ₹30,000 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी: केंद्रीय कैबिनेट ने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) में अतिरिक्त ₹30,000 करोड़ के निवेश कमिटमेंट को मंजूरी दी, जिससे भारत सरकार का कुल कमिटमेंट ₹60,000 करोड़ हो गया। यह निवेश NIIF इंफ्रास्ट्रक्चर फंड II और भविष्य के स्ट्रेटिजिक फंड को सपोर्ट करेगा, जिससे ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स और ई-मोबिलिटी में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही इंस्टीट्यूशनल कैपिटल को आकर्षित करने, पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप को मज़बूत करने, रोजगार पैदा करने और विकसित भारत 2047 विज़न की दिशा में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में तेज़ी आएगी।

राज्यवार जून महीने की महत्वपूर्ण घटनाएँ

आंध्र प्रदेश

- गुंटूर के लैम फार्म में रीजनल हॉर्टिकल्चरल रिसर्च स्टेशन (RHRS) ने मशहूर तेजा और ब्यादगी मिर्च का विकल्प देने के लिए मिर्च की दो नई किस्में— LCA-625 और LCA-643— पेश की हैं। इन किस्मों का मकसद पैदावार, कीड़ों से बचाव, मसालों की प्रोसेसिंग और किसानों की आमदनी को बेहतर बनाना है।
- यूनियन कैबिनेट ने अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज 2A को मंजूरी दे दी है? (आंध्र प्रदेश नहीं - इग्नोर करें)
- केंद्रीय कैबिनेट ने अमरावती में ₹ 1,234.91 करोड़ की लागत से सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन (GPRA) के कंस्ट्रक्शन को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट में 1,504 रेजिडेंशियल यूनिट, ग्रीन बिल्डिंग फीचर्स शामिल होंगे, और कंस्ट्रक्शन के दौरान हर साल लगभग 7 लाख मैन-डेज का रोजगार पैदा होगा।
- यूनियन कैबिनेट ने अमरावती में ₹ 1,299.08 करोड़ की लागत से सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल पूल ऑफिस अकोमोडेशन (CGGPOA) बनाने को भी मंजूरी दी है। इस ऑफिस कॉम्प्लेक्स में लगभग 8,000 सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी रह सकेंगे और यह GRIHA 4-स्टार ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा।

असम

- सरकार ने असम के मूगा सिल्क को सिल्क वैल्यू चेन, एक्सपोर्ट, ब्रांडिंग और GI ऑथेंटिकेशन को मजबूत करके ग्लोबल लज्जरी टेक्सटाइल ब्रांड में बदलने के लिए लगभग ₹ 396-411 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ मिशन सेनेहजोरी लॉन्च किया।
- APEDA ने असम से दुबई तक GI-टैग वाली तेजपुर लीची का पहली बार एक्सपोर्ट किया, जिससे किसानों की इनकम बेहतर हुई और एक्सपोर्ट पर आधारित खेती को बढ़ावा मिला।
- असम सरकार और यूरोपियन यूनियन ने फ्लेवर, फ्रेगरेंस और आयुष सेक्टर में सस्टेनेबल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए गुवाहाटी में ब्लू वैली क्लस्टर लॉन्च किया।
- असम और नागालैंड ने 50:50 रेवेन्यू-शेयरिंग मॉडल का इस्तेमाल करके अपनी साझी सीमा पर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के भंडारों की मिलकर खोज करने के लिए एक तीन-तरफा MoU पर साइन किए।
- कार्बी आंगलॉग हैंडलूम प्रोडक्ट्स, असम बिहू पेपा, असम बांस क्राफ्ट्स और देउरी हैंडलूम प्रोडक्ट्स के लिए GI टैग मिले, जिससे पारंपरिक क्राफ्ट्स और ग्रामीण आजीविका मजबूत हुई।

बिहार

- कैबिनेट ने कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने के लिए BOT (टोल) मॉडल के तहत ₹ 3,936.05 करोड़ के खगड़िया-पूर्णिया NH-31/NH-231 फोर-लेन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी।
- भोजपुर में ₹ 31.21 करोड़ का इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बनाएगा, जिसमें हैचरी, फ्रीड प्लांट, ट्रेनिंग सेंटर और डायग्नोस्टिक लैब होंगे।

दिल्ली

- केंद्रीय कैबिनेट ने प्रदूषण कम करने के लिए पुराने BS-IV और उससे पहले के ट्रकों और बसों को BS-VI या इलेक्ट्रिक गाड़ियों से बदलने के लिए ₹ 9,585 करोड़ की दिल्ली-NCR क्लीन मोबिलिटी स्कीम को मंजूरी दी।
- दिल्ली ने एक पेड़ माँ के नाम कैम्पेन के तहत 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया और 15 लाख पेड़ लगाने और 100 ऑक्सीजन पार्क बनाने की योजना की घोषणा की।
- महिला-केंद्रित पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए नॉर्थ दिल्ली में अपना पहला ऑल-वुमन पुलिस स्टेशन खोला।

गुजरात

- गुजरात इन्फॉर्मेशन कमीशन ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए QR-कोडेड सर्टिफिकेट शुरू करने का निर्देश दिया ताकि फूड सेफ्टी और ट्रांसपेरेंसी बेहतर हो सके।
- ऑपरेशन मिलाप के तहत, गुजरात पुलिस ने डिजिटल इंटेलिजेंस और इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन के जरिए 1,470 लापता लोगों का पता लगाया।
- केंद्रीय कैबिनेट ने अहमदाबाद एयरपोर्ट तक मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ₹ 2,169.04 करोड़ की लागत वाले अहमदाबाद मेट्रो फेज 2A को मंजूरी दी।

हरियाणा

- वर्ल्ड बैंक ने जल संरक्षित हरियाणा प्रोजेक्ट के लिए ₹ 4,000 करोड़ के लोन को मंजूरी दी, जिसका फोकस नहरों को मॉडर्न बनाने, ग्राउंडवाटर रिचार्ज, माइक्रो-इरिगेशन और क्लाइमेट-रेजिलिएंट खेती पर है।

जम्मू और कश्मीर / लद्दाख

- जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम की भविष्यवाणी को बेहतर बनाने के लिए जम्मू में अपने 7वें रीजनल मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया।
- ज़ोजिला टनल मेन टनल के सफल निर्माण के साथ एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिससे कश्मीर और लद्दाख के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो गई है।
- सरकार ने आर्टिकल 371 के तहत लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों पर चर्चा की, जिसमें लोकल गवर्नेंस, ज़मीन के अधिकार और कल्चरल सुरक्षा पर फोकस किया गया।

झारखंड

- भगैया सिल्क, कुचाई सिल्क, मुंडा आभूषण और बांस शिल्प को भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग मिले, जिससे पारंपरिक हस्तशिल्प और ग्रामीण आजीविका मजबूत हुई।

कर्नाटक

- डीके शिवकुमार को बिना किसी सहमति के कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी का नेता चुना गया और बाद में उन्होंने सिद्धारमैया की जगह कर्नाटक के 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली।
- ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026 के अनुसार, AI-नेटिव स्टार्टअप इकोसिस्टम में बेंगलुरु एशिया में दूसरे स्थान पर है।

<p>केरल</p> <ul style="list-style-type: none"> केरल ने HAWK (होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल) लॉन्च किया, जो भारत का पहला ज्यूडिशियरी-इंटीग्रेटेड वाइल्डलाइफ ऑफेंस मैनेजमेंट सिस्टम है। कोच्चिकोड में निपाह वायरस के संदिग्ध मामले के बाद केरल ने निगरानी बढ़ा दी है। केरल ने प्रियदर्शिनी फ्री बस ट्रेवल स्कीम शुरू की है, जिसमें महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को KSRTC बस में फ्री यात्रा की सुविधा दी जाएगी। केरल ने विज्ञान 2031 पेश किया, जिसका मकसद जेंडर-रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस और सेफ्टी इनिशिएटिव के ज़रिए राज्य को भारत का सबसे ज़्यादा महिला-फ्रेंडली बनाना है। <p>मध्य प्रदेश</p> <ul style="list-style-type: none"> कैबिनेट ने ₹ 4,415.60 करोड़ के NH-347B हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, जो 233.65 km लंबा है। मध्य प्रदेश की योजना मानसून सत्र 2026 के दौरान यूनिकॉम सिविल कोड (UCC) बिल पेश करने की है। मांडू के खुरासानी इमली (बाओबाब फल) को GI टैग मिला। <p>महाराष्ट्र</p> <ul style="list-style-type: none"> महाराष्ट्र कैबिनेट ने पुण्यश्लोक को मंजूरी दी अहिल्यादेवी होलकर किसान कर्ज राहत योजना, जिसमें ₹ 2 लाख तक का फसल कर्ज माफ किया जाता है। महाराष्ट्र ने कैंसर की पहचान और इलाज के लिए नागपुर में ₹ 300 करोड़ के हाई-एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। राज्य ने महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति 2026 को भी मंजूरी दी। <p>मेघालय</p> <ul style="list-style-type: none"> वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉजिस्टिक्स, सड़क, पर्यटन और आजीविका पर ध्यान केंद्रित करते हुए ₹ 1,246 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। लाकाडोंग हल्दी को G7 समिट 2026 में दिखाए जाने के बाद इंटरनेशनल पहचान मिली। <p>ओडिशा</p> <ul style="list-style-type: none"> कैबिनेट ने ₹ 8,300.79 करोड़ की रामेश्वर- पारादीप तटीय राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी। सिमिलिपाल टाइगर रिज़र्व में तीन बच्चों के साथ एक मेलेनिस्टिक बाघिन को दुर्लभ रूप से देखा गया। 26 जिलों में 64 जगहों के असली ओडिया नाम वापस कर दिए। ओडिशा ने ₹ 76,611.86 करोड़ के 20 इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी, जिनसे 50,500 से ज़्यादा नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। ओडिशा ने पिछड़े जिलों में इंडस्ट्री को आकर्षित करने के लिए GO-EAST इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और रिवाइज़्ड IPR 2022 लॉन्च की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के पारंपरिक त्योहार राजा परबा के महत्व पर प्रकाश डाला। 	<p>पंजाब</p> <ul style="list-style-type: none"> पंजाब ने VB-G RAM G ग्रामीण रोज़गार योजना 2026 को नोटिफ़ाई किया, जिसमें हर साल 125 दिन के रोज़गार की गारंटी दी गई। <p>राजस्थान</p> <ul style="list-style-type: none"> यूनिकॉम सिविल कोड (UCC) का ड्राफ़्ट बनाने के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यों की एक कमेटी बनाई। <p>सिक्किम</p> <ul style="list-style-type: none"> वन अधिकारियों ने उत्तरी सिक्किम में मिशमी ताकिन के झुंड का पहला वीडियो सबूत रिकॉर्ड किया, जिसमें हिमालय की बायोडायवर्सिटी पर रोशनी डाली गई। <p>तमिलनाडु</p> <ul style="list-style-type: none"> तमिलनाडु ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगपुन स्पेशल टास्क फोर्स शुरू की, जो पूरी तरह से महिलाओं वाली पुलिस यूनिट है। क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में तेज़ी लाने के लिए पांच रिन्यूएबल एनर्जी ज़ोन बनाने को मंजूरी दी। <p>तेलंगाना</p> <ul style="list-style-type: none"> कैबिनेट ने ₹ 7,597.16 करोड़ के NH-63 और NH-563 फोर-लेन हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, जिससे निज़ामाबाद, जगतियाल, मंचेरियल और करीमनगर में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। <p>त्रिपुरा</p> <ul style="list-style-type: none"> त्रिपुरा सरिंडा, एक पारंपरिक झुका हुआ संगीत वाद्ययंत्र, को भौगोलिक संकेत (GI) टैग मिला। <p>उत्तर प्रदेश</p> <ul style="list-style-type: none"> लखनऊ में एक नए रीजनल मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश ने प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च किया, जिसका लक्ष्य 20 लाख ग्रामीण परिवारों को हाई-स्पीड इंटरनेट देना है। इन्वेस्ट इंडिया और इन्वेस्ट UP ने FDI को बढ़ावा देने के लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना लागू है, जिसके तहत योग्य लड़कियों को जन्म से लेकर हायर एजुकेशन तक ₹ 25,000 दिए जाते हैं। <p>पश्चिम बंगाल</p> <ul style="list-style-type: none"> पश्चिम बंगाल नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) अपनाने वाला 33वां विधानमंडल बन गया। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत PM-JAY लागू करने वाला 36वां राज्य/UT बन गया। राज्य ने ₹ 4.38 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ पश्चिम बंगाल बजट 2026-27 पेश किया। सरकार ने पांच नए जिले बनाने का प्रस्ताव रखा : कोलकाता, बशीरहाट, सुंदरबन, जंगीपुर और आरामबाग।
--	--

जून महीने के लॉन्च और उद्घाटन:

- सरकार ने समाधान दीदी लॉन्च की: भारत सरकार ने समाधान दीदी लॉन्च की, जो CPGRAMS शिकायत पोर्टल के साथ इंटीग्रेटेड AI-पावर्ड मल्टीलिंगुअल वॉइस चैटबॉट है। भाषानी के साथ डेवलप किया गया, यह नागरिकों को 22 संवैधानिक भाषाओं में शिकायत दर्ज करने में मदद करता है, ऑटोमैटिक रूप से संबंधित डिपार्टमेंट की पहचान करता है, और ट्रांसपेरेंसी, एक्सेसिबिलिटी और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ाता है।
- सरकार ने खेत बचाओ अभियान शुरू किया: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिट्टी बचाने, खाद का सही इस्तेमाल, पानी का सही मैनेजमेंट और मौसम के हिसाब से खेती के तरीकों से टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए खेत बचाओ अभियान शुरू किया। यह अभियान सांडल हेल्थ कार्ड, किसानों को ट्रेनिंग देने और नकली खाद और कीटनाशकों के खिलाफ जागरूकता फैलाने को भी बढ़ावा देता है।
- चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इंडियाAI डेटा लैब लॉन्च की: चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इंटरनेट इंडिया के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और नई टेक्नोलॉजी में हैंड्स-ऑन ट्रेनिंग देने के लिए भारत की पहली प्राइवेट इंडियाAI डेटा लैब लॉन्च की। इस पहल का मकसद एकेडेमिया और इंडस्ट्री के बीच के गैप को कम करना और साथ ही स्किलड AI प्रोफेशनल्स को डेवलप करना है।
- MSDE ने नवाचार मंत्र लॉन्च किया: स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री (MSDE) ने IIT दिल्ली में नवाचार मंत्र लॉन्च किया। इसका मकसद मेंटरशिप, इन्वेस्टर एक्सेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सपोर्ट और मार्केट लिंकेज के जरिए ग्रामीण इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना है। यह प्रोग्राम मुख्य रूप से टियर-2, टियर-3 शहरों और एस्पिरेशनल जिलों के एंटरप्रेन्योर्स को टारगेट करता है।
- भारत ने पहला मॉडल बॉर्डर विलेज बनाया: भारत ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत लद्दाख के चुमुर में अपना पहला मॉडल बॉर्डर विलेज बनाया। यह प्रोजेक्ट क्लाइमेट-रेजिलिएंट हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टूरिज्म को बढ़ावा देने, रोज़ी-रोटी कमाने और दूर-दराज के हिमालयी इलाकों में बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत करने पर फोकस करता है।
- सरकार ने फोटू ला टनल प्रोजेक्ट शुरू किया: सरकार ने श्रीनगर-कारगिल-लेह हाईवे पर ₹824 करोड़ के फोटू ला टनल प्रोजेक्ट के लिए बोली शुरू की। ये दोनों टनल लद्दाख को हर मौसम में कनेक्टिविटी देंगी, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाएंगी, टूरिज्म को बढ़ावा देंगी और भारी बर्फबारी से होने वाली यात्रा में रुकावटों को कम करेंगी।
- दमन में NAMO एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में नए NAMO एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया, साथ ही लगभग ₹2,970 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन किया। इस मॉडर्न टर्मिनल से रीजनल एयर कनेक्टिविटी, टूरिज्म, ट्रेड और पैसेंजर की सुविधा में सुधार होने की उम्मीद है।
- नेशनल जूलॉजिकल पार्क ने NZP साथी ऐप लॉन्च किया: नेशनल जूलॉजिकल पार्क, नई दिल्ली ने डिजिटल टिकटिंग, स्मार्ट नेविगेशन और इंटरैक्टिव एजुकेशनल कंटेंट के जरिए विज़िटर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए NZP साथी ऐप, सेल्फ-टिकटिंग कियोस्क, UPI-इनेबल्ड पेमेंट सुविधाएँ और फ्री वाई-फ़ाई लॉन्च किया।

- सरकार ने लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (LPMS) लॉन्च किया: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के लैंड पोर्ट्स पर ऑपरेशन्स को डिजिटलाइज़ करने के लिए लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (LPMS) लॉन्च किया। यह प्लेटफॉर्म ऑनलाइन स्टांट बुकिंग, डिजिटल पेमेंट्स, कार्गो ट्रैकिंग और सिंगल-विंडो क्लीयरेंस देता है ताकि क्रॉस-बॉर्डर ट्रेड और पैसेंजर मूवमेंट को बेहतर बनाया जा सके।
- ICAR ने ऑयलसीड्स किसान मित्र लॉन्च किया: इंडियन काउंसिल ऑफ़ एग्रीकल्चरल रिसर्च (ICAR) ने ऑयलसीड्स किसान मित्र लॉन्च किया है, जो ऑयलसीड किसानों के लिए भारत का पहला WhatsApp-बेस्ड AI एडवाइज़री प्लेटफॉर्म है। यह फसल उगाने, पेस्ट मैनेजमेंट, सिंचाई, कटाई के बाद के तरीकों और बीज की उपलब्धता पर मुफ्त, कई भाषाओं में गाइडेंस देता है।
- डाक विभाग ने ड्रोन मेल सर्विस शुरू की: डाक विभाग ने हिमाचल प्रदेश में मंडी और रेहरधार के बीच ड्रोन-बेस्ड मेल डिलीवरी सर्विस शुरू की, जिससे डिलीवरी का समय दो घंटे से घटकर सिर्फ सात मिनट रह गया और दूर-दराज के पहाड़ी इलाकों में कनेक्टिविटी बेहतर हुई।
- आयुष मंत्रालय ने योग पार्क पोर्टल लॉन्च किया: आयुष मंत्रालय ने इंटरनेशनल योग दिवस 2026 से पहले योग, मेडिटेशन, प्रिवेंटिव हेल्थकेयर और पब्लिक पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देकर पब्लिक पार्कों को कम्युनिटी वेलनेस सेंटर में बदलने के लिए योग पार्क पोर्टल लॉन्च किया।
- सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन पोर्टल लॉन्च किया: राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत, सरकार ने नवाचार और स्वच्छ ऊर्जा विकास का समर्थन करते हुए ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में पारदर्शिता और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन पोर्टल लॉन्च किया।
- सरकार ने आधार ऐप लॉन्च किया: यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (UIDAI) ने अपग्रेडेड आधार ऐप लॉन्च किया, जिसमें फेस ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक लॉक/अनलॉक, QR-बेस्ड आधार शेयरिंग, ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री और सिक्योर डिजिटल आइडेंटिटी मैनेजमेंट जैसे फीचर हैं।
- सरकार ने NAFEX.in और डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल तकनीकों के माध्यम से कृषि मार्केटिंग, खरीद, लॉजिस्टिक्स और गवर्नेंस को आधुनिक बनाने के लिए NAFEX.in, NAFED-कल्याण स्कॉलरशिप स्कीम, DRISHTI पोर्टल और एक ERP पोर्टल लॉन्च किया।
- सरकार ने डिजिटल पुलिसिंग एप्लिकेशन लॉन्च किए: सरकार ने एकीकृत आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) को मजबूत करने, जांच में सुधार करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए चार उन्नत डिजिटल पुलिसिंग प्लेटफॉर्म- अभिज्ञान, सीआरपीआई, ई-प्रॉसिक्यूशन 2.0 और ई-फोरेंसिक 2.0 लॉन्च किए।
- सरकार ने एयर सुविधा 2.0 लॉन्च किया: नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए हवाई अड्डे की जांच, रोग निगरानी और संपर्क रहित यात्रा को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से डिजिटल स्वास्थ्य घोषणा प्रणाली एयर सुविधा 2.0 लॉन्च की।

- **मंत्रालय ने शतायु डैशबोर्ड लॉन्च किया:** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने शतायु डैशबोर्ड लॉन्च किया, जो पूरे भारत में बुजुर्गों की देखभाल सेवाओं में सुधार के लिए वरिष्ठ नागरिकों को प्रमाणित जेरियाट्रिक देखभालकर्ताओं से जोड़ने वाला एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है।
- **सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल पर विज्ञान डॉक्यूमेंट (2026-2029) लॉन्च किया:** केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ड्रग-फ्री भारत बनाने के लिए एंटी-ड्रग एनफोर्समेंट, रिहैबिलिटेशन, अवेयरनेस कैंपेन और इंटर-एजेंसी कोऑर्डिनेशन को मजबूत करने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल (2026-2029) पर विज्ञान डॉक्यूमेंट लॉन्च किया।

विविध राष्ट्रीय समाचार

- कसौली के जंगल की आग पर काबू पाने के लिए बांबी बकेट से लैस Mi-17V-5 हेलीकॉप्टर तैनात किए: इंडियन एयर फ़ोर्स ने हिमाचल प्रदेश के कसौली के जंगल की आग पर काबू पाने के लिए बांबी बकेट से लैस Mi-17V-5 हेलीकॉप्टर तैनात किए। हेलीकॉप्टरों ने 150 से ज्यादा उड़ानें भरीं, और आग पर काबू पाने के लिए 62,500 लीटर से ज्यादा पानी गिराया। इस ऑपरेशन ने मुश्किल पहाड़ी इलाकों में जंगल की आग से निपटने में एरियल फायरफाइटिंग टेक्नोलॉजी के महत्व को दिखाया।
- अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया : सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को पश्चिमी घाट में अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व से गैर-कानूनी अतिक्रमण और बिना इजाजत के बने स्ट्रक्चर हटाने का निर्देश दिया। इस आदेश का मकसद खराब जंगल की जमीन को ठीक करना, बायोडायवर्सिटी को बचाना और भारत के इकोलॉजिकली सेंसिटिव इलाकों में से एक की रक्षा करना है।
- भाविता मांडवा का नाम फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया में: हैदराबाद में जन्मी मांडवा भाविता मांडवा को फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया 2026 लिस्ट में राइजिंग टैलेंट्स कैटेगरी में शामिल किया गया। वह चैनल के मेटियर्स को खोलने वाली पहली भारतीय मॉडल बनीं। डी'आर्ट शो में काम किया और बाद में उन्हें चैनल का इंडियन ब्रांड एंबेसडर बनाया गया, जिससे ग्लोबल फैशन इंडस्ट्री में इंडिया की प्रेजेंस और बढ़ी।
- भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोलर ग्रोथ मार्केट बना: भारत 2025 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोलर ग्रोथ मार्केट बन गया, जब उसने सालाना सोलर कैपेसिटी बढ़ाने में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। देश ने 155 GW की इस्टॉलड सोलर कैपेसिटी पार कर ली है, जिसे PM सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना जैसी पहलों का सपोर्ट मिला है, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में भारत की लीडरशिप और मजबूत हुई है।
- भारत को मिला 100वां रामसर साइट: उत्तर प्रदेश में जय प्रकाश नारायण बर्ड सैंक्चुरी (सुरहा ताल) को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2026 पर भारत का 100वां रामसर साइट घोषित किया गया। यह पहचान वेटलैंड कंजर्वेशन, बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल इकोसिस्टम मैनेजमेंट के लिए भारत के कमिटमेंट को दिखाती है।

- APEDA ने बोटैनिकल मिलेट फंक्शनल फूड्स के पहले एक्सपोर्ट को आसान बनाया: एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी (APEDA) ने कर्नाटक से न्यूज़ीलैंड को बोटैनिकल मिलेट फंक्शनल फूड्स के भारत के पहले एक्सपोर्ट को आसान बनाया। यह माइलस्टोन वैल्यू-एडेड मिलेट प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देता है, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट को मजबूत करता है, और किसानों की इनकम बढ़ाता है।
- FSSAI ने ऑफिशियल वीगन लोगो पेश किया: फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने कस्टमर्स को सर्टिफाइड वीगन प्रोडक्ट्स पहचानने में मदद करने के लिए भारत का ऑफिशियल वीगन लोगो पेश किया। यह लोगो 1 जुलाई 2027 से ज़रूरी हो जाएगा, जिससे फूड लेबलिंग ट्रांसपेरेंसी में सुधार होगा और प्लांट-बेस्ड फूड चॉइस को बढ़ावा मिलेगा।
- हम्पी में ऐतिहासिक मंडप को ठीक किया : आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) ने हम्पी में ऐतिहासिक विरुपाक्ष मंदिर मंडप को बाद में हुए कंस्ट्रक्शन को हटाकर और उसके ओरिजिनल आर्किटेक्चरल डिज़ाइन को ठीक करके ठीक किया। इस रेस्टोरेशन से हेरिटेज कंजर्वेशन में सुधार होगा और UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट के कल्चरल और हिस्टोरिकल महत्व को भी बनाए रखा जाएगा।
- भारत ने E85 फ्यूल लाने की घोषणा की: सरकार ने क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने और इम्पोर्टेड कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने के लिए E85 फ्यूल लाने की घोषणा की, जिसमें 85% इथेनॉल और 15% पेट्रोल है। इस पहल से कार्बन एमिशन कम होने, भारत की बायोफ्यूल इकॉनमी मजबूत होने और ज्यादा इथेनॉल प्रोडक्शन से किसानों की इनकम बढ़ने की उम्मीद है।
- आकाशवाणी ने 90 साल पूरे किए: भारत के पब्लिक ब्रॉडकास्टर आकाशवाणी (ऑल इंडिया रेडियो) ने ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के 90 साल पूरे कर लिए हैं। प्रसार भारती के तहत काम करते हुए, आकाशवाणी दुनिया के सबसे बड़े रेडियो ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क में से एक बना हुआ है, जो न्यूज़ फैलाने, शिक्षा और कल्चरल बचाव में अहम भूमिका निभा रहा है।
- NFHS-6 में सबसे कम फर्टिलिटी रेट पर रोशनी डाली गई: नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS-6) के मुताबिक, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में भारत का सबसे कम टोटल फर्टिलिटी रेट (0.9) दर्ज किया गया। नतीजों से बदलते डेमोग्राफिक ट्रेंड्स का पता चलता है, जिसमें जन्म दर में कमी और बढ़ती उम्र की आवादी शामिल है।
- भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बना: भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन गया है, जिसकी वजह तेज़ी से एयरपोर्ट का विस्तार, पैसेंजर ट्रैफिक में बढ़ोतरी और UDAN जैसी रीजनल कनेक्टिविटी की पहल है। यह मील का पत्थर देश के बढ़ते एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक विकास को दिखाता है।
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के 11 साल पूरे: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) प्रोग्राम को लागू हुए 11 साल पूरे हो गए हैं। 2015 में शुरू होने के बाद से, इस स्कीम ने बच्चों के लिंग अनुपात, लड़कियों की शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और जेंडर भेदभाव के खिलाफ जागरूकता में सुधार लाने में मदद की है।

- भारत ने टनल हुड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया: भारत ने एयर प्रेशर वेक्स को कम करने, नॉइज़ पॉल्यूशन को कम करने, पैसेंजर कम्फर्ट को बेहतर बनाने और हाई-स्पीड रेल ऑपरेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर टनल हुड टेक्नोलॉजी शुरू की।
- इंडियन रेलवे ने कवच 4.0 को बढ़ाया: इंडियन रेलवे ने अपने स्वदेशी ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (ATP) सिस्टम, कवच 4.0 को तेजी से लागू किया है। यह टेक्नोलॉजी ट्रेन की टक्कर, ओवरस्पीडिंग और खतरे में सिग्नल पास करने की घटनाओं को रोकने के लिए डिज़ाइन की गई है, जिससे रेलवे सुरक्षा में काफ़ी सुधार हुआ है।
- भारत ने 2035 तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखा है: भारत ने 2035 तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य घोषित किया है, जिसमें 2030 तक 100 गीगावाट का मध्यवर्ती लक्ष्य शामिल है। यह पहल भारत की अक्षय ऊर्जा बदलाव, ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु प्रतिबद्धताओं का समर्थन करती है।
- सरकार ने कुछ समय के लिए टेलीग्राम पर रोक लगाई: सरकार ने NEET UG 2026 री-एग्जाम से पहले टेलीग्राम के एक्सेस पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी है ताकि नकली क्वेश्चन पेपर, आंसर की और गुमराह करने वाले कंटेंट के सर्कुलेशन को रोका जा सके, जिससे एग्जाम की ईमानदारी बनी रहे।
- सुप्रीम कोर्ट ने पैदल चलने के अधिकार को बुनियादी अधिकार बताया: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सुरक्षित और बिना कब्ज़ा वाले फुटपाथ पर चलने का अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 के तहत सुरक्षित है। कोर्ट ने अधिकारियों को पैदल चलने वालों के लिए सही शहरी प्लानिंग को प्राथमिकता देने और सुरक्षित पब्लिक वॉकवे बनाए रखने का निर्देश दिया।
- भारत दुनिया का सबसे बड़ा शिप रीसाइक्लिंग देश बना: भारत 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा शिप रीसाइक्लिंग देश बन गया, जिसने

मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 का टारगेट समय से पहले हासिल कर लिया। यह कामयाबी मॉडर्न रीसाइक्लिंग सुविधाओं और सस्टेनेबल मैरीटाइम पॉलिसी की सफलता को दिखाती है।

- भारत ने इंडियन फार्माकोपिया 2026 जारी किया: भारत ने इंडियन फार्माकोपिया 2026 जारी किया, जिससे वह खून और खून के हिस्सों के लिए खास क्वालिटी स्टैंडर्ड तय करने वाला पहला देश बन गया। नए स्टैंडर्ड का मकसद ट्रांसफ्यूजन सेफ्टी, क्वालिटी कंट्रोल और हेल्थकेयर नतीजों को बेहतर बनाना है।
- भारत ने सात नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की घोषणा की: सरकार ने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) के तहत सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की, जिससे कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास में सुधार के लिए भारत के बुलेट ट्रेन नेटवर्क को मुंबई-अहमदाबाद रूट से आगे बढ़ाया जाएगा।
- भारत ने भू-आधार (ULPIN) लॉन्च किया: भारत ने 36 करोड़ से ज़्यादा ज़मीन के टुकड़ों को यूनिक डिजिटल पहचान देकर भू-आधार (यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर - ULPIN) को बढ़ाया। यह पहल ज़मीन के रिकॉर्ड को मॉडर्न बनाती है, झगड़े कम करती है, और ज़मीन के मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाती है।
- भारत ने 5 लाख से ज़्यादा अंगदान के वादे पूरे किए: भारत ने 5 लाख से ज़्यादा अपनी मर्जी से अंगदान के वादे पूरे किए, जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के ज़रिए लोगों में बढ़ती जागरूकता और बेहतर डिजिटल रजिस्ट्रेशन को दिखाता है। यह उपलब्धि सही तरीके से अंग ट्रांसप्लांट और बेहतर हेल्थकेयर एक्सेस को सपोर्ट करती है।
- भारत QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में 13वें स्थान पर: भारत ने QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में वैश्विक स्तर पर 13वां स्थान हासिल किया, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल प्रौद्योगिकियों, नवाचार, स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्रों और भविष्य की कार्यबल तत्परता में इसकी बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है।

सरकारी योजनाएँ

पीएम स्वनिधि योजना के छह साल पूरे:

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) स्कीम को जून 2020 में लॉन्च हुए छह साल पूरे हो गए हैं। यह स्कीम शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी गारंटी के वर्किंग कैपिटल लोन देती है ताकि वे अपना बिज़नेस फिर से शुरू कर सकें और उसे बढ़ा सकें। पिछले छह सालों में, इससे 75.5 लाख से ज़्यादा वेंडर्स को फ़ायदा हुआ है, 1.12 करोड़ से ज़्यादा लोन मंज़ूर किए गए हैं, और ₹17,800 करोड़ से ज़्यादा दिए गए हैं। इसने 55 लाख से ज़्यादा वेंडर्स को डिजिटली जोड़ा है और उन्हें फ़ाइनेंशियल सर्विस, डिजिटल पेमेंट और कई वेलफ़ेयर स्कीम तक पहुँच आसान बनाई है। 34.81 लाख से ज़्यादा महिला वेंडर्स को फ़ायदा हुआ है, जिससे यह स्कीम फ़ाइनेंशियल इनक्लूजन और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में अहम योगदान दे रही है।

पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत PM-JAY में शामिल हुआ:

नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) के साथ एग्रीमेंट साइन करने के बाद, पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) लागू

करने वाला 36वां राज्य/केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। यह स्कीम सेकेंडरी और टर्शियरी हॉस्पिटलाइज़ेशन के लिए हर परिवार को सालाना ₹5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज देती है। यह पूरे भारत में पैनाल वाले अस्पतालों में कैथलेस इलाज की सुविधा देती है और इसका मकसद अच्छी मेडिकल केयर तक पहुंच बढ़ाते हुए जेब से होने वाले हेल्थकेयर खर्च को कम करना है।

PMSMA के 10 साल पूरे:

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) को 9 जून 2016 को लॉन्च हुए 10 साल पूरे हो गए। यह प्रोग्राम हर महीने की 9 तारीख को सरकारी हेल्थ सेंटर पर प्रेग्नेट महिलाओं को फ्री में पूरी एंटीनेटल केयर देता है। इस स्कीम के तहत 7.5 करोड़ से ज़्यादा प्रेग्नेट महिलाओं को फायदा हुआ है। इसने हाई-रिस्क प्रेग्नेसी को शुरुआती स्टेज में पहचानने में अहम भूमिका निभाई है और भारत के मैटरनल मॉर्टैलिटी रेशियो (MMR) को 130 (2014-16) से घटाकर 87 (2022-24) करने में मदद की है।

सरकार ने CGSMFI-2.0 को बढ़ाया:

सरकार ने माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम-2.0 (CGSMFI-2.0) को 31 अगस्त 2026 तक बढ़ा दिया है और बड़ी NBFC-MFIs और MFIs के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एलिजिबल लोन अमाउंट को ₹300 करोड़ से बढ़ाकर ₹1,000 करोड़ कर दिया है। यह स्कीम नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) के ज़रिए सरकार के सपोर्ट वाली क्रेडिट गारंटी देती है, जिससे बैंक माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशन को लोन देने में बढ़ोतरी करते हैं और कम इनकम वाले बॉरोअर्स और महिला एंटरप्रेन्योर्स के लिए सस्ते क्रेडिट तक पहुंच बेहतर होती है।

राजोलीबांदा डायवर्सन योजना:

राजोलीबांदा डायवर्सन स्कीम (RDS) एक इंटरस्टेट सिंचाई प्रोजेक्ट है जो कृष्णा नदी की एक बड़ी सहायक नदी तुंगभद्रा नदी पर बना है। यह तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को सिंचाई का पानी सप्लाई करता है, जिससे सूखे वाले इलाकों में खेती को मदद मिलती है। हाल ही में, यह स्कीम लंबे समय से चल रहे तुंगभद्रा नदी के पानी के बंटवारे के विवाद और पानी के इस्तेमाल, जलाशय की क्षमता और इंटरस्टेट तालमेल को बेहतर बनाने के प्रस्तावों पर चर्चा के कारण चर्चा में आई।

मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना:

मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना (MKSYS) शुरू की थी। यह उन किसानों को बिना किसी इश्योरेंस प्रीमियम के फाइनेंशियल मदद देती है जिनकी खरीफ फसलें कुदरती आपत्तों की वजह से खराब हो जाती हैं। किसानों को 33% से 60% के बीच फसल के नुकसान पर ₹20,000 प्रति हेक्टेयर और 60% से ज़्यादा नुकसान पर ₹25,000 प्रति हेक्टेयर मिलते हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा चार हेक्टेयर का कवरेज शामिल है। इस स्कीम के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के ज़रिए करीब 50 लाख किसानों को फायदा हुआ है।

सरकार ने एयर सुविधा 2.0 लॉन्च किया:

सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) के साथ मिलकर इंटरनेशनल यात्रियों के लिए पूरी तरह से डिजिटल और कॉन्टैक्टलेस हेल्थ डिक्लरेशन प्लेटफॉर्म एयर सुविधा 2.0 लॉन्च किया है। यह अपग्रेडेड सिस्टम यात्रियों को भारत आने से पहले ऑनलाइन हेल्थ जानकारी जमा करने में मदद करता है, जिससे एयरपोर्ट हेल्थ सर्विलांस मजबूत होता है और बीमारी की स्क्रीनिंग, इमिग्रेशन क्लियरेंस और हेल्थ अधिकारियों के बीच कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है।

यूपी बेरोजगारी भत्ता योजना 2026:

UP बेरोजगारी भत्ता योजना, जिसे UP रोजगार संगम योजना के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश सरकार की एक रोजगार सहायता पहल है। यह योजना योग्य शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने तक हर महीने ₹1,000 से ₹1,500 का बेरोजगारी भत्ता देती है। सेवायोजन UP पोर्टल के ज़रिए, लाभार्थियों को जाँच फेयर, रोजगार नोटिफिकेशन, करियर काउंसलिंग और प्लेसमेंट सहायता भी मिलती है।

सरकार ने PM फैमिली केयर ट्रैकर लॉन्च किया:

सरकार ने गुजरात के गांधीनगर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर PM फैमिली केयर ट्रैकर (PM-FCT) लॉन्च किया है। इसका मकसद प्रेग्नंसी से लेकर 18 साल की उम्र तक मां और बच्चे की सेहत पर डिजिटल तरीके से नज़र रखना है। यह प्लेटफॉर्म हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन और वेलफेयर बेनिफिट्स को ट्रैक करने के लिए बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर या ABHA IDs का इस्तेमाल करता है, साथ ही करीब 18 सरकारी स्कीम्स को एक साथ जोड़ता है। यह छूटी हुई सर्विसेज़ के लिए रियल-टाइम अलर्ट देता है और बेनिफिट्स समय पर मिलना पक्का करता है।

सरकार ने PM रिसर्च चेंजर स्कीम 2026 लॉन्च की:

सरकार ने दुनिया भर से भारतीय मूल के रिसर्चर्स, साइंटिस्ट्स, टेक्नोलॉजिस्ट्स और इनोवेटर्स को आकर्षित करने के लिए प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेंजर (PMRC) स्कीम 2026 लॉन्च की है। यह स्कीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, बायोटेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस, स्पेस और क्लाइमेट चेंज जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर पर फोकस करती है। यह यंग रिसर्च फेलो, सीनियर फेलो और रिसर्च चेंजर कैटेगरी ऑफर करती है और इसे IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT हैदराबाद, IIT (ISM) धनबाद और IISc बेंगलुरु जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन के ज़रिए लागू किया जाएगा।

कैबिनेट ने दिल्ली-एनसीआर क्लीन मोबिलिटी स्कीम को मंजूरी दी:

केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली-NCR इलाके में एयर पॉल्यूशन कम करने के लिए ₹9,585 करोड़ की स्कीम को मंजूरी दी है। इसके तहत BS-IV और पुरानी कमर्शियल गाड़ियों को BS-VI या इलेक्ट्रिक गाड़ियों से बदलने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। इस स्कीम से करीब 2.07 लाख ट्रक और बस मालिकों को इंटरस्ट सब्सिडी, टैक्स में छूट, फ्यूल वाउचर, खरीद पर डिस्काउंट और डिजिटल मॉनिटरिंग से फायदा होगा। इससे ट्रांसपोर्ट से जुड़े एमिशन को कम करने और इलाके की एयर क्वालिटी को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

सरकार ने VB-G RAM G योजना शुरू की:

सरकार ने VB-G RAM G स्कीम (विकसित भारत - रोजगार और आजीविका मिशन - ग्रामीण के लिए गारंटी) के लिए ₹95,692.31 करोड़ के अंतरिम आवंटन की घोषणा की है, जिसे 1 जुलाई 2026 को लॉन्च किया जाना है। यह प्रोग्राम टिकाऊ संपत्ति बनाने, पानी की सुरक्षा, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका बनाने, क्लाइमेट-रेसिलिएंट डेवलपमेंट और तेज़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) पेमेंट पर ध्यान देते हुए सालाना 125 दिनों तक की मज़दूरी वाली नौकरी की गारंटी देता है।

राहवीर स्कीम के लिए MoRTH के साथ पार्टनरशिप की:

राहवीर स्कीम को प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ़ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ (MoRTH) के साथ पार्टनरशिप की। यह स्कीम लोगों को ज़रूरी गोल्डन आवर के दौरान सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों की मदद करने के लिए बढ़ावा देती है। इस कैम्पेन के तहत, 4 लाख से ज़्यादा रैपिडो कैप्टन ने सड़क सुरक्षा की शपथ ली, जिससे गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। इस पहल का मकसद इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम को बेहतर बनाना, सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और भारत के पूरे सड़क सुरक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करना है।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

- **वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) ने वर्ल्ड नो टोबैको डे 2026 अवाार्ड्स की घोषणा की**, जिसमें दुनिया भर में टोबैको कंट्रोल और पब्लिक हेल्थ में शानदार योगदान को मान्यता दी गई। अवाार्ड पाने वालों में WHO के सभी छह रीजन के लोग, रिसर्चर, सरकारी एजेंसियां और ऑर्गनाइजेशन शामिल थे। **WHO डायरेक्टर-जनरल स्पेशल अवाार्ड यमन की डॉ. शायी मोहसिन जिंदानी को दिया गया।** भारत को राजस्थान के हेल्थ डिपार्टमेंट और **ICMR-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च** के ज़रिए टोबैको अवेयरनेस, रोकथाम की कोशिशों और टोबैको कंजम्पशन कम करने और पब्लिक हेल्थ के नतीजों के लिए मान्यता मिली।
- **भारत ने अफ्रीका सेंटर्स फॉर डिज़ीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के ज़रिए ज़रूरी हेल्थकेयर मटीरियल सप्लाई करके इबोला आउटब्रेक से प्रभावित अफ्रीकी देशों को इमरजेंसी मेडिकल मदद दी है।** इस मदद में डायग्नोस्टिक किट, दवाइयां, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इन्फेक्शन-कंट्रोल सप्लाई और केस-मैनेजमेंट मटीरियल शामिल हैं। इस मदद का मकसद प्रभावित समुदायों, खासकर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ कांगो में हेल्थकेयर रिस्पॉन्स को मज़बूत करना है। यह पहल ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी, मानवीय मदद और साउथ-साउथ कोऑपरेशन के लिए भारत के कमिटमेंट को दिखाती है, साथ ही पब्लिक हेल्थ और इमरजेंसी रिस्पॉन्स की कोशिशों में अफ्रीकी देशों के साथ लंबे समय से चली आ रही पार्टनरशिप को मज़बूत करती है।
- **फोर्ब्स 2026 रैंकिंग में एलन मस्क \$835 बिलियन के साथ दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं**, उनके बाद लैरी पेज, सर्गेई ब्रिन, जेफ बेजोस और लैरी एलिसन हैं। टॉप 10 में माइकल डेल, मार्क जुकरबर्ग, जेन्सेन हुआंग, बर्नार्ड अर्नाल्ट और स्टीव बाल्मर भी शामिल हैं। यह लिस्ट टेक्नोलॉजी सेक्टर, खासकर टेस्ला, स्पेसएक्स, अल्फाबेट, अमेज़न, ओरेकल और मेटा जैसी कंपनियों के लगातार दबदबे को दिखाती है। **AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल इनोवेशन में तेज़ी से हुई बढ़ोतरी ने ग्लोबल वेल्थ क्रिएशन पर काफी असर डाला है।** यह रैंकिंग दिखाती है कि कैसे टेक-ड्रिवन एंटरप्राइज़ ग्लोबल फाइनेंशियल पावर और दुनिया भर में अल्ट्रा-हाई-नेट-वर्थ इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन को आकार दे रहे हैं।
- **वेनेज़ुएला के एक्टिंग प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हाई-लेवल बातचीत के लिए 3-7 जून 2026 तक भारत आएंगे।** बातचीत एनर्जी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थकेयर, ट्रांसपोर्टेशन और रिन्यूएबल एनर्जी में सहयोग को मज़बूत करने पर फोकस करेगी। यह दौरा भारत-वेनेज़ुएला के गहरे होते रिश्तों को दिखाता है, खासकर वेनेज़ुएला से बढ़ते कच्चे तेल के इंपोर्ट के मामले में। सीनियर मंत्रियों के साथ, इस दौरे का मकसद साउथ-साउथ सहयोग को बढ़ाना और भारत की एनर्जी पार्टनरशिप में विविधता लाना है। यह दोनों देशों के बीच आपसी जुड़ाव को मज़बूत करने और स्ट्रेटिजिक इकोनॉमिक सहयोग को बढ़ाने की कोशिशों पर ज़ोर देता है।
- **बांग्लादेश के खलीलुर रहमान को 81वें UN जनरल असेंबली सेशन का प्रेसिडेंट चुना गया है**, उन्होंने साइप्रस के कैंडिडेट एंड्रियास काकोरिस को हराया है। वह सितंबर 2026 में एक साल के लिए ऑफिस संभालेंगे। उनकी प्रायोरिटीज़ में शांति और सुरक्षा, SDGs, क्लाइमेट एक्शन, ह्यूमन राइट्स, नई टेक्नोलॉजी और UN रिफॉर्म शामिल हैं। सेशन की थीम है "भरोसा फिर से बनाना, ट्रांसफॉर्मेशन को मैनेज करना।" उनका चुनाव ग्लोबल गवर्नेंस के लिए एक अहम समय पर हुआ है, जो मल्टीलेटरल कोऑपरेशन, UN रिफॉर्म और ग्लोबल डेवलपमेंट चैलेंजेस पर बढ़ते फोकस को दिखाता है।
- **यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने UN सिक्योरिटी काउंसिल के पांच नए नॉन-परमानेंट मेंबर (2027-2028 टर्म) चुने : ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पुर्तगाल, त्रिनिदाद और टोबैगो, और जिम्बाब्वे।** उनका टर्म 1 जनवरी 2027 से शुरू होगा। खास बात यह है कि किर्गिस्तान ने अपनी पहली UNSC सीट हासिल की, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह चुनाव बदलते ग्लोबल डिप्लोमैटिक डायनामिक्स को दिखाता है और अलग-अलग क्षेत्रों से रिप्रेजेंटेशन को मजबूत करता है। नए मेंबर मल्टीलेटरल गवर्नेंस के लिए एक अहम समय के दौरान ग्लोबल शांति, सिक्योरिटी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन पर चर्चा में योगदान देंगे।
- **यूनिवर्सिटी ऑफ़ लिवरपूल को NEP 2020 फ्रेमवर्क के तहत बेंगलुरु में अपना पहला इंडियन कैंपस बनाने के लिए भारत के शिक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है।** यह डेवलपमेंट भारत-UK हायर एजुकेशन कोलेबोरेशन को बढ़ाता है, ग्लोबल-क्वालिटी एजुकेशन, रिसर्च पार्टनरशिप और एकेडमिक इंटरनेशनलाइजेशन को बढ़ावा देता है। इस पहल को भारत और UK के सीनियर अधिकारियों ने सपोर्ट किया, जो बढ़ते एजुकेशनल संबंधों को दिखाता है। यह कैंपस स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल करिकुलम और रिसर्च के मौके देगा, जिससे ग्लोबल एजुकेशन हब के तौर पर भारत की स्थिति मज़बूत होगी।
- **भारत और UK ने क्लीन एनर्जी, EVs, सेमीकंडक्टर और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाले ज़रूरी मिनरल्स की सप्लाई चेन को मॉनिटर करने और मज़बूत करने के लिए नई दिल्ली में क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्ज़र्वेटरी (GSCO) लॉन्च किया।** IIT (ISM) धनबाद और यूनिवर्सिटी ऑफ़ कैम्ब्रिज जैसे इंस्टीट्यूट्स द्वारा डेवलप किया गया यह प्लेटफॉर्म रिसोर्स की अवेलेबिलिटी, जियोपॉलिटिकल रिस्क और मार्केट में होने वाले बदलावों को ट्रैक करता है। यह स्ट्रेटिजिक रिसोर्स सिक्योरिटी में कोऑपरेशन बढ़ाता है और नई टेक्नोलॉजी में सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ को सपोर्ट करता है।
- **UN जनरल असेंबली ने 2027-2028 के लिए UN सिक्योरिटी काउंसिल के पांच नॉन-परमानेंट मेंबर चुने, जिनमें ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पुर्तगाल, त्रिनिदाद और टोबैगो और जिम्बाब्वे शामिल हैं।** उनका टर्म जनवरी 2027 में शुरू होगा। किर्गिस्तान ने पहली बार ऐतिहासिक सीट हासिल की। यह चुनाव ग्लोबल डिप्लोमैटिक बैलेंस को दिखाता है और इंटरनेशनल सिक्योरिटी गवर्नेंस में रिप्रेजेंटेशन को मज़बूत करता है। ये मेंबर एक अहम जियोपॉलिटिकल समय के दौरान ग्लोबल शांति, झगड़े सुलझाने और इंटरनेशनल स्टेबिलिटी पर फैसलों में हिस्सा लेंगे।

- यूनिवर्सिटी ऑफ़ लिवरपूल को NEP 2020 के तहत बेंगलुरु में अपना पहला इंडिया कैम्पस बनाने की मंजूरी मिल गई है। इस कदम से इंडिया-UK एजुकेशन कोऑपरेशन मज़बूत होगा, जिससे इंडिया में ग्लोबल-क्वालिटी हायर एजुकेशन तक पहुँच आसान होगी। यह कैम्पस रिसर्च कोलेबोरेशन, एकेडमिक एक्सचेंज और एजुकेशन के इंटरनेशनलाइज़ेशन को बढ़ावा देगा, जिससे ग्लोबल एजुकेशन हब के तौर पर इंडिया की जगह मज़बूत होगी। यह इंडिया के हायर एजुकेशन सिस्टम में विदेशी यूनिवर्सिटी की बढ़ती हिस्सेदारी को दिखाता है।
- भारत और UK ने EVs, सेमीकंडक्टर और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाले ज़रूरी मिनरल्स की ग्लोबल सप्लाय चैन पर नज़र रखने के लिए नई दिल्ली में क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाय चैन ऑब्ज़र्वेटरी (GSCO) लॉन्च किया। IIT (ISM) धनबाद और यूनिवर्सिटी ऑफ़ कैम्ब्रिज जैसे संस्थानों के साथ मिलकर बनाया गया यह प्लेटफ़ॉर्म रिसोर्स की उपलब्धता, मार्केट रिस्क और जियोपॉलिटिकल कमज़ोरियों को ट्रैक करता है। यह स्ट्रेटेजिक रिसोर्स सिक्योरिटी और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में सहयोग को मज़बूत करता है।
- भारत ने सितंबर 2026 के बाद भी एक्काकल्चर प्रोडक्ट्स, शहद, अंडे और जानवरों के केसिंग के एक्सपोर्ट के लिए यूरोपियन यूनियन मार्केट में लगातार एक्सेस हासिल किया है। कमीशन इम्प्लीमेंटिंग रेगुलेशन (EU) 2026/1189 के तहत ऑथराइज़्ड एक्सपोर्टिंग देशों की लिस्ट में भारत को शामिल करने से दुनिया के सबसे बड़े मार्केट में से एक के साथ बिना रुकावट ट्रेड पक्का होता है। बदले हुए रेगुलेशन सख्त फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) की चिंताओं को दूर करने पर फोकस करते हैं। यह डेवलपमेंट भारत के फिशरीज़ सेक्टर के लिए खास तौर पर ज़रूरी है, जिसका EU को एक्सपोर्ट लगभग USD 1.59 बिलियन का है, जिससे ट्रेड की संभावनाएं और एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई मज़बूत होती है।
- यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) के तहत 8-18 जून तक हुई बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2026, मज़बूत क्लाइमेट एक्शन और बढ़े हुए अडैप्टेशन फाइनेंस की मांग के साथ शुरू हुई। ग्लोबल क्लाइमेट एंड हेल्थ अलायंस ने सरकारों से 2035 तक पब्लिक अडैप्टेशन फंडिंग को हर साल कम से कम \$120 बिलियन तक बढ़ाने की अपील की। कॉन्फ्रेंस में अडैप्टेशन फाइनेंस, फॉसिल-फ्यूल ट्रांज़िशन स्ट्रैटेजी, लॉस-एंड-डेमैज फंडिंग और जस्ट ट्रांज़िशन उपायों पर चर्चा हुई। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने हेल्थकेयर सिस्टम, डिज़ास्टर की तैयारी, फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट रेजिलिएंस को मज़बूत करने पर ज़ोर दिया, खासकर उन कमज़ोर और डेवलपिंग देशों में जो बढ़ते क्लाइमेट रिस्क का सामना कर रहे हैं।
- जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार, एल नीनो 2026 में वापस आ गया है और उम्मीद है कि यह पूरे साल मज़बूत होगा, जिससे सुपर एल नीनो बनने की संभावना है। मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में असामान्य रूप से गर्म पानी से शुरू होने वाली यह घटना दुनिया भर के मौसम के पैटर्न को काफी बदल देती है। यह भारत के मानसून को कमज़ोर कर सकता है, जिससे खेती, पानी की उपलब्धता और खाने के उत्पादन पर असर पड़ सकता है। दुनिया भर में, चावल, गेहूँ, कॉफी,

कोको और कपास जैसी मुख्य फसलों की पैदावार कम हो सकती है। वैज्ञानिक सूखे, बाढ़, हीटवेव और दुनिया भर में बढ़ते तापमान के बढ़ते खतरों की भी चेतावनी देते हैं।

- अहमदाबाद में हुए SAPLING हाई-लेवल पॉलिसी डायलॉग में, वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने इस बात पर ज़ोर दिया कि साउथ एशिया के फूड सिस्टम को बदलने से लाखों नौकरियाँ बन सकती हैं और अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट आ सकता है। इवेंट में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि इस इलाके का \$700 बिलियन का एग्रीकल्चर सेक्टर कम वैल्यू एडिशन और 30% से ज़्यादा फूड वेस्टेज जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। एक्सपर्ट्स ने फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड-चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और एक्सपोर्ट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की सलाह दी। PMKSY, PMFME और PLI जैसी स्कीमों से सपोर्टेड भारत का तेज़ी से बढ़ता फूड-प्रोसेसिंग सेक्टर, रोज़गार पैदा करने और इकोनॉमिक ग्रोथ के एक मुख्य ड्राइवर के तौर पर पहचाना गया।
- यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी (UNHCR) के अनुसार, 2025 के आखिर तक दुनिया भर में रिफ्यूजी की संख्या 3% घटकर 41.6 मिलियन हो जाएगी, जो एक दशक से ज़्यादा समय में पहली कमी है। यह कमी ज़्यादातर अफ़गानिस्तान, सीरिया और सूडान लौटने की वजह से हुई, जहाँ लगभग 14.7 मिलियन लोग घर लौटे, जिनमें 4.4 मिलियन रिफ्यूजी और 10.3 मिलियन देश के अंदर ही बेघर हुए लोग शामिल हैं। इस तरक्की के बावजूद, लगभग 70% रिफ्यूजी लंबे समय तक बेघर होने की स्थिति में फँसे हुए हैं। अपनी "50 बाय 35" पहल के ज़रिए, UNHCR का मकसद बेघर लोगों के बीच रोज़गार, शिक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देकर मदद पर निर्भरता कम करना है।
- भारत ने फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए अपने सालाना \$5 मिलियन के मदद पैकेज की पहली किस्त के तौर पर यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी (UNRWA) को \$2.5 मिलियन देने का वादा किया है। इस मदद से शिक्षा, हेल्थकेयर, समाज कल्याण और मानवीय राहत सेवाओं में मदद मिलेगी। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में, भारत ने इज़राइल-फ़िलिस्तीन विवाद को सुलझाने के लिए दो-देशों वाले समाधान को ही एकमात्र टिकाऊ रास्ता बताया। भारत ने गाजा में सीज़फ़ायर, आम लोगों की सुरक्षा, बिना रोक-टोक के मानवीय मदद और शांति बातचीत को फिर से शुरू करने की भी अपील की, और इस इलाके में शांति, स्थिरता और मानवीय मदद के लिए अपने लंबे समय से चले आ रहे वादे को दोहराया।
- G7 समिट 2026 से पहले, फ्रांस ने भारत को अपनी खास स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी में से एक माना है, जिससे दोनों देशों के रिश्तों की बढ़ती अहमियत पर ज़ोर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ डिफेंस कोऑपरेशन, इनोवेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी, क्लाइमेट एक्शन, स्पेस कोलेबोरेशन और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी पर बातचीत के लिए फ्रांस जाने वाले हैं। 1998 में शुरू हुई इंडिया-फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर में काफी बढ़ गई है। बातचीत में राफेल प्रोग्राम, भारत इनोवेट्स प्लेटफ़ॉर्म और बड़ा हुआ न्यूक्लियर कोऑपरेशन शामिल होने की उम्मीद है, जो इंडो-पैसिफिक और ग्लोबल मामलों में भारत के बढ़ते असर को दिखाता है।

- दक्षिण-पूर्वी हिंद महासागर के डायमेंटिना फ्रैक्चर ज़ोन में 7,000 मीटर से ज्यादा गहराई पर दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा है। चाइनीज़ एकेडमी ऑफ़ साइंसेज़ की लीडरशिप में फेंडौज़े सबमर्सिबल का इस्तेमाल करके, रिसर्चर्स ने 1,200 किलोमीटर पानी के नीचे की दूरी में 485 से ज्यादा फॉसिल साइट्स की पहचान की। 120,000 साल से लेकर 5.3 मिलियन साल पुराने फॉसिल्स मिले, जिनमें खत्म हो चुकी व्हेल प्रजातियों के अवशेष भी शामिल हैं। यह खोज व्हेल के विकास, गहरे समुद्र में बायोडायवर्सिटी, समुद्री इकोसिस्टम और लंबे समय तक कार्बन स्टोरेज के बारे में कीमती जानकारी देती है, जिससे यह समुद्री पैलियोन्टोलॉजी में एक बड़ी सफलता बन गई है।
- एलन मस्क SpaceX IPO के बाद दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बन गए, जिससे कंपनी की वैल्यू \$2 ट्रिलियन से ज्यादा हो गई। शेयर \$135 पर शुरू हुए, \$161.11 पर पहुंचे, और लगभग \$75 बिलियन जुटाए, जिससे यह इतिहास का सबसे बड़ा IPO बन गया। रीयूजेबल रॉकेट और स्टारलिनक सैटेलाइट इंटरनेट में SpaceX की सफलता ने इन्वेस्टर का भरोसा बढ़ाया। टेस्ला, xAI और X सहित मस्क के बिज़नेस एम्पायर ने उनके फाइनेंशियल माइलस्टोन को और मज़बूत किया, जिससे ग्लोबल टेक्नोलॉजी और स्पेस इकॉनमी लीडरशिप में एक बड़ा बदलाव आया।
- इंडिया-फ्रांस इनोवेशन पार्टनरशिप के हिस्से के तौर पर, PM नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रॉन मिलकर फ्रांस में "भारत इनोवेट्स 2026" नाम का इनिशिएटिव लॉन्च करेंगे। इस इवेंट में 120 स्टार्टअप, 15 इंस्टीट्यूशन और 500 इन्वेस्टर शामिल होंगे, जो सेमीकंडक्टर, AI, स्पेस, बायोटेक्नोलॉजी और एनर्जी जैसे सेक्टर पर फोकस करेंगे। इसका मकसद इंडिया और फ्रांस के बीच कोलेबोरेशन, इन्वेस्टमेंट और रिसर्च को बढ़ावा देना है। यह प्लेटफॉर्म 1998 की स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप को मज़बूत करता है और डीप-टेक इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम में इंडिया की ग्लोबल पोजीशन को बढ़ाता है।
- अमेरिका और ईरान के बीच एक अस्थायी समझ है, जिसे पाकिस्तान, कतर, तुर्की और सऊदी अरब की रीजनल डिप्लोमेसी का सपोर्ट मिला है। प्रस्तावित उपायों में समुद्री पाबंदियों में ढील देना, होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना और एक बड़े रीजनल सीज़फ़ायर फ्रेमवर्क को सपोर्ट करना शामिल है। इस डेवलपमेंट से एनर्जी सिक्योरिटी बेहतर हो सकती है, तेल मार्केट स्थिर हो सकते हैं, शिपिंग कॉस्ट कम हो सकती है और जियोपॉलिटिकल टेंशन कम हो सकते हैं। भारत के लिए, आसान एनर्जी सप्लाई और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव कम होने से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ट्रेड पर अच्छा असर पड़ सकता है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर के दौरान भारत और फ्रांस ने 13 बड़े नतीजों की घोषणा की, जिससे उनकी स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप और मज़बूत हुई। खास पहलों में इंडिया-फ्रांस इनोवेशन रोडमैप 2030, एक जॉइंट AI वर्किंग ग्रुप, बड़ी हुई UPI सर्विस, स्टार्टअप कोलेबोरेशन, डिफेंस कोऑपरेशन, रेलवे प्रोजेक्ट और ISRO और CNES के बीच स्पेस रिसर्च पार्टनरशिप शामिल हैं। दोनों देश पांच साल के अंदर आपसी व्यापार को दोगुना करने की दिशा में काम करने पर भी सहमत हुए, जिससे इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, आर्थिक सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए उनका कमिटमेंट दिखा।
- इंडिया-फ्रांस ATL ब्रिज को दोनों देशों के युवा इनोवेटर्स, स्कूलों और एंटरप्रेन्योरों को जोड़ने के लिए लॉन्च किया गया है। अटल इनोवेशन मिशन और ला फाउंडेशन डिसॉल्ट सिस्टम्स के बीच सहयोग से डेवलप की गई यह पहल स्टूडेंट एक्सचेंज, इनोवेशन प्रोजेक्ट्स और एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स को सपोर्ट करेगी। फ्रांस भारत के अटल टिकरिंग लैब मॉडल पर आधारित अपनी पहली स्कूल इनोवेशन लैब भी बनाएगा। यह प्रोग्राम एजुकेशनल सहयोग को मज़बूत करता है, इनोवेशन को बढ़ावा देता है और भारत और फ्रांस के बीच लोगों के बीच संबंधों को गहरा करता है।
- फ्रांस में 52 वें G7 समिट में बड़ी एडवांसड इकॉनमी के लीडर्स इकोनॉमिक ग्रोथ, एनर्जी सिक्योरिटी, ज़रूरी मिनरल्स, सप्लाई चेन्स और जियोपॉलिटिकल चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एक साथ आए। US-ईरान के बीच संभावित समझौते और होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने की खबरों के बीच इस समिट को अहमियत मिली, जिससे ग्लोबल ऑयल मार्केट स्थिर हो सकते हैं। भारत ने एक पार्टनर देश के तौर पर हिस्सा लिया, जिससे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और ग्लोबल गवर्नेंस चर्चाओं में इसकी बढ़ती भूमिका पर ज़ोर दिया गया।
- भारत इनोवेट्स 2026 समिट में भारत के बढ़ते डीप-टेक इकोसिस्टम को दिखाया गया, जिसमें 120 से ज्यादा स्टार्टअप, 20 इंस्टीट्यूट और 350 ग्लोबल इन्वेस्टर शामिल थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस और क्लीन एनर्जी में इनोवेशन पेश किए गए। इस इवेंट ने इनोवेशन में भारत-फ्रांस के सहयोग को मज़बूत किया और रिसर्च, एंटरप्रेन्योरशिप और इंटरनेशनल पार्टनरशिप के ज़रिए ग्लोबल टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप हब बनने के भारत के सपने को दिखाया।
- मोहम्मद बाघेर गालिबफ़ ईरान के सबसे असरदार पॉलिटिकल लोगों में से एक हैं, जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं और देश की पॉलिसी बनाने और स्ट्रेटिजिक मामलों में अहम भूमिका निभाते हैं। IRGC के पूर्व कमांडर, पुलिस चीफ़ और तेहरान के मेयर के तौर पर, उन्हें गवर्नेंस और सिक्योरिटी में दशकों का अनुभव है। उनका असर घरेलू पॉलिटिक्स और फॉरिन पॉलिसी की चर्चाओं तक फैला हुआ है, जिससे वे ईरान की भविष्य की पॉलिटिकल और डिप्लोमैटिक दिशा को बनाने में एक अहम व्यक्ति बन गए हैं।
- पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल 6.2 के तहत जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म (JCM) के लिए इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क अपनाया है। यह मैकेनिज्म टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग के ज़रिए लो-कार्बन प्रोजेक्ट्स पर सहयोग को मुमकिन बनाता है, जिसके नतीजे में कार्बन क्रेडिट दोनों देशों के बीच शेयर किए जाते हैं। यह फ्रेमवर्क प्रोजेक्ट अप्रूवल, मॉनिटरिंग, वेरिफिकेशन और क्रेडिट जारी करने के लिए ट्रांसपेरेंट प्रोसेस बनाता है, साथ ही एमिशन में कमी की डबल काउंटिंग को रोकता है। यह पहल दोनों देशों को उनके नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन (NDCs) को पाने और क्लाइमेट गोलस को आगे बढ़ाने में मदद करती है।

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मार्क कार्नी ने जनरल सिक्योरिटी ऑफ़ इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट (GSOIA) के लिए बातचीत शुरू करने और 2026 में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (CEPA) को पूरा करने की कोशिशों में तेज़ी लाने पर सहमति जताई। प्रस्तावित एग्रीमेंट से डिफेंस , इंटेलिजेंस शेयरिंग , ट्रेड , एनर्जी सिक्योरिटी , ज़रूरी मिनरल्स और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में सहयोग मज़बूत होगा। यह डेवलपमेंट भारत और कनाडा के बीच बढ़ते स्ट्रेटेजिक जुड़ाव और इकोनॉमिक सहयोग को दिखाता है।
- G7 समिट 2026 में , भारत इबोला के दोबारा फैलने से निपटने और कैंसर के खिलाफ इंटरनेशनल एक्शन को मज़बूत करने के लिए ग्लोबल कोशिशों में शामिल हुआ। पार्टनर देशों के साथ, भारत ने वैक्सीन डेवलपमेंट , बीमारी की निगरानी , डायग्नोस्टिक रिसर्च और पब्लिक हेल्थ की तैयारी से जुड़ी कोशिशों का सपोर्ट किया। समिट में सस्ती हेल्थकेयर एक्सेस, कैंसर का जल्दी पता लगाने और इंटरनेशनल रिसर्च में सहयोग पर भी ज़ोर दिया गया। भारत का हिस्सा लेना ग्लोबल हेल्थ डिप्लोमेसी में उसकी बढ़ती भूमिका और दुनिया भर में हेल्थ चुनौतियों से निपटने में मल्टीलेटरल सहयोग को दिखाता है।
- गैलरीज़ लाफ़ायट नाइस मैसेना में सर्विस लॉन्च करके यूनिफ़ाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) की इंटरनेशनल पहुंच को बढ़ाया है। इस पहल को NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) और लायरा कलेक्ट ने आसान बनाया , जिससे भारतीय विज़िटर्स फ़्रांस में बिना किसी रुकावट के QR-बेस्ड पेमेंट कर सकते हैं। UPI अब नौ देशों में चल रहा है , जिनमें फ़्रांस, सिंगापुर, UAE, नेपाल, भूटान, मॉरिशस, कतर, श्रीलंका और कंबोडिया शामिल हैं। इस बढ़ोतरी से डिजिटल पेमेंट में भारत की लीडरशिप मज़बूत होगी और क्रॉस-बॉर्डर फाइनेंशियल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा।
- यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑफिशियली यूनाइटेड स्टेट्स इंडो-पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर वापस यूनाइटेड स्टेट्स पैसिफिक कमांड कर दिया है। असल में 1947 में बनी इस कमांड का नाम 2018 में इंडो-पैसिफिक स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट को दिखाने के लिए बदला गया था। हालांकि पुराना नाम वापस ले लिया गया है, लेकिन इसके मिशन, लोगों और ऑपरेशनल जिम्मेदारियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह कमांड US के वेस्ट कोस्ट से लेकर भारत की पश्चिमी सीमा तक फैले दुनिया के सबसे स्ट्रेटेजिक रूप से ज़रूरी इलाकों में से एक की देखरेख करती है।
- अमेरिका और ईरान ने इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग की घोषणा की , जो एक 14-पॉइंट का अंतरिम फ्रेमवर्क है जिसका मकसद इलाके के तनाव को कम करना और बड़े पैमाने पर डिप्लोमैटिक बातचीत को आसान बनाना है। इस समझौते में मिलिट्री तनाव को रोकने, होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने और बैन हटाने और इलाके की स्थिरता पर बातचीत करने के वादे शामिल हैं। इस डेवलपमेंट से ग्लोबल एनर्जी मार्केट को सपोर्ट मिलने, समुद्री सुरक्षा में सुधार होने और दोनों देशों के बीच लगातार डिप्लोमैटिक बातचीत को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
- फ़्रांस में गैलरीज़ लाफ़ायट नाइस मैसेना में लॉन्च के साथ यूनिफ़ाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) की इंटरनेशनल पहुंच को बढ़ाया है। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) और लायरा कलेक्ट के बीच

सहयोग से लागू किया गया यह इंटीग्रेशन भारतीय विज़िटर्स को विदेश में तुरंत QR-कोड-बेस्ड डिजिटल पेमेंट करने की सुविधा देता है। UPI अब नौ देशों में चालू है, जिससे यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ी है और भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को दुनिया भर में स्वीकार करने में मदद मिली है। यह विस्तार भारत-फ़्रांस डिजिटल सहयोग को भी मजबूत करता है और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इनोवेशन में भारत की लीडरशिप को दिखाता है।

- यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑफिशियली यूनाइटेड स्टेट्स पैसिफिक कमांड का नाम फिर से शुरू कर दिया है , 2018 में हुए बदलाव को पलटते हुए इंडो-पैसिफिक कमांड कर दिया गया था। नाम तो बदल गया है, लेकिन कमांड का मिशन, ऑपरेशनल स्ट्रक्चर, लोग और ज्योग्राफिकल जिम्मेदारियां वैसी ही रहेंगी। 1947 में बनी यह सबसे पुरानी और सबसे बड़ी US कॉम्बैटेंट कमांड है। इस कदम को काफी हद तक सिंबॉलिक और एडमिनिस्ट्रेटिव माना जा रहा है, जो ऐतिहासिक नाम पर वापसी दिखाता है, जबकि एशिया-पैसिफिक रीजन में वही स्ट्रेटेजिक फोकस बनाए रखता है, जिसमें इंडिया की वेस्टर्न बाउंड्री तक के एरिया भी शामिल हैं।
- अमेरिका और ईरान ने इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए , जो इलाके के तनाव को कम करने के लिए बनाया गया 14-पॉइंट का अंतरिम समझौता है। इस समझौते में 60-दिन का बातचीत का फ्रेमवर्क , मिलिट्री तनाव से बचने के वादे, और होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने की योजना बनाई गई है, जो एक ज़रूरी ग्लोबल एनर्जी रूट है। इसमें पाबंदियों में राहत और ईरानी तेल एक्सपोर्ट पर भी चर्चा शामिल है, जबकि ईरान ने न्यूक्लियर हथियार न बनाने का अपना वादा दोहराया है। इस समझौते से इलाके की स्थिरता, डिप्लोमैटिक जुड़ाव और ग्लोबल एनर्जी मार्केट में भरोसे में सुधार होने की उम्मीद है।
- पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत को एक भरोसेमंद ग्लोबल पार्टनर के तौर पर तेज़ी से पहचाना जा रहा है। उन्होंने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और इनक्लूसिव ग्रोथ में भारत की तरक्की पर ज़ोर दिया, साथ ही इंटरनेशनल रिश्तों में भरोसे की अहमियत पर भी ज़ोर दिया। G7 समिट 2026 में हुई चर्चाओं का जिक्र करते हुए, उन्होंने इनक्लूसिव ग्लोबल गवर्नेंस, जिम्मेदार टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और विकासशील देशों के लिए मज़बूत रिप्रेजेंटेशन की वकालत की। उन्होंने डिफेंस , स्पेस, क्लाइमेट एक्शन, ट्रेड और साइंटिफिक रिसर्च में भारत-फ़्रांस के बढ़ते सहयोग पर भी ज़ोर दिया।
- उज़्बेकिस्तान, BRICS देशों द्वारा बनाए गए न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) में शामिल होने वाला पहला सेंट्रल एशियाई देश बन गया है। शामिल होने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद, उज़्बेकिस्तान बैंक का 10वां सदस्य बन गया , जिससे उसे इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए लंबे समय की फाइनेंसिंग मिल गई। 2015 में अपनी स्थापना के बाद से, NDB ने लगभग US\$43 बिलियन के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। यह सदस्यता उज़्बेकिस्तान के मॉडर्नाइज़ेशन लक्ष्यों का समर्थन करती है और क्षेत्रीय और ग्लोबल आर्थिक सहयोग में इसकी बढ़ती भूमिका को दिखाती है।

- फ्रांस अपने पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने वाला है, जो पूरी तरह से भारत से लाए गए पत्थरों से बना है और भारतीय कारीगरों ने इसे बनाया है। यह मंदिर असली हिंदू आर्किटेक्चरल सिद्धांतों को फॉलो करता है और इसका उद्घाटन 15 दिन के कल्चरल और धार्मिक उत्सव के साथ होगा। उम्मीद है कि यह विदेशों में रहने वाले भारतीय लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल और कल्चरल हब के तौर पर काम करेगा, साथ ही कल्चरल लेन-देन को बढ़ावा देगा और विदेशों में भारतीय परंपराओं को बचाए रखेगा। यह प्रोजेक्ट बढ़ते भारत-फ्रांस कल्चरल रिश्तों की निशानी है और भारतीय विरासत की ग्लोबल मौजूदगी को दिखाता है।
- यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) ने बच्चों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा नियम बनाया है, जिसमें सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की कम से कम उम्र 15 साल तय की गई है। इस पॉलिसी में AI-बेस्ड उम्र का वेरिफिकेशन, डिजिटल पहचान की जांच, ज़्यादा मज़बूत प्राइवैसी सेटिंग्स, पैरेंटल कंट्रोल और अजनबियों के साथ बातचीत पर रोक लगाना ज़रूरी है। प्लेटफॉर्म को कम उम्र के अकाउंट की पहचान करके उन्हें हटाना होगा। UAE ऐसे पूरे देश में नियम लागू करने वाला पहला अरब देश बन गया है, जो बच्चों और टीनएजर्स में ऑनलाइन सुरक्षा, नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट के संपर्क में आने, स्क्रीन की लत और डिजिटल प्राइवैसी को लेकर बढ़ती चिंताओं को दिखाता है।
- प्रोफेसर डॉ. बिमल पटेल को समुद्री कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण (ITLOS) का न्यायाधीश चुना गया है, जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय कानूनी कूटनीति के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS) के तहत स्थापित, ITLOS एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय है जिसका मुख्यालय हैम्बर्ग, जर्मनी में है, जो समुद्री सीमाओं, नेविगेशन अधिकार, मत्स्य पालन, समुद्री संसाधनों, पर्यावरण संरक्षण और हिरासत में लिए गए जहाजों से संबंधित विवादों को सुलझाता है। पटेल वर्तमान में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य कर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य हैं और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में कार्य करते हैं। उनका चुनाव वैश्विक समुद्री शासन में भारत की भूमिका को मजबूत करता है और नीरू चड्ढा की उपस्थिति को पूरक बनाता है, जो वर्तमान में ITLOS की उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रही हैं।
- साउथ अटलांटिक आइलैंड सेंट हेलेना पर रहने वाले सेशेल्स के एक बड़े कछुए जोनाथन को ऑफिशियली दुनिया का सबसे पुराना ज़मीन पर रहने वाला जानवर और अब तक का सबसे पुराना कछुआ माना गया है। जोनाथन का जन्म लगभग 1832 में हुआ था, और उनकी उम्र लगभग 194 साल है। अपनी ज़िंदगी में, उन्होंने विक्टोरियन युग, एफिल टॉवर का बनना, ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज़ का आविष्कार, और कंप्यूटर, इंटरनेट और स्पेस एक्सप्लोरेशन की शुरुआत जैसी बड़ी ऐतिहासिक घटनाएँ देखी हैं। इतनी ज़्यादा उम्र होने के बावजूद, जोनाथन काफी हेल्दी और एक्टिव रहते हैं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि उनकी लंबी उम्र का संबंध धीमे मेटाबॉलिज़्म, कम स्ट्रेस वाली लाइफस्टाइल, अच्छे जेनेटिक्स और अच्छे बायोलॉजिकल

सिस्टम से है। रिसर्चर हेल्दी एजिंग, लंबी उम्र, सेलुलर रिपेयर और उम्र से जुड़ी बीमारियों के बारे में जानकारी पाने के लिए उनके DNA की स्टडी कर रहे हैं।

- 2024 का आम चुनाव जीतने के दो साल से भी कम समय बाद, कीर स्टारमर ने यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने किंग चार्ल्स III को इसकी जानकारी दी और नए लेबर नेता के चुने जाने तक वे केयरटेकर प्रधानमंत्री बने रहेंगे। उनके इस्तीफे के बाद खराब लोकल चुनाव नतीजे, पार्टी के अंदरूनी मतभेद, घटता पब्लिक सपोर्ट और आर्थिक चुनौतियाँ आईं। क्योंकि लेबर के पास पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी है, इसलिए उसका अगला चुनाव हुआ नेता अपने आप प्रधानमंत्री बन जाएगा। लीडरशिप ट्रांज़िशन में आर्थिक सुधार, पब्लिक सर्विस और भविष्य की चुनावी स्ट्रेटेजी को प्राथमिकता दिए जाने की उम्मीद है।
- अपनी BRICS चेरपरसंसनिषिप में हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं BRICS एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग होस्ट करेगा, जिसकी थीम "Energy for All" होगी। मिनिस्टर्स एनर्जी सिक्योरिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी ट्रांज़िशन, स्मार्ट ग्रिड, एनर्जी स्टोरेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा करेंगे। BRICS, जिसमें 11 सदस्य देश हैं, दुनिया की लगभग आधी आबादी और दुनिया की GDP का लगभग 40% रिप्रेजेंट करता है। भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस जैसी पहलों को दिखाएगा, साथ ही उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सस्ती, भरोसेमंद और सस्टेनेबल एनर्जी के लिए सहयोग को बढ़ावा देगा।
- भारत ने 22-23 जून 2026 को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल की लीडरशिप में BRICS नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मीटिंग होस्ट की। डेलीगेट्स ने साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिस्क, टेररिज्म, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन, डिजिटल सिक्योरिटी और ट्रांसनेशनल क्राइम पर चर्चा की। चीन, रूस, ईरान और दूसरे BRICS मेंबर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स ने काउंटर-टेररिज्म पर जॉइंट वकिंग ग्रुप्स की प्रोग्रेस का रिव्यू किया, जिसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग, साइबर रेजिलिएंस और जिम्मेदार टेक्नोलॉजी इस्तेमाल पर जोर दिया गया। मीटिंग में उभरते नॉन-ट्रेडिशनल सिक्योरिटी खतरों से निपटने में इंटरनेशनल कोऑपरेशन को मजबूत किया गया, साथ ही कोलेबोरेटिव ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स के लिए भारत के कमिटमेंट पर भी जोर दिया गया।
- कीर स्टारर के इस्तीफे के बाद, एंडी बर्नहैम लेबर पार्टी लीडरशिप की चर्चाओं में एक बड़े दावेदार के तौर पर उभरे। 1970 में जन्मे बर्नहैम ने लेह के MP, हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट, कल्चर सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट और 2017 से 2026 तक ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर के तौर पर काम किया। "किंग इन द नॉर्थ" के नाम से मशहूर, उन्होंने रीजनल ऑटोनॉमी, पब्लिक सर्विस रिफॉर्म और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट किया। मेकरफील्ड के MP के तौर पर पार्लियामेंट में लौटने पर, बर्नहैम को डीसेंट्रलाइज़ेशन और कम्युनिटी-फोकस्ड गवर्नेंस का एक मज़बूत सपोर्टर माना जाता है।

- मशहूर अमेरिकी इकोनॉमिस्ट एलन ग्रीनस्पैन का 22 जून 2026 को 100 साल की उम्र में निधन हो गया। "द मेस्ट्रो" के नाम से मशहूर, उन्होंने 1987 से 2006 तक चार प्रेसिडेंट्स के अंडर US फेडरल रिजर्व के चेयरमैन के तौर पर काम किया। ग्रीनस्पैन ने 1987 के ब्लैक मंडे क्रैश, डॉट-कॉम बूम और 9/11 के बाद की रिकवरी में अमेरिकी इकोनॉमी को गाइड किया। अपने सतर्क "फेडस्पीक" कम्युनिकेशन स्टाइल के लिए मशहूर, उनकी मॉनेटरी पॉलिसीज़ ने ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को आकार दिया, हालांकि 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले फाइनेंशियल डीरेगुलेशन के लिए उनकी लेगेसी पर बहस होती रहती है।
- यूरोपियन यूनियन (EU) ऑफिशियली पैक्स सिलिका इनिशिएटिव में शामिल हो गया है। यह अमेरिका का बनाया हुआ एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और ज़रूरी टेक्नोलॉजी में सहयोग को बढ़ावा देता है। यह पहल पार्टनर देशों के बीच मज़बूत सप्लाय चेन, AI इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल कनेक्टिविटी, एनर्जी सिक्योरिटी, ज़रूरी मिनरल और एक्सपोर्ट कोऑर्डिनेशन को मज़बूत करती है। एग्रीमेंट के हिस्से के तौर पर, EU अमेरिका से कम से कम \$40 बिलियन के AI चिप्स खरीदने का प्लान बना रहा है। अभी इसमें भारत, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और कई यूरोपियन देश शामिल हैं, जो सुरक्षित टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम और इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं।
- यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी-जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने बिगडटे ग्लोबल क्लाइमेट संकट के बारे में चेतावनी दी, और फॉसिल फ्यूल, खेती और वेस्ट मैनेजमेंट से मीथेन एमिशन को कम करने के लिए तुरंत एक्शन लेने को कहा। लंदन में बोलते हुए, उन्होंने मीथेन पर UN कॉल टू एक्शन लॉन्च किया, जिसमें मीथेन के वार्मिंग असर पर ज़ोर दिया गया, जो बीस सालों में कार्बन डाइऑक्साइड से लगभग 80 गुना ज़्यादा मज़बूत है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटर से होने वाले एमिशन के बारे में भी चिंता जताई। इसके अलावा, सस्टेनेबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट-रेज़िलिएंट शहरी डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए 36 शहरों को शामिल करते हुए ग्लोबल अर्बन डेटा सेंटर्स पैक लॉन्च किया गया।
- बांग्लादेश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) का 27वां सदस्य बन गया है, जो खतरे में पड़ी बड़ी बिलियों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए दुनिया भर में सहयोग को मज़बूत करेगा। भारत ने 2023 में इसे शुरू किया था और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। यह अलायंस टाइगर, शेर, तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर और प्यूमा को बचाने पर फोकस करता है। बांग्लादेश की सदस्यता सुंदरबन के संरक्षण को बढ़ाती है, सीमा पार वाइल्डलाइफ मैनेजमेंट, शिकार रोकने की कोशिशों, रहने की जगह की सुरक्षा, साइंटिफिक रिसर्च और बायोडायवर्सिटी के संरक्षण को बढ़ावा देती है, साथ ही खतरे में पड़ी प्रजातियों को बचाने के लिए क्षेत्रीय सहयोग को भी मज़बूत करती है।
- दूसरा पैक्स सिलिका समिट वाशिंगटन, DC में हुआ, जहाँ भारत समेत 35 देशों ने ज़िम्मेदार और इनोवेशन-फ्रेंडली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए AI के मौके पर जॉइंट स्टेटमेंट पर

साइन किए। US की लीडरशिप वाली यह पहल भरोसेमंद AI गवर्नेंस, मज़बूत सेमीकंडक्टर सप्लाय चेन और इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन पर फोकस करती है। खास घोषणाओं में सुरक्षित AI ट्रेड के लिए पैक्स पास सिस्टम और AI-स्किल्ड प्रोफेशनल्स को डेवलप करने के लिए US फंडिंग से सपोर्टेड फाउंड्री स्कूल शामिल थे। भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री (MeitY) के अधिकारियों के ज़रिए हिस्सा लिया, जिससे ग्लोबल AI गवर्नेंस और डिजिटल पॉलिसी फ्रेमवर्क में उसकी भूमिका मज़बूत हुई।

- भारत ने भयानक भूकंप के बाद वेनेजुएला की मदद के लिए एक मानवीय मिशन ऑपरेशन अमिस्टैड शुरू किया। IAF ने राहत का सामान, मेडिकल मदद और 40 से ज़्यादा सदस्यों की एक रेस्क्यू टीम लेकर C-17 एयरक्राफ्ट भेजा। इस मिशन में हॉस्पिटल, मेडिकल किट और इमरजेंसी सपोर्ट शामिल हैं। यह दुनिया भर में आई आपदाओं में सबसे पहले मदद करने वाले के तौर पर भारत की भूमिका को दिखाता है। भारत ने एकजुटता दिखाई और लगातार मदद का वादा किया। यह ऑपरेशन HADR फ्रेमवर्क के तहत भारत की दुनिया भर में मानवीय लीडरशिप को मज़बूत करता है।
- SCO विमेंस फोरम 2026 किर्गिस्तान के बिश्केक में हुआ, जिसमें महिला सशक्तिकरण, लीडरशिप और जेंडर इक्वालिटी पर फोकस किया गया। भारत ने मिशन शक्ति, मिशन पोषण 2.0 और 100 मिलियन महिलाओं को कवर करने वाले SHGs के ज़रिए अपने महिला-नेतृत्व वाले डेवलपमेंट मॉडल पर ज़ोर दिया। लखपति दीदी स्कीम के तहत 30 मिलियन से ज़्यादा महिलाओं ने इनकम में अहम मुकाम हासिल किए। यह फोरम SCO 2035 स्ट्रेटेजी के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका पर सहयोग को बढ़ावा देता है। यह महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण पर सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को मज़बूत करता है।
- जापानी PM साने ताकाइची 16वें इंडिया-जापान एनुअल समिट के लिए भारत (1-3 जुलाई 2026) आएंगी। वह डिफेंस, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और ट्रेड में सहयोग का रिब्यू करने के लिए PM नरेंद्र मोदी से मिलेंगी। जापान भारत में एक बड़ा इन्वेस्टर है और बुलेट ट्रेन और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है। दोनों देश QUAD, G20 और इंडो-पैसिफिक फ्रेमवर्क के तहत सहयोग करते हैं। इस दौर से स्ट्रेटेजिक संबंध, सप्लाय चेन और रीजनल सिक्योरिटी सहयोग मज़बूत होगा।
- आइसलैंड में अपना पहला आम प्रमोशन इवेंट किया, जिसे APEDA और रेकजाविक में भारतीय दूतावास ने ऑर्गनाइज़ किया था। रेकजाविक और अकुरेरी में हुए इस इवेंट में दशहरी, चौसा, लंगड़ा और केसर जैसी वैरायटी दिखाई गई। इसका मकसद नॉर्डिक मार्केट में एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। चर्चाओं में इंडिया-EFTA TEPA एग्रीमेंट के तहत मौकों पर रोशनी डाली गई। आइसलैंड थाईलैंड और ब्राज़ील जैसे देशों से आम इंपोर्ट करता है, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग USD 3.3 मिलियन (2025) है। इस पहल से इंडिया के एग्रीकल्चर-एक्सपोर्ट डायवर्सिफिकेशन को बढ़ावा मिलेगा।

बैंकिंग और वित्त

मई 2026 में रिकॉर्ड 23.20 बिलियन ट्रांज़ैक्शन हासिल किए

- भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) ने मई 2026 में अपना अब तक का सबसे अच्छा मंथली परफॉर्मेंस रिकॉर्ड किया, जिसमें ₹29.90 ट्रिलियन के 23.20 बिलियन ट्रांज़ैक्शन प्रोसेस किए गए। अप्रैल 2026 की तुलना में, ट्रांज़ैक्शन वॉल्यूम और वैल्यू में लगातार बढ़ोतरी देखी गई, प्लेटफॉर्म पर हर दिन औसतन लगभग 748 मिलियन ट्रांज़ैक्शन हुए। UPI रिटेल शाॉपिंग, फ़ूड डिलीवरी, यूटिलिटी बिल पेमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ई-कॉमर्स और पीयर-टू-पीयर ट्रांसफ़र जैसे सेक्टर में तुरंत, सुरक्षित और कैशलेस ट्रांज़ैक्शन को मुमकिन बनाकर भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम पर अपना दबदबा बनाए हुए है। यह ज़बरदस्त बढ़ोतरी बढ़ते कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, मर्चेन्ट की ज़्यादा स्वीकार्यता और डिजिटल इकोनॉमी और फाइनेंशियल इनक्लूजन की दिशा में सरकार के लगातार प्रयासों को दिखाती है।

मई 2026 में GST कलेक्शन ₹1.94 लाख करोड़ तक पहुंचा

- भारत का गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (GST) कलेक्शन मई 2026 में ₹1.94 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो लगातार आर्थिक विकास और मज़बूत घरेलू मांग को दिखाता है। यह बढ़ोतरी ज़्यादा टैक्सेबल सप्लाई, बेहतर टैक्स कम्प्लायंस और इम्पोर्ट से जुड़े GST रेवेन्यू में काफ़ी बढ़ोतरी की वजह से हुई। मज़बूत कलेक्शन से पता चलता है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अच्छा है, खपत बढ़ रही है और सभी सेक्टर में बिज़नेस एक्टिविटी बढ़ रही है। महीने के दौरान, सरकार ने काफ़ी GST रिफंड भी जारी किए, जिससे एक्सपोर्टर्स और बिज़नेस के लिए लिक्विडिटी बेहतर हुई। यह परफॉर्मेंस भारत के इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम की बढ़ती एफिशिएंसी और सरकारी रेवेन्यू को मज़बूत करने में इसके योगदान को दिखाता है।

MSMEs को कैपिटल जुटाने में मदद के लिए प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया गया

- ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के साथ पार्टनरशिप में, MSMEs और डिजिटल-फर्स्ट बिज़नेस को कैपिटल मार्केट तक पहुंचाने में मदद करने के लिए प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया है। यह पहल BSE SME प्लेटफॉर्म के लिए ज़रूरी कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, रेगुलेटरी कंप्लायंस, गवर्नेंस स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और लिस्टिंग प्रोसीजर पर गाइडेंस देती है। उभरते हुए एंटरप्राइजेज को पब्लिक लिस्टिंग के लिए तैयार करके, प्रोजेक्ट शिखर का मकसद लॉन्ग-टर्म कैपिटल तक पहुंच को बेहतर बनाना, बिज़नेस ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना, इन्वेस्टर का भरोसा बढ़ाना और भारत के बढ़ते स्टार्टअप और MSME इकोसिस्टम को सपोर्ट करना है।

भारत ने अब तक का सबसे ज़्यादा सीफूड एक्सपोर्ट रिकॉर्ड किया

- भारत ने FY 2025-26 के दौरान अब तक का सबसे ज़्यादा सीफूड एक्सपोर्ट किया, जिसमें ₹73,890 करोड़ कीमत का 19.72 लाख मीट्रिक टन एक्सपोर्ट किया गया। फ़ोज़न थ्रिम्प सबसे बड़ा एक्सपोर्ट प्रोडक्ट रहा, जिसने एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई में सबसे ज़्यादा हिस्सा दिया, जबकि अमेरिका वैल्यू के हिसाब से और चीन क्वांटिटी के हिसाब से सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बना। दूसरे बड़े एक्सपोर्ट आइटम में फ़ोज़न मछली, स्क्रिड, कटलफ़िश, फ़िशमिल और मछली का तेल शामिल थे। यह रिकॉर्ड परफॉर्मेंस ग्लोबल सीफूड मार्केट में भारत

की बढ़ती कॉम्पिटिटिवनेस को दिखाता है और विदेशी मुद्रा से कमाई करने और तटीय इलाकों में रहने वालों की मदद करने में समुद्री प्रोडक्ट सेक्टर की अहमियत को दिखाता है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) 4.9% बढ़ा

- भारत के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स (IIP) ने अप्रैल 2026 में 4.9% की ग्रोथ दर्ज की, जो मुख्य रूप से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के मज़बूत परफॉर्मेंस की वजह से हुआ। सरकार ने IIP के लिए एक नया बेस ईयर (2022-23) भी शुरू किया, जो पहले की 2011-12 सीरीज़ की जगह लेगा ताकि इकॉनॉमी में स्ट्रक्चरल बदलावों को बेहतर ढंग से दिखाया जा सके। बदले हुए इंडेक्स में रिन्यूएबल एनर्जी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, पानी की सप्लाई, रेयर अर्थ मिनरल्स, वैकसीन, एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स और मेडिकल डिवाइस जैसे उभरते सेक्टर शामिल हैं, जो भारत के इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग लैंडस्केप की ज़्यादा सही तस्वीर देते हैं।

भारतीय बैंक एशिया-प्रशांत के सबसे ज़्यादा पूंजी वाले बैंकों में शामिल

- S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार, भारतीय बैंक एशिया-पैसिफिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कैपिटल वाले बैंकों में से हैं। कोटक महिंद्रा बैंक 16.56% के लेवरेज रेशियो के साथ लिस्ट में सबसे ऊपर है, उसके बाद HDFC बैंक (11.14%), ICICI बैंक (10.84%), और एक्सिस बैंक (9.28%) हैं। पब्लिक सेक्टर बैंकों में यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया ने सबसे ज़्यादा सुधार दर्ज किया। रिपोर्ट में भारत के मज़बूत बैंकिंग रेगुलेशन, बेहतर एसेट क्वालिटी, बेसल III कम्प्लायंस, और समझदारी भरे रिस्क मैनेजमेंट तरीकों पर ज़ोर दिया गया है, जो भारतीय बैंकिंग सेक्टर की मज़बूती और स्थिरता को दिखाता है।

MoSPI ने जिला घरेलू उत्पाद दिशानिर्देश जारी किए

- मिनिस्ट्री ऑफ़ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन (MoSPI) ने 2022-23 को बेस ईयर मानकर डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (DDP) का अनुमान लगाने के लिए फ़ाइनल गाइडलाइंस जारी की हैं। यह फ्रेमवर्क बॉटम-अप अप्रोच का इस्तेमाल करके सभी ज़िलों में ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GDDP), नेट डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (NDDP), और पर कैपिटा इनकम के कैलकुलेशन को स्टैंडर्ड बनाता है। यह पहल ज़िला-लेवल के इकोनॉमिक डेटा की एक्यूरेसी और कम्परेबिलिटी में सुधार करेगी, जिससे एविडेंस-बेस्ड पॉलिसीमेकिंग, डीसेंट्रलाइज़्ड प्लानिंग और डेवलपमेंट रिसोर्सेज के एफिशिएंट एलोकेशन को सपोर्ट मिलेगा।

भारत दुनिया की पांचवीं सबसे ज़्यादा डिजिटल अर्थव्यवस्था बन गया है

- SIDE 2026 रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2025 में आठवें स्थान से सुधरकर दुनिया की पांचवीं सबसे ज़्यादा डिजिटल अर्थव्यवस्था बन गया है। यह रैंकिंग CHIPS फ्रेमवर्क (कनेक्ट, हार्नेस, इनोवेट, प्रोटेक्ट और सस्टेन) पर आधारित है। भारत ने AI रेडीनेस में भी दुनिया भर में चौथा स्थान हासिल किया, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनटेक इनोवेशन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी अपनाने में तेज़ी से हो रही बढ़ोतरी को दिखाता है। रिपोर्ट में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इनोवेशन में भारत के ग्लोबल लीडर के तौर पर उभरने पर ज़ोर दिया गया है।

कंबोडिया में UPI लॉन्च हुआ

- नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (NPCI) ने ACLEDA बैंक के साथ पार्टनरशिप में कंबोडिया में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) सर्विस लॉन्च की है, जिससे यह भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम अपनाने वाला नौवां देश बन गया है। भारतीय यात्री अब कंबोडिया के KHQR और बाकॉग पेमेंट नेटवर्क से जुड़े 4.5 मिलियन से ज्यादा मर्चेन्ट्स पर QR-कोड-बेस्ड पेमेंट कर सकते हैं। यह पहल क्रॉस-बॉर्डर डिजिटल पेमेंट को मज़बूत करती है, टूरिज़्म को बढ़ावा देती है, फ़ाइनेंशियल कनेक्टिविटी को बढ़ाती है, और भारत के ग्लोबल फ़िनटेक फ़ुटप्रिंट को बढ़ाती है।

RBI ने रेपो रेट को 5.25% पर अपरिवर्तित रखा

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने जून 2026 की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) की मीटिंग में रेपो रेट को 5.25% पर बिना किसी बदलाव के रखा। सेंट्रल बैंक ने कच्चे तेल की अस्थिर कीमतों, पश्चिम एशिया में जियोपॉलिटिकल तनाव और सप्लाई चेन में रुकावटों से पैदा होने वाले महंगाई के दबाव को लेकर चिंता जताई। RBI ने FY27 के लिए 6.6% GDP ग्रोथ और 5.1% CPI महंगाई का अनुमान लगाया, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी का रुख न्यूट्रल रखा। यह फैसला आर्थिक विकास पर बुरा असर डाले बिना महंगाई को कंट्रोल करने के लिए एक संतुलित तरीका दिखाता है।

RBI की मॉनेटरी पॉलिसी न्यूट्रल बनी रही

- मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) ने अपना न्यूट्रल पॉलिसी रख बनाए रखा, और अनिश्चित ग्लोबल आर्थिक हालात के बीच मॉनेटरी मैनेजमेंट के लिए डेटा-ड्रिवन अप्रोच पर ज़ोर दिया। RBI ने महंगाई कंट्रोल को सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ बैलेंस करने और काफ़ी लिक्विडिटी और फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी पक्का करने का अपना कमिटमेंट दोहराया। यह फैसला बाहरी जोखिमों और अस्थिर ग्लोबल मार्केट के सामने भारत के समझदारी भरे मैक्रोइकोनॉमिक मैनेजमेंट को दिखाता है।

जम्मू और कश्मीर बैंक ने फिनेकल इनोवेशन अवार्ड 2026 जीता

- जम्मू और कश्मीर बैंक को फिनेकल इनोवेशन अवार्ड्स 2026 में गोल्ड अवार्ड मिला। यह अवार्ड AI-पावर्ड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म बनाने के लिए दिया गया है, जो मशीन लर्निंग, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और बिज़नेस इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करता है। यह प्लेटफॉर्म बैंक को कस्टमर इनसाइट्स को बेहतर बनाने, फ्रॉड डिटेक्शन को मज़बूत करने, रिस्क मैनेजमेंट को बेहतर बनाने और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज़ करने में मदद करता है। यह पहचान डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और कस्टमर-सेंट्रिक बैंकिंग सर्विस देने के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को अपनाने के बैंक के कमिटमेंट को दिखाती है।

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर \$682.32 बिलियन हुआ

- भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व बढ़कर \$682.32 बिलियन हो गया, जिसका मुख्य कारण गोल्ड रिज़र्व में गिरावट के बावजूद फॉरेन करेंसी एसेट्स में बढ़ोतरी है। बड़ा रिज़र्व पोज़िशन बाहरी झटकों को मैनेज करने, ग्लोबल उतार-चढ़ाव के दौरान रुपये को स्थिर करने, इम्पोर्ट को फाइनेंस करने और इन्वेस्टर का भरोसा बनाए रखने की भारत की क्षमता को मज़बूत करता है। यह देश की मैक्रोइकोनॉमिक स्थिरता को भी बढ़ाता है और जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताओं और ग्लोबल कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के खिलाफ एक मज़बूत बफर देता है।

भारत का 2031 तक 30 बिलियन डॉलर के सीफूड एक्सपोर्ट का लक्ष्य

- भारत सरकार ने 2031 तक सीफूड एक्सपोर्ट को \$8.5 बिलियन से बढ़ाकर \$30 बिलियन करने का एक बड़ा टारगेट रखा है। इस स्ट्रेटेजी में वैल्यू एडिशन, बेहतर प्रोसेसिंग फैसिलिटी, क्वालिटी सर्टिफिकेशन, ब्रांडिंग, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर और प्रोजन थ्रिम्प जैसे हाई-वैल्यू प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर फोकस है। इस पहल का मकसद मछुआरों, एक्वाकल्चर किसानों और सीफूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की इनकम बढ़ाते हुए भारत की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना है।

भारत ने Q4 FY26 में चालू खाता अधिशेष दर्ज किया

- FY26 की चौथी तिमाही में भारत ने \$7.1 बिलियन (GDP का 0.7%) का करंट अकाउंट सरप्लस दर्ज किया। यह सुधार मुख्य रूप से सर्विसेज़ एक्सपोर्ट में मज़बूत ग्रोथ की वजह से हुआ, जिससे \$60.4 बिलियन की नेट रिसीट हुई, और विदेश में रहने वाले भारतीयों से \$43.5 बिलियन का रिकॉर्ड इनवर्ड रेमिटेन्स आया। \$83.4 बिलियन के मर्चेन्डाइज़ ट्रेड डेफिसिट के बावजूद, देश का ओवरऑल बैलेंस ऑफ़ पेमेंट्स (BoP) सरप्लस में रहा, जो भारत के एक्सटर्नल सेक्टर की मज़बूती को दिखाता है।

भारत-नेपाल ने क्रॉस-बॉर्डर यूपीआई रेमिटेन्स सर्विस शुरू की

- भारत और नेपाल ने मिलकर भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) को नेपाल के नेशनल पेमेंट्स इंटरफ़ेस (NPI) से जोड़कर एक क्रॉस-बॉर्डर रेमिटेन्स सर्विस शुरू की है। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) और नेपाल क्लियरिंग हाउस लिमिटेड (NCHL) की बनाई यह सर्विस दोनों देशों के बीच तुरंत, सुरक्षित और कम लागत में पैसे ट्रांसफर करने में मदद करती है। इस पहल से प्रवासी मज़दूरों, टूरिस्ट, स्टूडेंट्स और बिज़नेस को फ़ायदा होने की उम्मीद है, साथ ही इससे रीजनल फ़ाइनेंशियल इंटीग्रेशन भी मज़बूत होगा।

संजय लोहिया RBI और SBI बोर्ड में नियुक्त

- सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ़ फ़ाइनेंशियल सर्विसेज़ (DFS) के सेक्रेटरी संजय लोहिया को रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) और स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) के बोर्ड में डायरेक्टर बनाया है। 1994 बैच के IAS ऑफिसर लोहिया ने RBI सेंट्रल बोर्ड में नागराजू महिराला की जगह ली है। उनके अपॉइंटमेंट से सरकार और खास फ़ाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच कोऑर्डिनेशन मज़बूत होने की उम्मीद है, साथ ही बैंकिंग रिफॉर्म, फ़ाइनेंशियल इनक्लूजन और भारत के फ़ाइनेंशियल सेक्टर के मॉडर्नाइज़ेशन को भी सपोर्ट मिलेगा।

वर्ल्ड बैंक ने भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया

- वर्ल्ड बैंक ने भारत के GDP ग्रोथ के अनुमान को FY2026-27 के लिए 6.6% और FY2027-28 के लिए 7.2% तक बढ़ा दिया है। इसमें मज़बूत घरेलू डिमांड, ग्रामीण खपत में सुधार, शहरी खर्च में बढ़ोतरी और विदेशी निवेश में बढ़ोतरी का हवाला दिया गया है। रिपोर्ट में यूरॉपियन यूनियन, ओमान और न्यूज़ीलैंड जैसे देशों के साथ चल रही ट्रेड बातचीत पर भी ज़ोर दिया गया है, जिनसे ग्लोबल आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद एक्सपोर्ट बढ़ने और और निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है।

भारत की CPI महंगाई दर बढ़कर 3.93% हुई

- भारत का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) महंगाई बढ़कर 3.93% हो गई , जिसका मुख्य कारण खाने की चीजों, खासकर टमाटर और अदरक की ज़्यादा कीमतें और साथ ही फ्यूल की बढ़ती कीमतें थीं। सप्लाई साइड की चुनौतियों और कंजम्पशन पैटर्न की वजह से गांव की महंगाई शहरी महंगाई से ज़्यादा रही। हालांकि महंगाई RBI के टारगेट रेंज में रही, लेकिन खाने और एनर्जी की कीमतों पर करीबी नज़र रखी जा रही है क्योंकि इनका घरेलू खर्च पर असर पड़ता है।

डिजिटल वॉलेट डाउनलोड में भारत दुनिया में सबसे आगे

- 2025 तक डिजिटल वॉलेट डाउनलोड में भारत दुनिया भर में पहले नंबर पर रहा, जिसमें 440 मिलियन से ज़्यादा ऐप डाउनलोड हुए। PhonePe, Paytm और BHIM जैसे प्लेटफॉर्म का मार्केट पर दबदबा बना रहा, जबकि UPI ने साल के दौरान ₹299.7 ट्रिलियन के 228.5 बिलियन से ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन प्रोसेस किए। यह कामयाबी डिजिटल पेमेंट, फिनटेक इनोवेशन और फाइनेंशियल इनक्लूजन में भारत की लीडरशिप दिखाती है।

भारत ने नई थोक मूल्य सूचकांक श्रृंखला पेश की

- सरकार ने 2022-23 को नया बेस ईयर बनाकर एक रिवाइज्ड होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI) पेश किया है, जो पहले की 2011-12 सीरीज़ की जगह लेगा। अपडेटेड इंडेक्स कमोडिटी बास्केट को 697 से बढ़ाकर 957 आइटम कर देता है और महंगाई को बेहतर तरीके से मापने के लिए प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (PPIs) भी पेश करता है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे नए सेक्टर भी शामिल किए गए हैं, जिससे यह इंडेक्स भारत की बदलती इकॉनमी को और अच्छे से दिखाता है।

RBI ने NRI और OCI के लिए निवेश के नियम आसान किए

- रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने नॉन-रेसिडेंट इंडियंस (NRIs), ओवरसीज़ सिटिज़न्स ऑफ़ इंडिया (OCIs), और दूसरे विदेशी इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को आसान बनाने के लिए डेज़िग्रेटेड रिपैट्रिबल रुपया अकाउंट्स शुरू किए हैं। इन सुधारों से कम्प्लायंस की ज़रूरतें कम होती हैं, डिविडेंड और बिक्री से होने वाली कमाई आसान होती है, फंड वापस लाना आसान होता है, और FEMA रेगुलेशंस के तहत इन्वेस्टमेंट के मौके बढ़ते हैं। इस पहल से भारत के कैपिटल मार्केट में ज़्यादा विदेशी इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है।

CAG ने राजकोषीय घाटे की चिंता जताई

- कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (CAG) की एक रिपोर्ट से पता चला है कि FY25 के दौरान 28 में से 18 राज्यों ने तय 3% फिस्कल डेफिसिट की लिमिट पार कर ली। सैलरी, पेंशन, सब्सिडी और इंटरेस्ट पेमेंट पर बढ़ते खर्च की वजह से उधार लेने की ज़रूरतें बढ़ गईं। रिपोर्ट में लंबे समय तक फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी पक्का करने के लिए फिस्कल डिस्प्लिन, सब्सिडी को सही बनाने, बेहतर रेवेन्यू जेनरेशन और समझदारी भरे खर्च मैनेजमेंट की ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया।

सर्वम एआई यूनिफॉर्म क्लब में शामिल

- बंगलुरु का स्टार्टअप सर्वम AI, सीरीज़-B फंडिंग राउंड में \$234 मिलियन जुटाने के बाद यूनिफॉर्म बन गया , जिससे इसकी वैल्यूएशन लगभग \$1.5 बिलियन हो गई। 2023 में शुरू हुई यह कंपनी भारत की कई भाषाओं वाली और एंटरप्राइज़ ज़रूरतों के हिसाब से सॉल्यूशन सांल्यूशन बनाती है। नई फंडिंग का इस्तेमाल एडवांस्ड AI मॉडल, कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और एंटरप्राइज़ AI प्रोडक्ट बनाने में किया जाएगा, जिससे भारत का बढ़ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम मज़बूत होगा।

भारत का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 14.64% बढ़ा

- भारत का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन साल-दर-साल 14.64% बढ़कर ₹5.21 ट्रिलियन हो गया। यह ग्रोथ ज़्यादा कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन, बेहतर एडवांस टैक्स पेमेंट, मज़बूत बिज़नेस प्रॉफिटेबिलिटी और बेहतर टैक्स कम्प्लायंस की वजह से हुई। मज़बूत कलेक्शन से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था लगातार फॉर्मल हो रही है और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतर एफिशिएंसी हो रही है।

RBI ने श्री महालक्ष्मी अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक का लाइसेंस रद्द किया

- रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने कर्नाटक में श्री महालक्ष्मी अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक का बैंकिंग लाइसेंस खराब फाइनेंशियल हालत, कैपिटल की कमी और डिपॉजिटर्स को पैसे वापस न कर पाने की वजह से कैंसिल कर दिया है। लगभग 97.9% डिपॉजिटर्स को डिपॉजिट इश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) इश्योरेंस स्कीम के तहत ₹5 लाख तक के डिपॉजिट मिलने की उम्मीद है , जिससे छोटे डिपॉजिटर्स की सुरक्षा पक्की होगी।

एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत के प्राइवेट सेक्टर में करीब \$1 बिलियन का निवेश करेगा

- एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने 2026 के दौरान भारत के प्राइवेट सेक्टर में लगभग \$1 बिलियन इन्वेस्ट करने के प्लान की घोषणा की है, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, शहरी ट्रांसपोर्ट, हेल्थकेयर, फाइनेंशियल सर्विसेज़ और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज़ किया जा सके। इस इन्वेस्टमेंट का मकसद और प्राइवेट कैपिटल जुटाना, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना और भारत के लॉन्ग-टर्म डेवलपमेंट गोल्ल्स को सपोर्ट करना है। ADB ने क्लाइमेट रेजिलिएंस को मज़बूत करने और देश भर में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के अपने कमिटमेंट को भी दोहराया।

चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को नवरत्न का दर्जा दिया गया

- भारत सरकार ने चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CPCL) को नवरत्न का दर्जा दिया है , जिससे यह भारत के लीडिंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज (CPSEs) में से एक बन गया है। अपग्रेडेड स्टेट्स से कंपनी को ज़्यादा फाइनेंशियल और ऑपरेशनल ऑटोनॉमी मिलती है, जिससे कंपनी बड़े इन्वेस्टमेंट कर सकती है, जॉइंट वेंचर बना सकती है, विदेश में सब्सिडियरी बना सकती है, और बिना सरकार की पहले से मंजूरी के स्ट्रेटेजिक बिज़नेस फैसले ले सकती है। इस पहचान से पेट्रोलियम और एनर्जी सेक्टर में CPCL की कॉम्पिटिटिवनेस और मज़बूत होने की उम्मीद है।

सेबी ने अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के लिए गरुड़ फ्रेमवर्क लॉन्च किया

- सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया (SEBI) ने अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड (AIF) इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए **GARUDA (गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, रिपोर्टिंग, यूनिफॉर्मिटी, डिस्कलोजर और ऑडिट)** फ्रेमवर्क पेश किया है। यह फ्रेमवर्क रिपोर्टिंग की ज़रूरतों को स्टैंडर्ड बनाता है, डिस्कलोजर के नियमों को मज़बूत करता है, इन्वेस्टर की सुरक्षा बढ़ाता है, और बेहतर रिस्क मैनेजमेंट तरीकों को बढ़ावा देता है। यह भारत के अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी को बढ़ावा देते हुए रेगुलेटरी निगरानी को भी बेहतर बनाने की कोशिश करता है।

RBI ने डिजिटल फ्राँड कंपनसेशन फ्रेमवर्क पेश किया

- रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने बिना इजाज़त वाले डिजिटल बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन के खिलाफ़ कस्टमर की सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए एक नया **डिजिटल फ्राँड कंपनसेशन फ्रेमवर्क** पेश किया है। बदली हुई गाइडलाइंस के तहत, बैंकों और रेगुलेटेड संस्थाओं को शिकायत मुलझाने का तेज़ सिस्टम बनाना होगा और डिजिटल फ्राँड के योग्य पीड़ितों को समय पर मुआवज़ा देना होगा। इस फ्रेमवर्क में साइबर सिक्योरिटी के मज़बूत उपाय, रियल-टाइम फ्राँड मॉनिटरिंग और साइबर से जुड़े फाइनेंशियल रिस्क को कम करने के लिए कस्टमर की जागरूकता बढ़ाना भी ज़रूरी है।

BHIM ऐप ने UPI ट्रांज़ैक्शन में 206% से ज़्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की

- BHIM (भारत इंटरफ़ेस फ़ॉर मनी) एप्लिकेशन ने **FY2025-26** के दौरान **ट्रांज़ैक्शन वॉल्यूम में साल-दर-साल 206%** की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की। यह बढ़ोतरी ग्रामीण और सेमी-अर्बन इलाकों में UPI पेमेंट को ज़्यादा अपनाने, मर्चेंट की मंजूरी बढ़ने और डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की वजह से हुई। BHIM की लगातार सफलता देश भर में फाइनेंशियल इनक्लूजन, डिजिटल पेमेंट और कैशलेस ट्रांज़ैक्शन को बढ़ावा देने की सरकार की कोशिशों को दिखाती है।

RBI ने HDFC बैंक के अंतरिम चेयरमैन के तौर पर केकी मिश्री का कार्यकाल बढ़ाया

- रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने **HDFC बैंक के पार्ट-टाइम चेयरमैन के तौर पर केकी मिश्री का कार्यकाल बढ़ाने को मंजूरी दे दी है।** यह एक्सटेंशन लीडरशिप में निरंतरता पक्का करता है, जबकि HDFC लिमिटेड के HDFC बैंक में मर्जर के बाद बैंक अपने मर्जर के बाद के इंटीग्रेशन को जारी रखता है। उनके नेतृत्व में, बैंक से गवर्नेंस को मज़बूत करने, डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को बढ़ाने, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार करने और मज़बूत कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड बनाए रखने पर ध्यान देने की उम्मीद है।

RBI ने किसान क्रेडिट कार्ड गाइडलाइंस में बदलाव किया

- रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने किसानों, डेयरी किसानों, मछली पालन और खेती से जुड़े कामों के लिए क्रेडिट एक्सेस को बेहतर बनाने के लिए **किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)** स्कीम के लिए ऑपरेशनल गाइडलाइंस में बदलाव किया है। बदले हुए नियम लोन प्रोसेसिंग को आसान बनाते हैं, ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा फाइनेंशियल इन्क्लूजन को बढ़ावा देते हैं, और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट समय पर मिलने में मदद करते हैं। इस पहल से किसानों की इनफॉर्मल साहूकारों पर निर्भरता कम होने और खेती की प्रोडक्टिविटी बढ़ने की उम्मीद है।

RBI ने NBFCs के लिए स्केल-बेस्ड रेगुलेशन फ्रेमवर्क में बदलाव किया

- रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने **नॉन-बैंकिंग फ़ाइनेंशियल कंपनियों (NBFCs) के लिए स्केल-बेस्ड रेगुलेशन (SBR)** फ्रेमवर्क को अपडेट किया है ताकि फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मज़बूत किया जा सके और रिस्क मैनेजमेंट को बेहतर बनाया जा सके। बदले हुए फ्रेमवर्क में NBFCs के साइज़ और रिस्क प्रोफ़ाइल के आधार पर सख्त गवर्नेंस नियम, बेहतर डिस्कलोजर ज़रूरतें, बेहतर कैपिटल एडिक्विसी स्टैंडर्ड और मज़बूत सुपरवाइज़री सिस्टम शामिल हैं। इस कदम का मकसद एक ज़्यादा मज़बूत और ट्रांसपेरेंट नॉन-बैंकिंग फ़ाइनेंशियल सेक्टर बनाना है।

RBI ने वेरिएबल रेट रेपो नीलामी के ज़रिए ₹1.41 लाख करोड़ डाले

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने कुछ समय के लिए लिक्विडिटी की कमी को दूर करने के लिए **वेरिएबल रेट रेपो (VRR) नीलामी** के ज़रिए बैंकिंग सिस्टम में **₹1.41 लाख करोड़ डाले**। लिक्विडिटी डालने का मकसद बैंकिंग सिस्टम में फंड की काफ़ी उपलब्धता पक्का करना, शॉर्ट-टर्म इंटररेस्ट रेट को स्थिर करना और बिज़नेस और कंज्यूमर को आसानी से क्रेडिट फ्लो में मदद करना था। ऐसे ऑपरेशन फाइनेंशियल मार्केट में स्थिरता बनाए रखने के लिए RBI की लिक्विडिटी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी का हिस्सा है।

आरईसी लिमिटेड का पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ विलय होगा

- सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए एक मज़बूत पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए **REC लिमिटेड के पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (PFC)** के साथ मर्जर को मंजूरी दे दी है। इस मर्जर से ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार, लागत में कमी, लोन देने की क्षमता में बढ़ोतरी और भारत के पावर, रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए फाइनेंसिंग सपोर्ट को मज़बूत करने की उम्मीद है। यह मिली-जुली कंपनी बड़े पैमाने पर एनर्जी ट्रांज़िशन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लक्ष्यों को सपोर्ट करने में अहम भूमिका निभाएगी।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा जहाज रीसाइक्लिंग देश बन गया है

- भारत दुनिया का सबसे बड़ा शिप रीसाइक्लिंग देश बन गया है, जिसने **मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030** के तहत तय समय से पांच साल पहले ही टारगेट हासिल कर लिया है। शिप रीसाइक्लिंग की बड़ी एक्टिविटी गुजरात के **अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड में होती है**, जिसने एनवायरनमेंट के हिसाब से सस्टेनेबल और ग्लोबली कम्प्लायंट रीसाइक्लिंग तरीकों को अपनाया है। यह कामयाबी ग्लोबल मैरीटाइम सेक्टर में भारत की जगह को मज़बूत करती है, साथ ही रिसोर्स रिकवरी, रोज़गार पैदा करने और सर्कुलर इकॉनमी के सिद्धांतों को बढ़ावा देती है।

भारत ने ग्रीन रेवेन्यू में US\$110 बिलियन का योगदान दिया

- **लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप (LSEG)** के अनुसार, भारत ने 2025 के दौरान लगभग **US\$110 बिलियन** का ग्रीन रेवेन्यू कमाया, जिससे वह सस्टेनेबल बिज़नेस एक्टिविटीज़ में दुनिया के लीडिंग देशों में शामिल हो गया। रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, क्लीन टेक्नोलॉजी, वेस्ट मैनेजमेंट और एनर्जी-एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग बड़े योगदान देने वाले के तौर पर उभरे। रिपोर्ट में ग्लोबल ग्रीन इकॉनमी में भारत की बढ़ती भूमिका और क्लाइमेट गोल्व और नेट-ज़ीरो एमिशन को पाने के उसके कमिटमेंट पर ज़ोर दिया गया है।

भारत का व्यापार पैटर्न एशिया और अफ्रीका की ओर बदल रहा है

- हाल के ट्रेड डेटा से पता चलता है कि भारत का मर्चेंडाइज़ एक्सपोर्ट तेज़ी से एशिया, अफ्रीका और उभरते बाज़ारों की ओर बढ़ रहा है, जिससे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जैसे पारंपरिक बाज़ारों पर निर्भरता कम हो रही है। इस डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ते ट्रेड एग्रीमेंट, मज़बूत रीजनल पार्टनरशिप और इंजीनियरिंग सामान, फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और खेती-बाड़ी की चीज़ों के बढ़ते एक्सपोर्ट से सपोर्ट मिला है। इस बदलाव से एक्सपोर्ट रेजिलिएंस में सुधार होने और भारत की ग्लोबल ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस मज़बूत होने की उम्मीद है।

नीति आयोग ने 8वीं ट्रेड वॉच तिमाही रिपोर्ट जारी की

- नीति आयोग ने ट्रेड वॉच क्वार्टरली का 8वां एडिशन जारी किया है, जिसमें भारत के इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, इम्पोर्ट पर निर्भरता और उभरते ग्लोबल मार्केट के मौकों के ट्रेड्स पर रोशनी डाली गई है। रिपोर्ट में मैनुफैक्चरिंग एक्सपोर्ट बढ़ाने, लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी में सुधार, सप्लाइ चेन को मज़बूत करने और भारत के

लॉन्ग-टर्म एक्सपोर्ट टारगेट को पाने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTAs) का फायदा उठाने के महत्व पर जोर दिया गया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी इन्फ्रस्ट्रक्चर, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग जैसे हाई एक्सपोर्ट पोटेन्शियल वाले सेक्टरों की भी पहचान की गई है।

भारत का बैंकिंग सेक्टर लगातार मज़बूत हो रहा है

- भारत के बैंकिंग सेक्टर ने FY2025-26 के दौरान मज़बूत फ़ाइनेंशियल लचीलापन दिखाना जारी रखा, जिसे बेहतर एसेट क्वालिटी, ज़्यादा प्रॉफ़िट, मज़बूत कैपिटल एडिक्वेंसी और लगातार क्रेडिट ग्रोथ से सपोर्ट मिला। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों ने अच्छी कमाई बताई, जबकि डिजिटल बैंकिंग सर्विस में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई। RBI द्वारा लगातार रेगुलेटरी सुधार, मज़बूत कॉर्पोरेट गवर्नेंस और फ़ाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को ज़्यादा अपनाने से भारत के बैंकिंग इकोसिस्टम की स्थिरता और कॉम्पिटिटिवनेस और मज़बूत हुई है।

अर्थव्यवस्था और व्यापार**अर्थव्यवस्था समाचार****भारत की अर्थव्यवस्था Q4 FY26 में 7.8% बढ़ी; FY26 की ग्रोथ संशोधित होकर 7.7% हुई**

- भारत की इकॉनमी ने FY2025-26 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) में मैनुफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, फ़ाइनेंशियल सर्विसेज़ और एग्रीकल्चर में मज़बूत परफॉर्मेंस की वजह से 7.8% की मज़बूत GDP ग्रोथ दर्ज की। इसके साथ ही, FY2025-26 के लिए देश की कुल GDP ग्रोथ को बढ़ाकर 7.7% कर दिया गया, जिससे भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बड़ी इकॉनमी में से एक बन गया। ज़्यादा सरकारी कैपिटल खर्च, मज़बूत घरेलू खपत, सर्विसेज़ का बढ़ता एक्सपोर्ट और बेहतर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी ने इकॉनमिक विस्तार में अहम योगदान दिया। यह मज़बूत ग्रोथ जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताओं और ग्लोबल इकॉनमिक मंदी के बावजूद एक अहम ग्लोबल ग्रोथ इंजन के तौर पर भारत की स्थिति को मज़बूत करती है।

वर्ल्ड बैंक ने भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया

- वर्ल्ड बैंक ने मज़बूत घरेलू मांग, बढ़ते पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हवाला देते हुए, FY2026-27 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.6% और FY2027-28 के लिए 7.2% कर दिया है। रिपोर्ट में ग्लोबल आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत की मज़बूती पर जोर दिया गया है और इस बात पर जोर दिया गया है कि लगातार स्ट्रक्चरल सुधार, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और मैनुफैक्चरिंग में बढ़ोतरी से लंबे समय तक आर्थिक ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। वर्ल्ड बैंक ने यह भी कहा कि भारत दुनिया भर में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है।

फिच रेटिंग्स ने भारत के ग्रोथ आउटलुक में बदलाव किया

- ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने जियोपॉलिटिकल टेंशन, कच्चे तेल की ज़्यादा कीमतों और ग्लोबल ट्रेड में अनिश्चितताओं का हवाला देते हुए FY2026-27 के लिए भारत के GDP ग्रोथ के अनुमान को बदला है। हालांकि, फिच ने कहा कि मज़बूत घरेलू डिमांड, बैंकिंग सेक्टर की बेहतर सेहत, सरकारी कैपिटल खर्च और बढ़ते इन्वेस्टमेंट की वजह से भारत की इकॉनमी काफ़ी मज़बूत बनी हुई है। एजेंसी ने बाहरी चुनौतियों के बावजूद भारत के स्थिर मैक्रोइकॉनॉमिक फंडामेंटल्स और हेल्दी फिस्कल मैनेजमेंट पर भी जोर दिया।

एसएंडपी ग्लोबल ने मज़बूत आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया

- S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने अनुमान लगाया है कि FY2026-27 में भारत की GDP 6.6% की दर से बढ़ेगी, जिसे मज़बूत घरेलू खपत, बेहतर इन्वेस्टमेंट माहौल, बैंकिंग सेक्टर का अच्छा परफॉर्मेंस और सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च का सपोर्ट मिलेगा। एजेंसी ने कहा कि कई एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में एक्सपोर्ट पर भारत की तुलनात्मक रूप से कम निर्भरता ग्लोबल आर्थिक उतार-चढ़ाव से सुरक्षा देती है। लगातार सुधार, डिजिटलाइज़ेशन और बढ़ती मैनुफैक्चरिंग एक्टिविटी से लंबे समय तक ग्रोथ बनी रहने की उम्मीद है।

जीएसटी संग्रह ₹1.94 लाख करोड़ पर पहुंचा

- भारत का गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (GST) कलेक्शन मई 2026 में ₹1.94 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो बेहतर टैक्स कम्प्लायंस, बढ़ती घरेलू खपत और ज़्यादा इकॉनॉमिक एक्टिविटी को दिखाता है। GST रेवेन्यू में बढ़ोतरी को बढ़े हुए इंपोर्ट, मैनुफैक्चरिंग और सर्विसेज़ में बढ़ोतरी और मज़बूत डिजिटल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन से सपोर्ट मिला। ज़्यादा कलेक्शन से सरकार की फिस्कल हालत बेहतर होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और वेलफेयर प्रोग्राम के लिए ज़्यादा रिसोर्स मिलते हैं।

उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति बढ़कर 3.93% हुई

- भारत का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) इन्फ्लेशन बढ़कर 3.93% हो गया, जिसका मुख्य कारण खाने की चीजों, खासकर सब्जियों और दालों की ज़्यादा कीमतें और फ्यूल की बढ़ी हुई कीमतें थीं। हालांकि इन्फ्लेशन रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के टारगेट रेंज में रहा, लेकिन पॉलिसी बनाने वाले खाने की इन्फ्लेशन और ग्लोबल कच्चे तेल की कीमतों पर करीब से नज़र रख रहे हैं। स्थिर इन्फ्लेशन कंज्यूमर की खरीदने की ताकत को सपोर्ट करता है, जबकि RBI को मॉनेटरी पॉलिसी के फैसलों में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है।

सरकार ने नई थोक मूल्य सूचकांक श्रृंखला पेश की

- सरकार ने 2022-23 को नया बेस ईयर बनाकर एक रिवाइज़्ड होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI) पेश किया है, जो पिछली 2011-12 सीरीज़ की जगह लेगा। अपडेटेड इंडेक्स में कमोडिटी बास्केट को 697 से बढ़ाकर 957 आइटम कर दिया गया है और इसमें रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे उभरते हुए सेक्टर शामिल हैं। यह बदलाव होलसेल महंगाई का ज़्यादा सही माप देता है और भारत की अर्थव्यवस्था में स्ट्रक्चरल बदलावों को दिखाता है।

भारत का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 14.64% बढ़ा

- FY2026-27 की पहली तिमाही में भारत का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 14.64% बढ़कर ₹5.21 लाख करोड़ हो गया। यह बढ़ोतरी ज़्यादा कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन, एडवांस टैक्स पेमेंट और टैक्सपेयर्स के बीच बेहतर कम्प्लायंस की वजह से हुई। यह बढ़ोतरी मज़बूत कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी, इकॉनमी के बढ़ते फॉर्मलाइज़ेशन और डिजिटल पहलों के ज़रिए टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की बेहतर एफिशिएंसी को दिखाती है।

भारत ने चालू खाता अधिशेष दर्ज किया

- भारत ने FY2025-26 की चौथी तिमाही में \$7.1 बिलियन (GDP का 0.7%) का करंट अकाउंट सरप्लस दर्ज किया। यह सरप्लस मुख्य रूप से रिकॉर्ड सर्विस एक्सपोर्ट, ज़्यादा सॉफ्टवेयर कमाई और विदेश में रहने वाले भारतीयों से आने वाले अच्छे रेमिटेंस की वजह से हुआ। बड़े मर्चेडाइज़ ट्रेड घाटे के बावजूद, सर्विस एक्सपोर्ट में अच्छी ग्रोथ और बढ़ते फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो की वजह से भारत का एक्सटर्नल सेक्टर मज़बूत बना रहा।

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर \$682.32 बिलियन हुआ

- भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व बढ़कर \$682.32 बिलियन हो गया, जो ग्लोबल फाइनेंशियल उतार-चढ़ाव और बाहरी आर्थिक झटकों के खिलाफ एक मज़बूत बफर देता है। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से गोल्ड रिज़र्व में उतार-चढ़ाव के बावजूद ज़्यादा फॉरेन करेंसी एसेट्स की वजह से हुई। बड़े फॉरेक्स रिज़र्व भारतीय रुपये को मज़बूत करते हैं, इन्वेंस्टर का भरोसा बढ़ाते हैं, इंपोर्ट फाइनेंसिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं, और ग्लोबल अनिश्चितता के समय में स्थिरता देते हैं।

भारत दुनिया की पांचवीं सबसे ज़्यादा डिजिटल अर्थव्यवस्था बन गया है

- SIDE 2026 रिपोर्ट के अनुसार, भारत दुनिया की पांचवीं सबसे ज़्यादा डिजिटल अर्थव्यवस्था बन गया है, जो पिछले साल के आठवें स्थान से बेहतर है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और डिजिटल गवर्नेंस में देश के तेज़ी से विस्तार ने रैंकिंग में सुधार में योगदान दिया। भारत ने AI रेडीनेस में भी

दुनिया भर में चौथा स्थान हासिल किया, जो डिजिटल इनोवेशन में इसकी बढ़ती लीडरशिप को दिखाता है।

डिजिटल वॉलेट डाउनलोड में भारत दुनिया में सबसे आगे

- भारत दुनिया भर में पहले नंबर पर रहा, जिसके 440 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हुए। यह बढ़ोतरी PhonePe, Google Pay, Paytm और BHIM जैसे UPI-इनेबल्ड एप्लिकेशन के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल से हुई। यह कामयाबी डिजिटल पेमेंट को अपनाने, फाइनेंशियल इन्क्लूजन और डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस में ग्लोबल लीडर के तौर पर भारत के उभरने को दिखाती है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 4.9% बढ़ा

- भारत के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स (IIP) ने अप्रैल 2026 में 4.9% की ग्रोथ दर्ज की, जिसमें मज़बूत मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, माइनिंग एक्टिविटी और बिजली उत्पादन का हाथ रहा। सरकार ने 2022-23 को बेस ईयर मानकर एक रिवाइज़्ड IIP सीरीज़ भी शुरू की, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी इन्फ्रामेंट, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, मेडिकल डिवाइस और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी नई इंडस्ट्रीज़ को शामिल किया गया। रिवाइज़्ड इंडेक्स भारत की बदलती इंडस्ट्रियल इकॉनमी की ज़्यादा अच्छी तस्वीर दिखाता है।

सरकार ने जिला घरेलू उत्पाद दिशानिर्देश जारी किए

- मिनिस्ट्री ऑफ़ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन (MoSPI) ने 2022-23 को बेस ईयर मानकर डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (DDP) का अनुमान लगाने के लिए नेशनल गाइडलाइंस जारी की हैं। यह फ्रेमवर्क सभी जिलों में ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GDDP), नेट डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (NDDP), और पर कैपिटा इनकम के कैलकुलेशन को स्टैंडर्ड बनाता है। यह पहल डिस्ट्रिक्ट-लेवल प्लानिंग को मज़बूत करेगी, पॉलिसी बनाने में सुधार करेगी, और बैलेंस्ड रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करेगी।

भारत ने ग्रीन रेवेन्यू में US\$110 बिलियन का योगदान दिया

- लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप (LSEG) के अनुसार, भारत ने 2025 के दौरान लगभग US\$110 बिलियन का ग्रीन रेवेन्यू कमाया, जिससे यह दुनिया की लीडिंग ग्रीन इकॉनमी में से एक बन गया। रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, क्लीन टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग और वेस्ट मैनेजमेंट इसमें बड़े योगदान देने वाले रहे। यह रिपोर्ट क्लाइमेट एक्शन, क्लीन एनर्जी ट्रांज़िशन और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भारत के बढ़ते कमिटमेंट को दिखाती है।

भारत का व्यापार पैटर्न एशिया और अफ्रीका की ओर बदल रहा है

- भारत की एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी तेज़ी से एशिया, अफ्रीका और उभरते हुए मार्केट की ओर शिफ्ट हो गई, जिससे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जैसे पारंपरिक मार्केट पर निर्भरता कम हो गई। इंजीनियरिंग सामान, फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स और खेती-बाड़ी की चीजों के बढ़ते एक्सपोर्ट ने इस डाइवर्सिफिकेशन को सपोर्ट किया। बदलते ट्रेड पैटर्न से एक्सपोर्ट रेजिलिएंस में सुधार, सप्लाइ चैन मज़बूत होने और तेज़ी से बढ़ रहे ग्लोबल मार्केट में भारत की मौजूदगी बढ़ने की उम्मीद है।

नीति आयोग ने 8वीं ट्रेड वॉच तिमाही रिपोर्ट जारी की

- नीति आयोग ने ट्रेड वॉच क्वार्टरली का 8वां एडिशन जारी किया, जिसमें भारत के एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ट्रेड एग्रीमेंट और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के खास ट्रेंड्स पर रोशनी डाली गई। रिपोर्ट में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट को मजबूत करने, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTAs) को बढ़ाने और इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी इन्फ्रामेंट और फूड प्रोसेसिंग जैसे हाई-वैल्यू सेक्टर को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। इसमें भारत को अपने लॉन्ग-टर्म एक्सपोर्ट और इकोनॉमिक ग्रोथ टारगेट हासिल करने में मदद करने के लिए स्ट्रेटेजी भी बताई गई।

CAG ने राज्यों में बढ़ते राजकोषीय घाटे की ओर इशारा किया

- कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (CAG) ने बताया कि FY2024-25 के दौरान 18 राज्यों ने ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GSDP) के 3% की सुझाई गई फिस्कल डेफिसिट लिमिट को पार कर लिया। सैलरी, पेंशन, सब्सिडी और इंटरेस्ट पेमेंट पर बढ़ते खर्च की वजह से उधार लेने की ज़रूरतें बढ़ गईं। रिपोर्ट में सस्टेनेबल पब्लिक फाइनेंस और लंबे समय तक आर्थिक स्थिरता पक्का करने के लिए फिस्कल डिसिप्लिन, अच्छे खर्च मैनेजमेंट और बेहतर रेवेन्यू जुटाने की अहमियत पर ज़ोर दिया गया।

व्यापार समाचार**MSMEs को कैपिटल जुटाने में मदद के लिए प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया गया**

- मीशो ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के साथ मिलकर प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया है। इसका मकसद माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) और डिजिटल-फर्स्ट बिजनेस को कैपिटल मार्केट तक पहुंचने में मदद करना है। यह पहल BSE SME प्लेटफॉर्म के लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रेगुलेटरी कंप्लायंस और लिस्टिंग प्रोसेस पर गाइडेंस देती है। पब्लिक लिस्टिंग के लिए एलिजिबल बिजनेस को तैयार करके, प्रोजेक्ट शिखर का मकसद लॉन्ग-टर्म कैपिटल तक पहुंच को बेहतर बनाना, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना, इन्वेस्टर का भरोसा मजबूत करना और भारत के स्टार्टअप और MSME इकोसिस्टम की ग्रोथ को तेज करना है।

भारत ने अब तक का सबसे ज्यादा सीफूड एक्सपोर्ट रिकॉर्ड किया

- भारत ने FY2025-26 के दौरान ₹73,890 करोड़ (लगभग US\$8.78 बिलियन) कीमत के 19.72 लाख मीट्रिक टन समुद्री प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करके अब तक का सबसे ज्यादा सीफूड एक्सपोर्ट किया। फ्रोज़न थ्रिम्प सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कमोडिटी बनी रही, जिसने एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई में सबसे ज्यादा हिस्सा दिया, जबकि कीमत के हिसाब से अमेरिका और मात्रा के हिसाब से चीन सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बना। यह रिकॉर्ड परफॉर्मेंस ग्लोबल सीफूड मार्केट में भारत की बढ़ती कॉम्पिटिटिवनेस को दिखाता है और रोजगार, विदेशी मुद्रा से होने वाली कमाई और फिशरीज़ सेक्टर से जुड़े लाखों लोगों की रोज़ी-रोटी को सपोर्ट करता है।

भारत ने 2031 तक 30 बिलियन डॉलर के सीफूड एक्सपोर्ट का टारगेट रखा है

- भारत सरकार ने 2031 तक सीफूड एक्सपोर्ट को US\$30 बिलियन तक बढ़ाने का एक बड़ा टारगेट रखा है। इस मकसद को पाने के लिए, सरकार

सस्टेनेबल एक्वाकल्चर को बढ़ाने, सीफूड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न बनाने, वैल्यू-एडेड मरीन प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने, क्वालिटी सर्टिफिकेशन में सुधार करने और कोल्ड-चेन लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने की योजना बना रही है। इस पहल से भारत का ग्लोबल मार्केट शेयर बढ़ने, एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलने, मछुआरों की इनकम बढ़ने और पूरी फिशरीज़ वैल्यू चेन में और रोज़गार पैदा होने की उम्मीद है।

अडानी पोर्ट्स ने अर्जेंटीना LNG मरीन सर्विसेज़ कॉन्ट्रैक्ट जीता

- अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन (APSEZ) को अर्जेंटीना में एक बड़े लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) प्रोजेक्ट के लिए लंबे समय का मरीन सर्विसेज़ कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस एग्रीमेंट के तहत, कंपनी LNG एक्सपोर्ट टर्मिनल के लिए पूरी पोर्ट मैनेजमेंट, पायलटेज, टोवेज और मरीन लॉजिस्टिक्स सर्विसेज़ देगी। यह कॉन्ट्रैक्ट अडानी पोर्ट्स के लगातार ग्लोबल विस्तार को दिखाता है और इंटरनेशनल पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और मेरीटाइम लॉजिस्टिक्स सर्विसेज़ में भारत की मौजूदगी को मजबूत करता है।

आरईसी लिमिटेड का पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ विलय होगा

- सरकार ने REC लिमिटेड के पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (PFC) के साथ मर्जर को मंजूरी दे दी है, जिससे भारत के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन में से एक बन जाएगा। इस मर्जर का मकसद ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार करना, डुप्लिकेशन कम करना, लोन देने की क्षमता बढ़ाना और पावर जेनरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंसिंग सपोर्ट को मजबूत करना है। यह मिली-जुली कंपनी भारत के क्लीन एनर्जी ट्रांज़िशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मदद करने में अहम भूमिका निभाएगी।

सर्वम एआई यूनिकॉर्न बन गया

- बेंगलुरु की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप सर्वम AI ने सीरीज़-B फंडिंग राउंड में US\$234 मिलियन जुटाने के बाद यूनिकॉर्न क्लब में एंट्री की, जिससे इसकी वैल्यूएशन लगभग US\$1.5 बिलियन हो गई। 2023 में शुरू हुई यह कंपनी भारतीय भाषाओं और एंटरप्राइज़ एप्लिकेशन के हिसाब से सॉल्यूशन AI मॉडल बनाने पर फोकस करती है। नए इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल एडवांस्ड AI इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े लैंग्वेज मॉडल और एंटरप्राइज़ AI सॉल्यूशन डेवलप करने के लिए किया जाएगा, जिससे भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन मजबूत होगा।

एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत के प्राइवेट सेक्टर में करीब \$1 बिलियन का निवेश करेगा

- एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने 2026 के दौरान भारत के प्राइवेट सेक्टर में लगभग US\$1 बिलियन इन्वेस्ट करने के प्लान की घोषणा की है। यह इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, हेल्थकेयर, फाइनेंशियल सर्विसेज़, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट-रेसिलिएंट प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करेगा। इस फंडिंग का मकसद और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जुटाना, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना, रोज़गार के मौके बनाना और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को तेज़ करना है, साथ ही इसके नेट-ज़ीरो और क्लाइमेट कमिटमेंट्स को भी सपोर्ट करना है।

चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को नवरत्न का दर्जा दिया गया

- भारत सरकार ने **चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CPCL)** को नवरत्न का दर्जा दिया है, जिससे यह देश के सबसे बड़े सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज (CPSE) में से एक बन गया है। अपग्रेडेड स्टेटस से CPCL को ज्यादा ऑपरेशनल और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलेगी, जिससे वह बड़े इन्वेस्टमेंट कर सकेगी, जॉइंट वेंचर बना सकेगी, विदेश में ऑपरेशन बढ़ा सकेगी, और बिना सरकार की पहले से मंजूरी के स्ट्रेटेजिक बिज़नेस फैसले ले सकेगी। इस कदम से भारत के पेट्रोलियम रिफाइनिंग सेक्टर के मज़बूत होने और कंपनी की कॉम्पिटिटिवनेस में सुधार होने की उम्मीद है।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा जहाज रीसाइक्लिंग देश बन गया है

- भारत दुनिया का सबसे बड़ा शिप रीसाइक्लिंग देश बन गया है, जिसने मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 के तहत तय समय से पांच साल पहले ही टारगेट हासिल कर लिया है। यह कामयाबी काफी हद तक गुजरात के अलंग शिप रीसाइक्लिंग यार्ड की वजह से है, जो दुनिया की सबसे बड़ी शिप-ब्रेकिंग फैसिलिटी में से एक है। एनवायरनमेंट के हिसाब से सस्टेनेबल रीसाइक्लिंग तरीकों को अपनाने, वर्कर सेफ्टी स्टैंडर्ड में सुधार और इंटरनेशनल नियमों के पालन ने ग्लोबल मैरीटाइम रीसाइक्लिंग इंडस्ट्री में भारत की स्थिति को काफी मज़बूत किया है और साथ ही सर्कुलर इकॉनमी को भी बढ़ावा दिया है।

भारत ने ग्रीन रेवेन्यू में US\$110 बिलियन का योगदान दिया

- लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप (LSEG) के अनुसार, भारत ने 2025 के दौरान लगभग **US\$110 बिलियन** का ग्रीन रेवेन्यू जनरेट किया, जिससे यह ग्लोबल ग्रीन इकॉनमी में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले देशों में से एक बन गया। रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, क्लीन टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल मैनुफैक्चरिंग, एनर्जी-एफिशिएंट बिल्डिंग और वेस्ट मैनेजमेंट ग्रीन रेवेन्यू जनरेट करने के मुख्य ड्राइवर के तौर पर उभरे। रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट एक्शन और क्लीन एनर्जी ट्रांज़िशन के लिए भारत के बढ़ते कमिटमेंट पर जोर दिया गया है।

भारत का व्यापार पैटर्न एशिया और अफ्रीका की ओर बदल रहा है

- भारत का मर्चेन्डाइज़ एक्सपोर्ट तेज़ी से एशिया, अफ्रीका और दूसरे उभरते हुए मार्केट की ओर बढ़ रहा है, जिससे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जैसे ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन पर निर्भरता कम हो रही है। इंजीनियरिंग सामान, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, केमिकल्स और खेती-बाड़ी की चीज़ों के बढ़ते एक्सपोर्ट ने इस डाइवर्सिफिकेशन में मदद की है। बदलती ट्रेड स्ट्रेटेजी से एक्सपोर्ट रेजिलिएंस में सुधार, रीजनल ट्रेड पार्टनरशिप मज़बूत होने और ग्लोबल मार्केट में भारत की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ने की उम्मीद है।

कुणाल शाह को मेटा में व्हाट्सएप का ग्लोबल हेड नियुक्त किया गया

- मेटा ने कुणाल शाह को **WhatsApp का ग्लोबल हेड** बनाया है, जिससे कंपनी के सबसे तेज़ी से बढ़ते कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म में से एक में उसकी लीडरशिप मज़बूत होगी। अपने नए रोल में, वह ग्लोबल मार्केट में प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी, बिज़नेस बढ़ाने, यूजर एंगेजमेंट और इनोवेशन को देखेगा। उनका अपॉइंटमेंट दिखाता है कि मेटा WhatsApp के इकोसिस्टम को बढ़ाने पर फोकस कर रहा है, जिसमें बिज़नेस मैसेजिंग, डिजिटल पेमेंट और AI-पावर्ड कम्युनिकेशन सर्विस शामिल हैं।

भारत के कॉर्पोरेट सेक्टर में मज़बूत ग्रोथ की रफ़्तार दिख रही है

- FY2025-26 के दौरान भारत के कॉर्पोरेट सेक्टर में अच्छी ग्रोथ जारी रही, जिसे बढ़ती घरेलू डिमांड, ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, बेहतर कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी और डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाने में बढ़ोतरी से सपोर्ट मिला। मैनुफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विसेज़ और टेक्नोलॉजी सेक्टर में ग्रोथ ने बिज़नेस का भरोसा मज़बूत किया है और घरेलू और विदेशी दोनों तरह के इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया है। **मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव (PLI) स्कीम** और **ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस रिफॉर्म** जैसी सरकारी पहल कॉर्पोरेट एक्सपेंशन को बढ़ावा दे रही हैं और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर भारत की स्थिति को बेहतर बना रही हैं।

समझौता जापान और समझौते**भारत और अमेरिका ने ज़रूरी मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स को ऑपरेशन के लिए बाइलेटरल फ्रेमवर्क पर साइन किए**

- भारत और अमेरिका ने संपूर्ण महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला में सहयोग को मज़बूत करने के लिए 11वें क्लाड विदेश मंत्रियों की बैठक के मौके पर महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के सहयोग पर द्विपक्षीय रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता अन्वेषण, खनन, प्रसंस्करण, शोधन, पुनर्चक्रण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और महत्वपूर्ण खनिजों से संबंधित निवेश पर केंद्रित है जो इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी), अर्धचालकों, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, एयरोस्पेस, रक्षा प्रणालियों, दूरसंचार और उच्च तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आवश्यक हैं। यह रूपरेखा अमेरिका के नेतृत्व वाली पैक्स सिलिका पहल में भारत की भागीदारी पर आधारित है, जिसमें भारत 20 फरवरी 2026 को शामिल हुआ था और इसका उद्देश्य वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाना है, ऐसे समय में जब चीन वैश्विक महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण के लगभग 90% को नियंत्रित करता है

नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने फोर्थ वैली कंसीयज कॉर्पोरेशन के साथ पार्टनरशिप की

- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) ने जापान में कुशल भारतीय पेशेवरों के लिए सुरक्षित और पारदर्शी रोजगार के अवसरों की सुविधा के लिए, जापान के फोर्थ वैली कंसीयज कॉर्पोरेशन (FVCC) के साथ एक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए। सहयोग के तहत, NSDC ट्रस्ट की विश्वसनीयता जांच ढांचा उम्मीदवारों की पहचान, शैक्षिक योग्यता, रोजगार इतिहास, आपराधिक पृष्ठभूमि (जहां कानूनी रूप से अनुमत हो), और दस्तावेज़ प्रामाणिकता को सत्यापित करेगा, इससे पहले कि उन्हें विदेश में तैनात किया जाए। यह पहल मानव संसाधन विनिमय और सहयोग के लिए भारत-जापान कार्य योजना का समर्थन करती है, जिसका उद्देश्य अगले पांच वर्षों में जापान में कम से कम 50,000 कुशल भारतीय पेशेवरों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाना है। साझेदारी का उद्देश्य विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा, निर्माण, आतिथ्य और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में कुशल जनशक्ति की जापान की बढ़ती मांग को संबोधित करते हुए वैश्विक कौशल मान्यता, कार्यबल गतिशीलता, अंतर्राष्ट्रीय भर्ती मानकों और रोजगार पारदर्शिता में सुधार करना है

गुजरात सरकार ने मेटा प्लेटफॉर्म के साथ MoU साइन किया

- गुजरात सरकार ने सुगम डिजिटल गुजरात प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्हाट्सएप आधारित सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए मेटा प्लेटफॉर्म इंक के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, जिससे एकल डिजिटल इंटरफेस के माध्यम से नागरिक सेवाएं अधिक सुलभ हो जाएंगी। इस पहल के तहत, पांच प्रमुख सरकारी विभागों की लगभग 20 सार्वजनिक सेवाओं को गुजराती और अंग्रेजी में उपलब्ध बहुभाषी व्हाट्सएप चैटबॉट में एकीकृत किया जाएगा। नागरिक आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) प्रमाण पत्र, राशन कार्ड अपडेट, राजस्व रिकॉर्ड, आधिकारिक शपथ पत्र और शिकायत निवारण जैसी सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे, साथ ही वास्तविक समय में अपने आवेदन की स्थिति पर भी नज़र रख सकेंगे। साझेदारी का उद्देश्य डिजिटल शासन, पहुंच में आसानी, पारदर्शिता, नागरिक सुविधा और अंतिम-मील सेवा वितरण को मजबूत करना है, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में,

ओडिशा, इंटेल कॉर्पोरेशन और 3D ग्लास सॉल्यूशंस ने \$3.3 बिलियन के सेमीकंडक्टर एग्रीमेंट पर साइन किए

- ओडिशा सरकार, इंटेल कॉर्पोरेशन और 3D ग्लास सॉल्यूशंस इंक (3DGS) ने भुवनेश्वर-खुर्दा क्षेत्र में एक उन्नत पैकेजिंग ग्लास कोर सबस्ट्रेट विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए 3.3 बिलियन डॉलर के समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए, जिससे यह भारत में सबसे बड़े अर्धचालक निवेशों में से एक बन गया। यह सुविधा उन्नत पैकेजिंग ग्लास कोर सबस्ट्रेट्स, उच्च घनत्व इंटरकनेक्ट (HDI) सबस्ट्रेट्स और अगली पीढ़ी के सेमीकंडक्टर घटकों का निर्माण करेगी, जबकि इंटेल उन्नत विनिर्माण विशेषज्ञता और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। ग्लास कोर सबस्ट्रेट्स महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करते हैं, जिसमें उच्च चिप घनत्व, बेहतर थर्मल प्रदर्शन, बेहतर विद्युत दक्षता, बड़ी हुई सिग्नल अखंडता और कम बिजली की खपत शामिल है, जो उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग (HPC) और उन्नत सेमीकंडक्टर अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाते हैं। यह प्रोजेक्ट इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) के साथ है और उम्मीद है कि इससे इंडिया का सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम मजबूत होगा, इम्पोर्ट पर निर्भरता कम होगी, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आकर्षित होगा, और इंडिया ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाय चैन में एक बड़ा प्लेयर बनेगा।

भारत और म्यांमार ने रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया

- म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग की 30 मई से 3 जून 2026 तक भारत की आधिकारिक यात्रा के दौरान, भारत और म्यांमार व्यापार, संपर्क, सुरक्षा, कृषि, ऊर्जा, बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान सहित रणनीतिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने पर सहमत हुए। भारत ने अपने पड़ोसी पहले नीति, एकट ईस्ट पॉलिसी और महासागर (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति) पहल के तहत म्यांमार के महत्व की पुष्टि की। दोनों देशों ने कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट और भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग जैसे प्रमुख संपर्क परियोजनाओं को जल्द पूरा करने पर जोर दिया, जिनसे क्षेत्रीय व्यापार और संपर्क बढ़ाने की उम्मीद है। नेताओं ने परिचालन रुपया-क्यात सेटलमेंट मैकेनिज्म पर भी प्रकाश डाला

राइट्स लिमिटेड ने क्रिसिल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

- राइट्स लिमिटेड ने भारत और विदेशों में परियोजनाओं के लिए संयुक्त रूप से डेटा-संचालित बुनियादी ढांचा परामर्श समाधान प्रदान करने के लिए क्रिसिल (क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। सहयोग प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना और निष्पादन में सुधार के लिए क्रिसिल के शोध, विश्लेषण, वित्तीय सलाह और बाजार खुफिया क्षमताओं के साथ राइट्स की इंजीनियरिंग और परिवहन बुनियादी ढांचे की विशेषज्ञता को जोड़ता है। साझेदारी रेलवे, मेट्रो सिस्टम, राजमार्ग, हवाई अड्डे, बंदरगाह, रोपवे, पुलों, सुरंगों, शहरी परिवहन, जल विद्युत, जल संसाधन, अपशिष्ट जल प्रबंधन और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों का समर्थन करेगी। उन्नत डेटा एनालिटिक्स, मूल्यांकन समर्थन, उचित परिश्रम, बाजार अनुसंधान और वित्तीय मॉडलिंग के माध्यम से,

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने एंटरप्राइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस के लिए मिस्ट्रल एआई के साथ पार्टनरशिप की

- टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने विभिन्न उद्योगों में एंटरप्राइज-ग्रेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) समाधानों को अपनाने में तेजी लाने के लिए फ्रांस की प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी मिस्ट्रल AI के साथ रणनीतिक साझेदारी की। इस सहयोग के माध्यम से, TCS मिस्ट्रल फोर्ज के लिए पहला ग्लोबल सिस्टम्स इंटीग्रेटर (GSI) बन गया, जो एक एंटरप्राइज AI प्लेटफॉर्म है जो संगठनों को मालिकाना व्यावसायिक डेटा का उपयोग करके सुरक्षित और अनुकूलित AI मॉडल विकसित करने में सक्षम बनाता है। TCS बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा (BFSI), विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा और सार्वजनिक क्षेत्र जैसे क्षेत्रों के लिए AI-संचालित समाधान बनाने के लिए मंच का लाभ उठाएगी। समझौते के हिस्से के रूप में, TCS उद्योग-विशिष्ट AI एप्लिकेशन विकसित करने, पेशेवरों को प्रशिक्षित करने, परियोजना कार्यान्वयन का समर्थन करने और वैश्विक उद्यमों के बीच AI अपनाने में तेजी लाने के लिए एक समर्पित उत्कृष्टता केंद्र (CoE) स्थापित करेगी

भारत-ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) लागू हुआ

- भारत-ओमान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (CEPA) 1 जून 2026 को ऑफिशियली लागू हुआ, जो बाइलेटरल ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को मजबूत करने में एक अहम मील का पत्थर है। यह एग्रीमेंट ओमान की 98.08% टैरिफ लाइनों पर ज़ीरो-ड्यूटी मार्केट एक्सेस देता है, जिसमें इंडिया का लगभग 99.38% एक्सपोर्ट शामिल है, जिससे इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर, मरीन प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, लेदर, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे सेक्टरों में इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए नए मौके पैदा होते हैं। CEPA ओमान में कई सर्विस सेक्टरों में इंडियन कंपनियों द्वारा 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) को भी आसान बनाता है और इसमें इन्वेस्टमेंट, प्रोफेशनल मोबिलिटी, ट्रेडिशनल मेडिसिन (आयुष), हलाल सर्टिफिकेशन, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट रिकग्निशन, फार्मास्यूटिकल अप्रूवल और रेगुलेटरी कोऑपरेशन से जुड़े प्रोविज़न शामिल हैं। इस एग्रीमेंट से बाइलेटरल ट्रेड को बढ़ावा मिलने, इन्वेस्टमेंट फ्लो गहरा होने, रोज़गार पैदा होने और गल्फ रीजन के साथ इंडिया के स्ट्रेटिजिक इकोनॉमिक जुड़ाव को और मजबूत करने की उम्मीद है।

केंद्र ने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

- केंद्र सरकार ने देश भर में ग्रामीण पेयजल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए जल जीवन मिशन 2.0 (JJM 2.0) के तहत अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, नागालैंड, पुडुचेरी और बाद में सिक्किम के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। सुधार से जुड़े समझौते स्थायी जल आपूर्ति प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायत के नेतृत्व वाले, समुदाय-आधारित और सेवा-उन्मुख दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं। मिशन का लक्ष्य दिसंबर 2028 तक सभी 19.36 करोड़ ग्रामीण घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTCs) प्रदान करना है, साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायत को "हर घर जल" गांव के रूप में प्रमाणित करना है। ₹8.69 लाख करोड़ के बड़े हुए वित्तीय परिव्यय के साथ, मिशन का दूसरा चरण सुरक्षित पेयजल की नियमित आपूर्ति, सामुदायिक भागीदारी, जल आपूर्ति प्रणालियों के संचालन और रखरखाव और दीर्घकालिक स्थिरता पर केंद्रित है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है।

भारत और यूनाइटेड किंगडम ने क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाय चैन ऑब्जर्वेटरी लॉन्च की

- भारत और यूनाइटेड किंगडम ने महत्वपूर्ण खनिजों के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने में सहयोग को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में भारत-यूके क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाय चैन ऑब्जर्वेटरी (GSCO) का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। इस पहल का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी और यूके के विदेश सचिव यवेटे कूपर ने किया और इसे IIT (ISM) धनबाद में TEXMiN और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के बीच सहयोग के माध्यम से विकसित किया गया है। वेधशाला डेटा विश्लेषण, अनुसंधान और खुफिया जानकारी का उपयोग करके वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की निगरानी करेगी, जिससे सरकारों को आपूर्ति में व्यवधान, भू-राजनीतिक जोखिम, बाजार के रुझान और महत्वपूर्ण खनिजों से संबंधित उभरते अवसरों की पहचान करने में मदद मिलेगी। चूंकि ये खनिज इलेक्ट्रिक वाहनों, अर्धचालकों, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा प्रणालियों, दूरसंचार और उन्नत विनिर्माण के लिए आवश्यक हैं, इसलिए इस पहल से रणनीतिक योजना को मजबूत करने, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का समर्थन

पश्चिम बंगाल विधानसभा नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) से जुड़ी

- पश्चिम बंगाल विधानसभा ने नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) को लागू करने के लिए एक मेमोरेण्डम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) पर साइन किए, जिससे यह डिजिटल प्लेटफॉर्म अपनाते वाली भारत की 33वीं विधानसभा बन गई। संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा एक मिशन मोड प्रोजेक्ट के तौर पर डेवलप किया गया, NeVA का मकसद "वन नेशन - वन एप्लीकेशन" के विज़न के ज़रिए लेजिस्लेटिव कामकाज को मॉडर्न बनाना है। यह प्लेटफॉर्म सवाल, बिल, नोटिस, कमिटी की कार्यवाही, हाउस डिबेट, बुलेटिन, लेजिस्लेटिव रिकॉर्ड और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स सहित लेजिस्लेटिव कामों का पेपरलेस मैनेजमेंट करने में मदद करता है, साथ ही लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्यों (MLAs) को कहीं से भी डिजिटल रूप से जानकारी एक्सेस करने की सुविधा देता है। यह पहल पूरी तरह से डिजिटल लेजिस्लेटिव इकोसिस्टम के ज़रिए ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, एक्सेसिबिलिटी, रिकॉर्ड मैनेजमेंट, सिटिज़न एंगेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को कम करके डिजिटल इंडिया मिशन को सपोर्ट करती है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज और मेटा ने AI-इनेबल्ड हाइपरस्केल डेटा सेंटर बनाने के लिए पार्टनरशिप की

- रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) और मेटा प्लेटफॉर्म ने गुजरात के जामनगर में 168 मेगावाट (MW) की प्रारंभिक क्षमता के साथ एक AI-सक्षम हाइपरस्केल डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की। यह सुविधा, जो भारत की सबसे बड़ी AI अवसंरचना परियोजनाओं में से एक बनने की उम्मीद है, भारत में मेटा का पहला बिल्ट-टू-सूट डेटा सेंटर के रूप में काम करेगी, जो इसके तेजी से विस्तारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग (HPC) आवश्यकताओं का समर्थन करेगी। परियोजना कार्बन उत्सर्जन और मीठे पानी की खपत को कम करते हुए टिकाऊ संचालन सुनिश्चित करने के लिए अक्षय ऊर्जा, अलवणीकृत समुद्री जल आधारित शीतलन प्रणाली और J10 की फाइबर कनेक्टिविटी का लाभ उठाएगी। रिलायंस बुनियादी ढांचे का विकास और संचालन करेगा, जबकि मेटा AI वर्कलोड के लिए क्षमता पट्टे पर देगा

हिमाचल प्रदेश ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के साथ MoU साइन किया

- हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में क्लाउड-रेसिलिएंट, इनक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम (UNDP) के साथ एक मेमोरेण्डम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) पर साइन किए हैं। यह पार्टनरशिप सर्कुलर इकोनॉमी, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, सस्टेनेबल लाइवलीहुड और वेस्ट क्लेक्शन के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे खास सेक्टर पर फोकस करती है। यह पहल एनवायरनमेंटल गवर्नेंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में महिलाओं, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी और इनफॉर्मल वर्कर की भागीदारी पर भी ज़ोर देती है। एग्रीमेंट के साथ-साथ, राज्य ने वेस्ट मैनेजमेंट में लगे सैनिटेशन वर्कर की इज्जत, सेफ्टी और सोशियो-इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए सफाई मित्र स्कीम शुरू की। इस कोलेबोरेशन से इकोलॉजिकल कंजर्वेशन को मजबूत करने, ग्रीन डेवलपमेंट को बढ़ावा देने और हिमाचल प्रदेश के लॉन्ग-टर्म एनवायरनमेंटल सस्टेनेबिलिटी गोल को सपोर्ट करने की उम्मीद है।

एयर इंडिया और रियाद एयर ने रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए

- एयर इंडिया और रियाद एयर ने भारत, सऊदी अरब और दूसरे इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के बीच एयर कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए एक MoU साइन किया है। रेगुलैटरी मंजूरी मिलने पर, एयरलाइंस कोडशेयर और इंटरलाइन एग्रीमेंट शुरू करेंगी, जिससे पैसेंजर दिल्ली, मुंबई और रियाद में हब के ज़रिए अपने मिले-जुले नेटवर्क पर एक ही टिकट पर बिना रुकावट के यात्रा कर सकेंगे। इस पार्टनरशिप में कार्गो सर्विस, लॉयल्टी प्रोग्राम, ऑपरेशनल सपोर्ट, डिजिटल टेक्नोलॉजी और कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने में भी सहयोग की गुंजाइश होगी। इस एग्रीमेंट से टूरिज्म को बढ़ावा मिलने, बिज़नेस ट्रैवल में आसानी होने, दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होने और भारत और सऊदी अरब के बीच एविएशन सहयोग मजबूत होने की उम्मीद है, साथ ही एयर इंडिया की चल रही ग्लोबल विस्तार स्ट्रैटेजी को भी सपोर्ट मिलेगा।

राहवीर स्कीम को प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ़ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के साथ पार्टनरशिप की

- रैपिडो ने भारत सरकार की पहल राहवीर स्कीम के बारे में देश भर में जागरूकता बढ़ाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के साथ पार्टनरशिप की है। यह योजना लोगों को सड़क दुर्घटना के पीड़ितों की मदद करने के लिए ज़रूरी गोल्डन आवर के दौरान बढ़ावा देती है। इस कैंपेन के तहत, 4 लाख से ज़्यादा रैपिडो कैप्टन ने राहवीर शपथ ली, जिससे सड़क सुरक्षा की सबसे बड़ी शपथ का गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। डिजिटल कैंपेन, कम्युनिटी आउटरीच और इन-ऐप जागरूकता प्रोग्राम के ज़रिए, रैपिडो लोगों को बिना किसी डर के दुर्घटना के पीड़ितों को समय पर मदद देने के बारे में बताएगा। इस पहल का मकसद इमरजेंसी में मदद को बेहतर बनाना, जान बचाने में लोगों की भागीदारी बढ़ाना, सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और पूरे भारत में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को कम करने के सरकार के नज़रिए में मदद करना है।

इन्वेस्ट इंडिया और इन्वेस्ट यूपी ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की

- इन्वेस्ट इंडिया और इन्वेस्ट UP ने उत्तर प्रदेश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) को तेज़ करने और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की है। यह कोलेबोरेशन इन्वेस्टर को आसानी देने, इन्वेस्टमेंट प्रोज़ेक्ट को तेज़ी से लागू करने, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, शिकायत दूर करने और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आउटरीच पर फोकस करता है। इसका मकसद बिज़नेस करने में आसानी को मज़बूत करना, रेगुलेटरी मंजूरी में सुधार करना, ज़मीन खरीदने में आसानी करना और टेक्नोलॉजी पर आधारित और रोज़गार देने वाले सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना भी है। यह पार्टनरशिप घरेलू और विदेशी इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करके, रोज़गार के मौके पैदा करके और भारत के लीडिंग इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन में से एक के तौर पर राज्य की स्थिति को मज़बूत करके उत्तर प्रदेश के \$1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने के विज़न को सपोर्ट करती है।

असम और नागालैंड ने जॉइंट ऑयल और नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन के लिए त्रिपक्षीय MoU पर साइन किए

- असम और नागालैंड की सरकारों ने अपनी साझा सीमा पर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के संयुक्त अन्वेषण और उत्पादन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री की उपस्थिति में एक त्रिपक्षीय समझौता ज़ापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में 1,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक में फैले छह हाइड्रोकार्बन समृद्ध विवादित क्षेत्र शामिल हैं और सीमा विवादों के कारण दशकों की सीमित गतिविधि के बाद समन्वित पेट्रोलियम अन्वेषण के लिए एक औपचारिक ढांचा स्थापित करता है। समझौते के तहत, तेल और गैस उत्पादन से उत्पन्न राजस्व को 50:50 राजस्व-साझाकरण मॉडल के माध्यम से समान रूप से साझा किया जाएगा। इस पहल से महत्वपूर्ण हाइड्रोकार्बन भंडार को अनलॉक करने, भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत करने, निवेश आकर्षित करने, रोज़गार के अवसर पैदा करने और पूर्वोत्तर क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की उम्मीद है।

बीएसएनएल और आईआईटी कानपुर ने अगली पीढ़ी की दूरसंचार प्रौद्योगिकियों पर सहयोग किया

- भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने अगली पीढ़ी की टेलीकॉम टेक्नोलॉजी को मिलकर डेवलप करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (IIT) कानपुर के साथ एक MoU साइन किया है। यह सहयोग डायरेक्ट-टू-मोबाइल (D2M) ब्रॉडकास्टिंग, स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड स्पेक्ट्रम रिसर्च जैसी एडवांस्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के रिसर्च, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और कमर्शियलाइज़ेशन पर फोकस करता है। इस पार्टनरशिप का मकसद इनोवेशन को बढ़ावा देना, स्वदेशी टेलीकॉम क्षमताओं को मज़बूत करना, ग्रामीण इलाकों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना और डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल में योगदान देना है। इस सहयोग से टेलीकम्युनिकेशन में भारत की आत्मनिर्भरता में तेज़ी आने की उम्मीद है, साथ ही भविष्य के लिए तैयार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा मिलेगा।

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने कनाडा लाइफ के साथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एग्रीमेंट साइन किया

- टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने यूरोप की प्रमुख जीवन बीमा और पेंशन कंपनियों में से एक, कनाडा लाइफ के साथ एक बहु-वर्षीय डिजिटल परिवर्तन और प्रबंधित सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत, TCS अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)-संचालित कॉग्निक्स प्लेटफॉर्म का लाभ उठाकर कनाडा लाइफ के आईटी बुनियादी ढांचे, डेटा सेंटर, अंतिम-उपयोगकर्ता कंप्यूटिंग वातावरण और सॉफ्टवेयर जीवनचक्र प्रबंधन का आधुनिकीकरण करेगा। साझेदारी में यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, जर्मनी और आइल ऑफ़ मैन में TCS की बुनियादी ढांचा सेवा प्रतिभा का विस्तार करना भी शामिल है, जबकि कर्मचारी प्रशिक्षण और प्रमाणन में निवेश किया जाएगा। सहयोग से यूरोपीय बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा (BFSI) क्षेत्र में TCS की उपस्थिति को मज़बूत करने और यूरोपीय संघ के डिजिटल ऑपरेशनल रेजिलिएंस एक्ट (DORA) के अनुपालन का समर्थन करने की उम्मीद है।

भारत और स्लोवाकिया ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक साझेदारी तक बढ़ाया

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1993 में अपनी स्वतंत्रता के बाद से स्लोवाकिया का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। यात्रा के दौरान, भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को एक व्यापक साझेदारी तक बढ़ाया और रक्षा सहयोग, श्रम प्रवास, उच्च शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकियों, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, वैज्ञानिक अनुसंधान, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और क्वांटम संचार को कवर करने वाले 11 समझौतों और समझौता ज़ापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। एक महत्वपूर्ण परिणाम कोसिसे के तकनीकी विश्वविद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) में पहली भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) चेंबर की स्थापना थी। दोनों देश आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह और एक कांसुलरी वार्ता तंत्र स्थापित करने पर भी सहमत हुए,

भारत-यूनाइटेड किंगडम CETA और डबल कंट्रीव्यूशन कन्वेंशन लागू हुए

- भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA) और दोहरा योगदान सम्मेलन (DCC) 15 जून 2026 को लागू हुआ, जिससे द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में काफी मजबूती आई है। CETA भारत की लगभग 99% टैरिफ लाइनों पर शून्य-शुल्क बाजार पहुंच प्रदान करता है और माल, सेवाओं, निवेश, डिजिटल व्यापार, वित्तीय सेवाओं, बौद्धिक संपदा अधिकार, सरकारी खरीद, नवाचार और स्थिरता जैसे क्षेत्रों को कवर करता है। यह आईटी विशेषज्ञों, इंजीनियरों, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों, शेफ, योग प्रशिक्षकों और संगीतकारों सहित भारतीय पेशेवरों के लिए बड़ी हुई गतिशीलता के अवसर भी प्रदान करता है। दोहरे योगदान सम्मेलन के तहत, यूके में अस्थायी असाइनमेंट पर भारतीय कर्मचारियों को पांच साल तक के लिए दोहरे सामाजिक सुरक्षा योगदान करने से छूट दी गई है,

MoRTH ने दिल्ली-NCR फ्लिट मॉडर्नाइजेशन के लिए व्हीकल मैनुफैक्चरर्स के साथ एग्रीमेंट साइन किए

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से सरकार की दिल्ली-एनसीआर फ्लिट आधुनिकीकरण योजना को लागू करने के लिए अशोक लेलैंड, स्विच मोबिलिटी और टाटा मोटर्स के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। यह पहल BS-IV और पुराने ट्रकों और बसों के मालिकों को BS-VI या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिसमें 8% निर्माता छूट, वाहन ऋण पर 5% ब्याज सब्सिडी, मासिक ईंधन वाउचर, मोटर वाहन कर रियायतें और पंजीकरण शुल्क में छूट सहित कई प्रोत्साहन दिए जाते हैं। साथ में, भाग लेने वाले निर्माता भारत के ट्रक और बस बाजार का लगभग 50% हिस्सा हैं, जिससे यह कार्यक्रम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वच्छ परिवहन, बेहतर वायु गुणवत्ता और टिकाऊ शहरी गतिशीलता की दिशा में एक बड़ा कदम है।

गुजरात ने हुडको के साथ ₹1 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग एग्रीमेंट पर साइन किए

- गुजरात सरकार ने राज्य भर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में तेज़ी लाने के लिए दो साल में ₹1 लाख करोड़ तक की फाइनेंसियल मदद के लिए हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HUDCO) के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) पर साइन किए। इस फंडिंग से गुजरात मेट्रो रेल फेज़-II और फेज़-III, एक्सप्रेसवे, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और धोलेरा स्मार्ट सिटी के डेवलपमेंट जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट मिलेगा। HUDCO रीपेमेंट मोरेटोरियम के साथ फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग देगा, जबकि राज्य सरकार आसानी से लागू करने के लिए मंजूरी देगी। इसके अलावा, गुजरात ने IIM अहमदाबाद के साथ फीजिविलिटी स्टडी करने, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करने और विकसित गुजरात 2047 विजन के तहत प्रोजेक्ट्स का मूल्यांकन करने के लिए एक और MoU साइन किया।

IITM और ARIES ने मिलकर हिमालयी जलवायु अवलोकन स्टेशन स्थापित किया

- भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM), पुणे, और आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान (ARIES), नैनीताल ने भारत जलवायु अवलोकन नेटवर्क (BCON) के तहत उत्तराखंड के देवस्थल में एक दीर्घकालिक जलवायु अवलोकन स्टेशन स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। स्टेशन 50 वर्षों से अधिक की अवधि में मौसम संबंधी मापदंडों, ग्रीनहाउस गैसों, वायुमंडलीय रसायन विज्ञान, मिट्टी की नमी और अल्पकालिक जलवायु प्रदूषकों की निगरानी करेगा। मिशन मौसम के तहत विकसित इस पहल का उद्देश्य जलवायु अनुसंधान को मजबूत करना, पृथ्वी प्रणाली मॉडल (ESM) में सुधार करना, जलवायु पूर्वानुमान को बढ़ाना और नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की वैज्ञानिक समझ को गहरा करना है,

नियुक्तियाँ और इस्तीफे

- केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की मंजूरी बढ़ने के बाद, सुप्रीम कोर्ट में पांच नए जजों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इन नियुक्तियों की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की थी और उम्मीद है कि इससे न्यायिक क्षमता मजबूत होगी और पेंडिंग केस कम होंगे। एक खास बात यह है कि सीनियर एडवोकेट वी. मोहना को पदोन्नत किया गया है, जो बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत होने वाली दूसरी महिला बन गई हैं। इस बढ़ोतरी का मकसद न्याय देने की क्षमता में सुधार करना और देश की सबसे बड़ी न्यायिक संस्था के कामकाज को बेहतर बनाना है।
- जस्टिस मीनाक्षी मदन राय को पटना हाई कोर्ट का अगला चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है। अभी सिक्किम हाई कोर्ट में काम कर रही जस्टिस मीनाक्षी मदन राय, चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू के रिटायरमेंट के बाद पद संभालेंगी। उन्होंने 1990 में अपना ज्युडिशियल करियर शुरू किया और सिक्किम की पहली महिला बनीं जिन्हें ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास-कम-सिविल जज के तौर पर

अपॉइंट किया गया। 2015 में परमानेंट जज के तौर पर प्रमोट होने के बाद, उन्होंने कई ज्युडिशियल रोल में काम किया है। उनका अपॉइंटमेंट उनके तीन दशक से ज़्यादा लंबे ज्युडिशियल करियर में एक अहम मील का पत्थर है और ज्युडिशियरी में जेंडर रिप्रेजेंटेशन को मजबूत करता है।

- लोखंडे प्रशांत सीताराम को CBSE का चेयरपर्सन बनाया गया है, जबकि वरुण भारद्वाज इसके सेक्रेटरी बन गए हैं। AGMUT कैडर के 2001 बैच के IAS ऑफिसर सीताराम, राहुल सिंह की जगह लेंगे। भारद्वाज हिमांशु गुप्ता की जगह लेंगे और सितंबर 2027 तक काम करेंगे। लीडरशिप में यह बदलाव ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम, जिसमें इवैल्यूएशन के मुद्दे और देरी शामिल हैं, को लेकर चिंताओं के बीच हुआ है। 1929 में बना CBSE, भारत का सबसे बड़ा स्कूल बोर्ड है जो 30,000 से ज़्यादा स्कूलों के लिए क्लास 10 और 12 की परीक्षाएं कराता है। इन नियुक्तियों का मकसद भारत के सेंट्रल एजुकेशन सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को मजबूत करना और परीक्षा और इवैल्यूएशन प्रोसेस को बेहतर बनाना है।

- सीनियर डिप्लोमैट **विपुल** को सऊदी अरब में भारत का अगला एम्बेसडर बनाया गया है। 1998 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर, वे अभी कतर में एम्बेसडर हैं। इससे पहले वे काहिरा, कोलंबो, जिनेवा, दुबई और MEA पोस्टिंग में अहम डिप्लोमैटिक रोल निभा चुके हैं, जिसमें गल्फ मामले भी शामिल हैं। IIT दिल्ली और ISB के पुराने स्टूडेंट, वे गल्फ डिप्लोमेसी में अच्छी एक्सपर्टीज़ रखते हैं। उनका अपॉइंटमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत और सऊदी अरब अपनी स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप के तहत ट्रेड, एनर्जी, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस और टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ा रहे हैं, जिससे वेस्ट एशियन रीजन में भारत का डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट मज़बूत होगा।
- नीलकंठ मिश्रा को **वर्ल्ड बैंक** में भारत का अगला एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। वे भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका जैसे साउथ एशियाई इलाकों को रिप्रेजेंट करेंगे। वे एक जाने-माने इकोनॉमिस्ट और एक्सिस बैंक के पूर्व चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। उनके पास पॉलिसी रिसर्च, फाइनेंशियल मार्केट और इकोनॉमिक एडवाइजरी रोल में काफी अनुभव है। उनके अपॉइंटमेंट से ग्लोबल फाइनेंशियल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन में भारत का रिप्रेजेंटेशन मज़बूत होगा।
- सरकार ने प्रधानमंत्री के सलाहकार के तौर पर तरुण कपूर का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया है। पूर्व IAS अधिकारी, वह PMO में एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी कोऑर्डिनेशन में अहम भूमिका निभाते हैं। उनके बने रहने से स्ट्रेटिजिक गवर्नेंस और डेवलपमेंट प्लानिंग में स्थिरता सुनिश्चित होती है।
- IndiaAI मिशन का CEO बनाया गया है, जबकि सुदीप श्रीवास्तव COO बन गए हैं। इन नियुक्तियों से IndiaAI मिशन 2024 के तहत AI इनोवेशन, कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वदेशी मॉडल और जिम्मेदार AI डेवलपमेंट में भारत की कोशिशों को मज़बूती मिलेगी, जिससे भारत दुनिया भर में AI लीडर बनेगा।
- भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के आर्टिकल 217(1) के तहत **बॉम्बे हाई कोर्ट** के परमानेंट जज के तौर पर छह एडिशनल जजों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। नियुक्त जजों में जस्टिस निवेदिता प्रकाश मेहता, जस्टिस प्रफुल्ल सुरेंद्रकुमार खुबलकर, जस्टिस अश्विन दामोदर भोवे, जस्टिस रोहित वासुदेव जोशी, जस्टिस अद्वैत महेंद्र सेठना और जस्टिस प्रवीण शेषराव पाटिल शामिल हैं। इन नियुक्तियों से न्यायिक क्षमता मज़बूत होने, केस निपटाने की क्षमता में सुधार होने, पेंडिंग केस कम होने और मौजूदा खाली पदों को भरने में मदद मिलने की उम्मीद है। इस कदम से भारत की सबसे व्यस्त संवैधानिक अदालतों में से एक का कामकाज बेहतर होगा और समय पर न्याय मिलने में सुधार होगा।
- कुमार शंकर को 5 जून, 2026 से **इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL)** का नया मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। GAIL (इंडिया) लिमिटेड द्वारा नॉमिनेट किए गए, उनके पास नेचुरल गैस और एनर्जी सेक्टर में 31 साल से ज़्यादा का अनुभव है। BITS पिलानी से केमिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, उन्होंने गैस मार्केटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन, टैरिफ रिफॉर्म और पॉलिसी इनिशिएटिव में अहम भूमिका निभाई है। वह कमल किशोर चाटवाल की जगह लेंगे और उनसे IGL की फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रेटेजी को लीड करने, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मज़बूत करने और भारत में क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपेंशन में मदद करने की उम्मीद है।
- बनवारीलाल पुरोहित को बिना किसी विरोध के भारतीय विद्या भवन का प्रेसिडेंट चुना गया। उन्होंने सुरेंद्रलाल मेहता की जगह ली, जिन्होंने सेहत की वजह से पद छोड़ दिया था। ट्रस्टी, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर और वाइस-प्रेसिडेंट के तौर पर 22 साल से ज़्यादा समय तक संस्था से जुड़े रहने वाले पुरोहित के पास एडमिनिस्ट्रेटिव और पब्लिक सर्विस का बहुत अनुभव है। वे पहले पंजाब, तमिलनाडु, असम और मेघालय के गवर्नर रह चुके हैं। दीपक पारेख वाइस-प्रेसिडेंट चुने गए। कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी ने 1938 में भारतीय विद्या भवन की शुरुआत की थी, जो आज भी भारत के जाने-माने एजुकेशनल और कल्चरल ऑर्गनाइज़ेशन में से एक है।
- विदेश मंत्रालय ने दो सीनियर इंडियन फॉरेन सर्विस (IFS) अधिकारियों को अफ्रीकी देशों में राजदूत नियुक्त किया है। अटलांटा में कॉन्सुल जनरल के तौर पर काम कर रहे लक्ष्मणन रमेश बाबू को कोटे डी आइवर का राजदूत नियुक्त किया गया, जबकि विनय कुमार को साओ टोमे और प्रिंसिपे का राजदूत नियुक्त किया गया। दोनों अधिकारियों के जल्द ही अपनी जिम्मेदारी संभालने की उम्मीद है। ये नियुक्तियां व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा, क्षमता निर्माण और विकास साझेदारी में सहयोग के ज़रिए अफ्रीका के साथ भारत के बढ़ते जुड़ाव को दिखाती हैं, जो पूरे महाद्वीप में राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को मज़बूत करने की नई दिल्ली की बड़ी डिप्लोमैटिक रणनीति का समर्थन करती हैं।
- विदेश मंत्रालय ने 1999 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी रुद्र गौरव श्रेष्ठ को तुर्की में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। इससे पहले ईरान में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत, वह अंकारा में रहेंगे और व्यापार, निवेश, संपर्क, संस्कृति और रणनीतिक मामलों में सहयोग को मज़बूत करने का काम संभालेंगे। यूरोप और एशिया के बीच तुर्की का स्थान इसे काफी भू-राजनीतिक महत्व देता है। उनकी नियुक्ति प्रमुख यूरोशियन भागीदारों के साथ राजनयिक जुड़ाव का विस्तार करने और वाणिज्य, क्षेत्रीय संपर्क और रणनीतिक सहयोग जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने पर भारत के निरंतर ध्यान को दर्शाती है।
- भारत सरकार ने दिनेश पंत और गिरिजा सुब्रमण्यम को **इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI)** का सदस्य नियुक्त किया है। दिनेश पंत को सदस्य (एक्चुअरी) बनाया गया है, जो एक्चुअरी स्टैंडर्ड, इंश्योरेंस रिस्क असेसमेंट और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की लंबे समय तक चलने वाली फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी के लिए जिम्मेदार होंगे। गिरिजा सुब्रमण्यम को सदस्य (डिस्ट्रीब्यूशन) नियुक्त किया गया है, जो इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मज़बूत करने और कस्टमर आउटरीच को बेहतर बनाने पर ध्यान देंगे। दोनों नियुक्तियों का कार्यकाल पाँच साल या 65 साल की उम्र तक होगा। इसके अलावा, सरकार ने सीनियर अधिकारियों दीपक सूद और राजय कुमार सिन्हा का कार्यकाल दो साल के लिए बढ़ा दिया है।

- भारत ने पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में अपना नया उच्चायुक्त नियुक्त किया, जो दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक विकास का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अपने क्रेडेंशियल प्राप्त करने के बाद उन्होंने 12 जून 2026 को ढाका में पदभार ग्रहण किया। यह एक उच्च कूटनीतिक पद पर दुर्लभ राजनीतिक नियुक्तियों में से एक है, जो भारत-बांग्लादेश संबंधों के रणनीतिक महत्व को दर्शाता है। त्रिवेदी ने प्रणय वर्मा का स्थान लिया और ढाका में भारत के कूटनीतिक मिशन का नेतृत्व करेंगे, जो व्यापार, संपर्क, ऊर्जा, सीमा प्रबंधन और क्षेत्रीय सुरक्षा में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। उनकी नियुक्ति भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करना और दोनों देशों के बीच लोगों से लोगों के बीच संबंध बढ़ाना है।
- नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी (NBA) ने बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट, 2002 के तहत डॉ. पीएल गौतम को चेयर अपॉइंट करते हुए एक साल के लिए अपनी एग्रोबायोडायवर्सिटी एक्सपर्ट कमेटी को फिर से बनाया है। यह कमेटी फसल जेनेटिक रिसोर्स, जानवरों की नस्लों और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण में गाइड करेगी, जिसमें एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग (ABS) पर फोकस किया जाएगा। इसमें ICAR, PPVFRA और दूसरे इंस्टीट्यूशन के एक्सपर्ट शामिल हैं। इस कदम का मकसद क्लाइमेट-रेसिलिएंट एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, देसी फसलों की किस्मों को बचाना और ITPGRFA के तहत भारत के कमिटीमेंट्स को सपोर्ट करना, फूड सिक्योरिटी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को मजबूत करना है।
- कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने हितेश जोशी को जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) अपॉइंट किया है। एक अनुभवी इंश्योरेंस प्रोफेशनल और इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के फेलो, वे रीडिंशोरेंस, रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में एक्सपर्ट हैं। उनके अपॉइंटमेंट से GIC

Re की लीडरशिप मजबूत होने और भारत के इंश्योरेंस और रीडिंशोरेंस सेक्टर को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

- सुंदरराज पट्टिलिंगम को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में इंस्पेक्टर जनरल बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में एंटी-नक्सल ऑपरेशन्स में अपने बहुत ज्यादा अनुभव के लिए जाने जाने वाले सुंदरराज ने माओवादी विद्रोह के खिलाफ सुरक्षा ऑपरेशन्स को कोऑर्डिनेट करने में अहम भूमिका निभाई थी। उनके अपॉइंटमेंट से NIA की काउंटर-टेररिज्म और नेशनल सिक्योरिटी क्षमताओं को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
- बाटा इंडिया ने गुंजन शाह की जगह संजय राव को अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बनाया है। नाइकी में लीडरशिप रोल और ज़ारा इंडिया को बढ़ाने में शामिल होने सहित दो दशकों से ज़्यादा के इंटरनेशनल रिटेल अनुभव के साथ, राव रिटेल ग्रोथ, कंज्यूमर एंगेजमेंट और ब्रांड मैनेजमेंट में एक्सपर्टिज़ लाते हैं। उनके अपॉइंटमेंट से इनोवेशन को सपोर्ट मिलने, कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने और बाटा इंडिया की लॉन्ग-टर्म एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाने की उम्मीद है।
- वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) के उपाध्यक्ष के रूप में विवेक अग्रवाल के चुनाव के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जिससे वे इस प्रभावशाली पद को धारण करने वाले पहले भारतीय बन गए। पेरिस में FATF प्लेनरी मीटिंग में चुने गए, वे जुलाई 2026 से जून 2027 तक काम करेंगे। मध्य प्रदेश कैडर के 1994 बैच के IAS अधिकारी, अग्रवाल वर्तमान में केंद्रीय संस्कृति सचिव के रूप में कार्यरत हैं और उन्हें वित्तीय खुफिया और नियामक मामलों का व्यापक अनुभव है। उन्होंने पहले FIU-IND के निदेशक, वित्त मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और भारत के FATF प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख के रूप में कार्य किया। 1989 में स्थापित, FATF मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और उभरते वित्तीय खतरों से निपटने के लिए वैश्विक मानक विकसित करता है,

पुरस्कार

- जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल की साइंस टीचर सोमा मंडल, ग्लोबल कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवॉर्ड 2026 जीतने वाली पहली भारतीय बनीं। उन्हें क्लाइमेट-फोकस्ड और इंकवायरी-बेस्ड साइंस करिकुलम बनाने के लिए पहचान मिली, जो स्टूडेंट्स में एनवायरनमेंटल अवेयरनेस, प्रॉब्लम-सॉल्विंग और सस्टेनेबल सोच को बढ़ावा देता है। यह अवॉर्ड दुनिया भर के बेहतरीन टीचरों को सम्मानित करता है और स्टूडेंट्स की लर्निंग पर पॉजिटिव असर डालने वाले इनोवेटिव टीचिंग प्रैक्टिस को पहचान देता है। उनकी यह कामयाबी भारतीय टीचरों की बढ़ती ग्लोबल पहचान और अच्छी एजुकेशन और एनवायरनमेंटल अवेयरनेस के ज़रिए आने वाली पीढ़ियों को बनाने में उनके योगदान को दिखाती है।
- तमिलनाडु के पोलाची के किसान वल्लुवन को FAO सॉइल फार्मर हीरो के तौर पर पहचान मिली। उन्होंने अपने नारियल के खेत को एक फायदेमंद मल्टी-क्रॉप एग्रोफॉरेस्ट्री एंटरप्राइज में सफलतापूर्वक बदल दिया। फसल डायवर्सिफिकेशन और सस्टेनेबल खेती के तरीकों को अपनाकर, उन्होंने इनकम लेवल और मिट्टी की सेहत दोनों में काफी

सुधार किया। उनका मॉडल एग्रोफॉरेस्ट्री, पर्यावरण संरक्षण और क्लाइमेट-रेसिलिएंट खेती के फायदों को दिखाता है। यह पहचान दिखाती है कि कैसे नई खेती की तकनीकों प्रोडक्टिविटी को बेहतर बना सकती हैं, किसानों की कमाई बढ़ा सकती हैं और प्राकृतिक संसाधनों को बचाते हुए लंबे समय तक सस्टेनेबिलिटी में योगदान दे सकती हैं।

- भारतीय स्टूडेंट्स विवान छावछरिया, एरियाना अग्रवाल और अब्याना मेहता, इमली के बीज के पाउडर से बने एक इनोवेटिव बायोडिग्रेडेबल मटीरियल प्लास-स्टिक को डेवलप करने के लिए द अर्थ प्राइज़ जीतने वाली पहली भारतीय टीम बन गए। यह सॉल्यूशन प्लास्टिक के पार्टिकल्स को बड़े गुच्छों में बांधकर, जिन्हें आसानी से अलग किया जा सकता है, खराब पानी से माइक्रोप्लास्टिक्स को हटाने में मदद करता है। इसे कम लागत वाली और इको-फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के तौर पर डिज़ाइन किया गया है, यह पानी के प्रदूषण और एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन की बढ़ती चुनौती का समाधान करता है। उनकी यह कामयाबी ग्लोबल एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम्स के लिए सस्टेनेबल सॉल्यूशन डेवलप करने में युवाओं के इनोवेशन की भूमिका को हाईलाइट करती है।

- पंचायती राज मंत्रालय नई दिल्ली में 42 पंचायतों को नेशनल पंचायत अवॉर्ड 2025 देगा। ये अवॉर्ड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत दिए जाएंगे। लोकल गवर्नेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इनक्लूजन में बेहतरीन काम को पहचानना। सिलेक्शन पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 के आधार पर होता है, जिसमें ट्रांसपेरेंसी, महिला एम्पावरमेंट और एनवायरनमेंटल सस्टेनेबिलिटी का मूल्यांकन किया जाता है। अवॉर्ड्स में SDG से जुड़े थीम और सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाली पंचायतों को कवर करने वाली कैटेगरी शामिल हैं। यह पहल जमीनी स्तर पर डेमोक्रेसी, नागरिकों की भागीदारी और अच्छे गवर्नेंस को बढ़ावा देती है, ग्रामीण डेवलपमेंट सिस्टम को मजबूत करती है और पूरे भारत में लोकल सेल्फ-गवर्नेंस में इनोवेशन को बढ़ावा देती है।
- डेविड बेकहम को 12 जून 2026 को हॉलीवुड वॉक ऑफ़ फ़ेम पर एक स्टार मिलेगा। यह सम्मान फुटबॉल और ग्लोबल स्पोर्ट्स कल्चर में उनके शानदार योगदान के लिए दिया जाता है। बेकहम ने मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड, LA गैलेक्सी, AC मिलान और PSG जैसे क्लबों के लिए खेला और कई टाइटल जीते। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 115 इंटरनेशनल मैच भी खेले, जिसमें उन्होंने 59 बार टीम की कप्तानी की। यह सम्मान FIFA वर्ल्ड कप 2026 से पहले मिला है, जो ग्लोबल फुटबॉल और कई पीढ़ियों तक स्पोर्ट्स आइकन के तौर पर उनके लंबे समय तक चलने वाले असर को दिखाता है।
- ब्रिटिश अभिनेता और कार्यकर्ता इदरीस एल्बा यूथ डेवलपमेंट और कम्युनिटी वर्क में उनकी सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स III ने विंडसर कैसल में उन्हें नाइटहुड दिया था। उन्हें एल्बा होप फाउंडेशन और द किंग्स ट्रस्ट के साथ उनके सहयोग के लिए सम्मानित किया गया, जिसने उनके शुरुआती करियर में मदद की। द वायर और लूथर में भूमिकाओं के लिए जाने जाने वाले, उन्होंने एंटरटेनमेंट और परोपकार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नाइटहुड शिक्षा, सशक्तिकरण और सामाजिक उत्थान के प्रति उनके कमिटमेंट को मान्यता देता है, जिससे वे कला और सामाजिक प्रभाव को मिलाने वाले प्रमुख सांस्कृतिक व्यक्तियों में से एक बन गए।
- दलाई लामा को धर्मशाला में उनके घर पर ऑडियोबुक "मेडिटेशन्स" के लिए ग्रैमी अवॉर्ड मिला। इस प्रोजेक्ट में सरोद वादक अमजद अली खान और उनके बेटों अमान और अयान अली बंगश के साथ मिलकर काम किया गया था। ऑडियोबुक ने बेस्ट ऑडियोबुक कैटेगरी में अवॉर्ड जीता था। यह पहचान शांति, दया और एकता के विषयों पर जोर देती है, जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मेलजोल को बढ़ावा देती है। अवॉर्ड सेरेमनी में मॉडर्न मीडिया फॉर्मेट के ज़रिए आध्यात्मिक शिक्षाओं की दुनिया भर में तारीफ़ और कलात्मक सहयोग पर जोर दिया गया, जिससे दलाई लामा के अहिंसा और सबकी भलाई के संदेश को मज़बूती मिली।
- लियोनेल मेसी प्रिंसेस ऑफ़ एस्टुरियस स्पोर्ट्स अवॉर्ड 2026 पाने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं। यह अवॉर्ड फुटबॉल में उनके बेहतरीन काम और इंसानियत के काम, लीडरशिप और स्पोर्ट्समैनशिप में उनके योगदान को पहचान देता है। उनकी उपलब्धियों में FIFA वर्ल्ड कप 2022, कोपा अमेरिका टाइटल, ओलंपिक गोल्ड मेडल और आठ बैलन डी'ओर अवॉर्ड शामिल हैं। यह सम्मान खेल और समाज में उनके

ग्लोबल असर को दिखाता है, और उनकी एथलेटिक सफलता और सोशल असर दोनों का ज़रूर मनाता है।

- भारत के यूथ प्लेटफॉर्म MY भारत ने एक हफ्ते में सबसे ज्यादा यूज़र्स द्वारा ऑनलाइन क्विज़ पूरा करने के लिए गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। 3.9 लाख से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग क्विज़ पूरा किया, जो विकसित भारत@2047 के विज़न में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देता है। यह पहल देश के विकास और डिजिटल लर्निंग में युवा नागरिकों की मज़बूत भागीदारी को दिखाती है।
- पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स (PAI) ने ग्रामीण प्रशासन में डेटा-ड्रिवन गवर्नेंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल ई-गवर्नेंस अवार्ड्स 2026 में गोल्ड अवार्ड जीता। यह पंचायतों में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटबिलिटी और एविडेंस-बेस्ड प्लानिंग को मजबूत करता है।
- उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ने संगीत, डांस, थिएटर और लोक कलाओं में योगदान के लिए 51 कलाकारों को सम्मानित किया। यह सम्मान भारत की सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक कलाओं और परफॉर्मिंग आर्ट डॉक्यूमेंटेशन को बचाने की कोशिशों को दिखाता है।
- डिपार्टमेंट ऑफ़ कंज्यूमर अफेयर्स के बनाए ई-जागृति प्लेटफॉर्म ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए गवर्नमेंट प्रोसेस री-इंजीनियरिंग की कैटेगरी में नेशनल अवार्ड्स फॉर ई-गवर्नेंस (NAEg) 2026 में सिल्वर अवार्ड जीता है। जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया, AI-पावर्ड प्लेटफॉर्म चार पुराने कंज्यूमर डिस्प्यूट सिस्टम को एक सिंगल पेपरलेस इकोसिस्टम में जोड़ता है। इस पर 4.15 लाख से ज्यादा यूज़र्स रजिस्टर हुए हैं, 2.29 लाख केस हैंडल किए हैं, और 90.75% डिस्पोजल रेट हासिल किया है। AI चैटबॉट, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट, रियल-टाइम ट्रैकिंग और ऑनलाइन हियरिंग जैसे फीचर्स ने कंज्यूमर कंज्यूमर रिड्रेसल और जस्टिस तक पहुंच को काफी बेहतर बनाया है।
- ओडिशा के पुरी के मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक, 11 जून 2026 को रूस में हुए दूसरे इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर फेस्टिवल में हुए मशहूर रशिया ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 को जीतने वाले पहले इंडियन बने। इस इवेंट में 12 इंटरनेशनल स्कल्पचर ने हिस्सा लिया, जहाँ पटनायक को सैंड आर्ट में उनके शानदार योगदान और ग्लोबल वार्मिंग पर उनके असरदार स्कल्पचर के लिए सम्मानित किया गया। उनके तीन मीटर के आर्टवर्क में एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन की कोशिशों के धरती के अलग-अलग पहलुओं को दिखाया गया है। यह अवॉर्ड एलेना अलेक्जेंड्रोवना ने दिया, जिसमें आर्ट के ज़रिए क्लाइमेट अवेयरनेस, सस्टेनेबिलिटी और इंसानी मैसेज को बढ़ावा देने में उनके ग्लोबल असर को पहचान दी गई।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रातिस्लावा के अपने दौरे के दौरान स्लोवाक प्रेसिडेंट पीटर पेलेग्रिनी से मशहूर ऑर्डर ऑफ़ द व्हाइट डबल क्रॉस (1st क्लास) मिला। यह सम्मान भारत-स्लोवाकिया रिश्तों को मज़बूत करने और इंटरनेशनल सहयोग को बढ़ावा देने में उनके योगदान को पहचान देता है। यह किसी दूसरे देश की तरफ से PM मोदी को दिया गया 33वां इंटरनेशनल सम्मान था, जो भारत के बढ़ते डिप्लोमैटिक असर और ग्लोबल जुड़ाव को दिखाता है।

- नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 को मशहूर प्रिक्स वर्सेल्स वल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स लिस्ट 2026 में शामिल किया गया। यह पहचान बेहतरीन आर्किटेक्चर, सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन और पैसेंजर एक्सपीरियंस के लिए दी गई। नवी मुंबई एयरपोर्ट ने अपने लोटस-इंस्पायर्ड डिज़ाइन से सबको इम्प्रेस किया, जबकि गुवाहाटी टर्मिनल को इसके बैम्बू ऑर्किड-इंस्पायर्ड आर्किटेक्चर के लिए पहचान मिली, जो नॉर्थईस्ट इंडिया की कल्चरल हेरिटेज को दिखाता है। यह अचीवमेंट वर्ल्ड-क्लास, एनवायरनमेंट के हिसाब से सस्टेनेबल एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत के बढ़ते फोकस को दिखाता है।
- भारतीय मूल के सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी जैनेंद्र के. जैन भौतिकी में प्रतिष्ठित बुल्फ पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बने। उन्हें संमिश्र फर्मिऑन की अग्रणी खोज के लिए यह पुरस्कार मिला, जिसने आंशिक क्वांटम हॉल प्रभाव की समझ को बदल दिया। यह पुरस्कार येरुशलम में इसाक हजॉंग द्वारा प्रदान किया गया था। 1989 में, येल विश्वविद्यालय में रहते हुए, जैन ने प्रस्ताव दिया कि इलेक्ट्रॉन क्वांटम भंवर के साथ मिलकर संमिश्र फर्मिऑन बना सकते हैं, जो पहले से अस्पष्टीकृत आंशिक चालकता स्थितियों के लिए एक एकीकृत स्पष्टीकरण प्रदान करता है। उनके सिद्धांत ने प्रसिद्ध "जैन राज्यों" की भविष्यवाणी की और संघनित पदार्थ भौतिकी की आधारशिला बन

गया। राजस्थान के सांभर में जन्मे, उन्होंने आईआईटी कानपुर में अध्ययन किया, स्टोनी ब्रुक विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और वर्तमान में पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं।

- भारतीय कंजर्वेशनलिस्ट परवीन शेख और डॉ. बरखा सुब्बा को 2026 व्हिटली अवॉर्ड्स मिले, जिन्हें 'ग्रीन ऑस्कर' के नाम से जाना जाता है। यह अवॉर्ड लंदन में व्हिटली फंड फॉर नेचर ने दिया था। हर अवॉर्ड पाने वाले को कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए £50,000 मिले। परवीन शेख को कम्युनिटी-बेस्ड कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स के ज़रिए चंबल नदी के किनारे इंडियन स्कीमर को बचाने के लिए पहचान मिली। डॉ. बरखा सुब्बा को दार्जिलिंग में हिमालयन सैलामैंडर को हैबिटाट रेस्टोरेशन और साइंटिफिक मॉनिटरिंग के ज़रिए बचाने के लिए सम्मानित किया गया। ये अवॉर्ड्स दुनिया भर में बेहतरीन ग्रासरूट एनवायरनमेंटल लीडरशिप को पहचान देते हैं।
- वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल प्राइज़ 2026 के टॉप 10 फाइनलिस्ट में 7 स्कूलों को जगह देकर भारत ने एक रिकॉर्ड बनाया है। पुणे और जम्मू-कश्मीर के स्कूलों को इनोवेशन और कम्युनिटी कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया था। ये अवॉर्ड लीडरशिप, सस्टेनेबिलिटी और एजुकेशन इनोवेशन में बेहतरीन काम को पहचान देते हैं। विजेताओं की घोषणा नवंबर 2026 में की जाएगी। यह कामयाबी ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन और इनक्लूसिव लर्निंग प्रैक्टिस में भारत की ग्लोबल लीडरशिप को दिखाती है।

शिखर सम्मेलन और कार्यक्रम

भारत इंदौर में पांच दिन की ब्रिक्स कृषि बैठक की मेज़बानी करेगा

भारत, अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत, 9 से 13 जून 2026 तक इंदौर, मध्य प्रदेश में पांच दिवसीय ब्रिक्स कृषि बैठक की मेज़बानी करेगा। इस कार्यक्रम में ब्रिक्स कृषि कार्य समूह की बैठक (9-11 जून) के बाद ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक (12-13 जून) शामिल है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा घोषित, बैठक में कृषि और खाद्य सुरक्षा में सहयोग को मजबूत करने के लिए ब्रिक्स सदस्य देशों के कृषि मंत्री, नीति निर्माता और वरिष्ठ अधिकारी एक साथ आएंगे। चर्चा खाद्य सुरक्षा, किसान कल्याण, पोषण सुरक्षा, जलवायु-लचीली कृषि, स्मार्ट खेती, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, डिजिटल कृषि, कृषि अनुसंधान, अंतरराष्ट्रीय कृषि व्यापार और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं पर केंद्रित होगी। मीटिंग के आखिर में सस्टेनेबल खेती, इनोवेशन और किसान कल्याण के लिए साझा प्राथमिकताओं को बताने वाला एक जॉइंट डिक्लरेशन अपनाए जाने की उम्मीद है।

हाइलाइट

- स्थान: इंदौर, मध्य प्रदेश
- तारीखें: 9-13 जून 2026
- मेज़बान: ब्रिक्स प्रेसीडेंसी 2026 के तहत भारत
- मुख्य फोकस: फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट-रेज़िलिएंट एग्रीकल्चर, AI, रोबोटिक्स, डिजिटल फ़ार्मिंग, किसान कल्याण
- अपेक्षित परिणाम: कृषि सहयोग पर संयुक्त घोषणा

भारत ने 114वें इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस में समावेशी लेबर सुधारों के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई

केंद्रीय श्रम और रोजगार और एमएसएमई राज्य मंत्री, शोभा करंदलाजे ने 9 जून 2026 को स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में आयोजित 114वें अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में 187 सदस्य देशों की सरकारें, नियोक्ता और श्रमिक वैश्विक श्रम मानकों और रोजगार नीतियों पर चर्चा करने के लिए एक साथ आए। सम्मेलन के दौरान, भारत ने समावेशी आर्थिक विकास, लैंगिक समानता, कार्यबल कल्याण, डिजिटल श्रम प्लेटफॉर्म, कौशल विकास और सामाजिक संवाद में अपनी उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। आयोजन के दौरान, भारत ने श्रम गतिशीलता, कौशल मान्यता, व्यावसायिक प्रशिक्षण, डिजिटल शासन, कानूनी प्रवासन रास्ते और भारतीय पेशेवरों के लिए रोजगार के अवसरों में सहयोग को मजबूत करने के लिए नेपाल, अंगोला, मॉरीशस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं।

हाइलाइट

- इवेंट: 114वां इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस (ILC)
- स्थान: जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड
- आयोजक: इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइज़ेशन (ILO)
- भारतीय प्रतिनिधि: शोभा करंदलाजे
- फोकस एरिया: लेबर रिफॉर्म, स्किल डेवलपमेंट, जेंडर इक्वालिटी, डिजिटल एम्प्लॉयमेंट, वर्कर वेलफेयर
- मुख्य द्विपक्षीय साझेदार: नेपाल, मॉरीशस, अंगोला, UK, USA, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, कनाडा

2026 में BRICS की अध्यक्षता में BRICS राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेज़बानी करेगा

भारत अपनी BRICS अध्यक्षता 2026 के तहत 22-23 जून 2026 को दो दिन की BRICS राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (NSA) की मीटिंग की मेज़बानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता में होने वाली इस मीटिंग में BRICS सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सीनियर सुरक्षा अधिकारी उभरती वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर सहयोग को मज़बूत करने के लिए एक साथ आएंगे। मीटिंग का मुख्य विषय है "आज दुनिया के सामने गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियाँ।" चर्चा साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिम, सूचना युद्ध, आतंकवाद, सीमा पार संगठित अपराध, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा, डिजिटल सुरक्षा और उभरती टेक्नोलॉजी पर केंद्रित होगी। मीटिंग में आतंकवाद-रोधी BRICS संयुक्त कार्य समूह के नतीजों की भी समीक्षा की जाएगी, जिसमें खुफिया जानकारी साझा करने, आतंक के वित्तपोषण का मुकाबला करने, कट्टरपंथ को रोकने और साइबर सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर ज़ोर दिया जाएगा। अजीत डोभाल (भारत), वांग यी (चीन), सर्गेई शोइगु (रूस), और नेज़ामीपुर (ईरान) सहित वरिष्ठ नेताओं के भाग लेने की उम्मीद है। यह मीटिंग रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी मामलों पर BRICS कोऑपरेशन को मज़बूत करने में भारत की बढ़ती लीडरशिप को दिखाती है।

हाइलाइट

- तारीखें: 22-23 जून 2026
- अध्यक्ष: अजीत डोभाल
- थीम: गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियाँ
- फोकस एरिया: साइबर सिक्योरिटी, AI, आतंकवाद, डिजिटल सिक्योरिटी, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर
- मुख्य नतीजा: ब्रिक्स सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग में बढ़ोतरी

भारत ने गुरुग्राम में 11वीं BRICS ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत 25 जून 2026 को गुरुग्राम, हरियाणा में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की सफलतापूर्वक मेज़बानी की। "लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण" विषय और ऊर्जा ट्रैक विषय "सर्वेक्षण" के तहत आयोजित "ऊर्जम् (सभी के लिए ऊर्जा)" बैठक में ऊर्जा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए), वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (जीबीए) और न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) एक साथ आए। चर्चा ऊर्जा सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला, स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा भंडारण, डिजिटलीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, महत्वपूर्ण खनिजों और सस्ती स्वच्छ ऊर्जा पर केंद्रित थी। भारत ने दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक और उपभोक्ता बनने, 540 गीगावाट स्थापित बिजली क्षमता को पार करने, 50% से अधिक गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता हासिल करने और 154 गीगावाट तक सौर क्षमता का विस्तार करने जैसी प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। बैठक का समापन 11वें ब्रिक्स ऊर्जा

मंत्रियों की संयुक्त विज्ञप्ति को अपनाने, स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण के लिए ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (डीसीओई)

हाइलाइट

- स्थान: गुरुग्राम, हरियाणा
- तारीख: 25 जून 2026
- थीम: लचीलापन, इनोवेशन, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण
- प्रमुख लॉन्च: ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (DCoE)
- मुख्य फोकस: रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन, स्मार्ट ग्रिड, AI, एनर्जी स्टोरेज
- नतीजा: जॉइंट कम्युनिके को अपनाया गया

दूसरे पैक्स सिलिका समिट में 35 देशों ने AI के मौके पर जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन किए

दूसरा पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन 25-26 जून 2026 को वाशिंगटन, डीसी, यूएसए में आयोजित किया गया था, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मज़बूत करने के लिए भारत सहित 35 देशों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाया गया था। शिखर सम्मेलन का समापन एआई अवसर पर संयुक्त वक्तव्य को अपनाने के साथ हुआ, जिसमें विश्वसनीय एआई शासन, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, औद्योगिक सहयोग, नवाचार के अनुकूल विनियमन और सुरक्षित एआई पारिस्थितिकी तंत्रों के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। दिसंबर 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू की गई पैक्स सिलिका पहल का उद्देश्य सुरक्षित और लचीली एआई आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना और एआई प्रौद्योगिकियों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। भारत का प्रतिनिधित्व एस कृष्णन (सचिव, मीटीई) और नागराज नायडू (विदेश मंत्रालय) ने किया बड़ी घोषणाओं में AI से जुड़ी टेक्नोलॉजी के सुरक्षित मूवमेंट को आसान बनाने के लिए पैक्स पास प्लेटफॉर्म का लॉन्च और AI इंडस्ट्रीज़ के लिए एडवांस्ड मैनुफैक्चरिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए स्टैनफोर्ड के फाउंड्री स्कूल का लॉन्च शामिल था, जिसे US\$50 मिलियन का कमिटमेंट मिला था। इस समिट ने ग्लोबल AI गवर्नेंस और उभरती टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका को और मज़बूत किया।

हाइलाइट

- इवेंट: दूसरा पैक्स सिलिका समिट
- स्थान: वाशिंगटन, डीसी, यूएसए
- तारीखें: 25-26 जून 2026
- भाग लेने वाले देश: 35
- मुख्य नतीजा: AI के मौके पर जॉइंट स्टेटमेंट
- प्रमुख पहल: पैक्स पास, स्टैनफोर्ड के नेतृत्व वाला फाउंड्री स्कूल
- भारत के प्रतिनिधि: एस. कृष्णन और नागराज नायडू
- फोकस एरिया: AI गवर्नेंस, भरोसेमंद सप्लाय चैन, इनोवेशन, डिजिटल कोऑपरेशन

रैंकिंग

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी CPPI 2025 में भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला कंटेनर पोर्ट बना

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (JNPA) विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलेजेंस द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स (CPPI) 2025 में भारत के सर्वोच्च प्रदर्शन वाले कंटेनर पोर्ट के रूप में उभरा है। JNPA ने वैश्विक स्तर पर 22वां स्थान हासिल किया, पिछले संस्करण से एक रैंक में सुधार किया और भारत के अग्रणी कंटेनर पोर्ट के रूप में अपनी स्थिति जारी रखी। यह मान्यता पोत के टर्नअराउंड समय, कार्गो हैंडलिंग दक्षता, परिचालन प्रदर्शन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाती है। अन्य भारतीय बंदरगाहों में, पिपावाव पोर्ट 28वें स्थान पर रहा, जो मुंद्रा पोर्ट (30वें) से आगे निकलकर सर्वोच्च रैंक वाला निजी कंटेनर बंदरगाह बन गया, जबकि विशाखापत्तनम पोर्ट ने 104वां स्थान हासिल किया। CPPI परिचालन दक्षता, कार्गो हैंडलिंग गति, टर्नअराउंड समय और समग्र लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन के आधार पर बंदरगाहों का मूल्यांकन करता है।

हाइलाइट

- रिपोर्ट: कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स (CPPI) 2025
- प्रकाशितकर्ता: वर्ल्ड बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलेजेंस
- भारत का सबसे अच्छा पोर्ट: जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (JNPA)
- जेएनपीए की ग्लोबल रैंक: 22वीं
- सर्वोच्च रैंक वाला निजी भारतीय बंदरगाह: पिपावाव बंदरगाह (28वां)
- पैरामीटर: टर्नअराउंड टाइम, कार्गो हैंडलिंग, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, स्पलाई चैन परफॉर्मेंस

ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026: आइसलैंड पहले स्थान पर, भारत 127वें स्थान पर

इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (IEP) ने वैश्विक शांति सूचकांक (GPI) 2026 जारी किया, जिसमें सामाजिक सुरक्षा, चल रहे संघर्ष और सैन्यीकरण के आधार पर 163 देशों की रैंकिंग की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक शांति में लगातार 12वें वर्ष गिरावट आई है, जिसमें 99 देशों में शांति के स्तर में गिरावट दर्ज की गई और 61 सक्रिय राज्य-आधारित संघर्ष हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे अधिक है। आइसलैंड ने लगातार 19 वें वर्ष दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देश के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा, उसके बाद न्यूजीलैंड और स्विट्जरलैंड का स्थान रहा, जबकि रूस को सबसे कम शांतिपूर्ण राष्ट्र का दर्जा दिया गया। भारत ने 2.409 स्कोर के साथ 127 वां स्थान हासिल किया,

हाइलाइट

- रिपोर्ट: ग्लोबल पीस इंडेक्स (GPI) 2026
- जारीकर्ता: इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (IEP)
- सबसे शांतिपूर्ण देश: आइसलैंड
- सबसे कम शांतिपूर्ण देश: रूस
- भारत का स्थान: 127वां
- दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला देश: भूटान (16वां)

स्पेसएक्स के आईपीओ के बाद एलन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बन गए हैं।

जून 2026 में स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन (स्पेसएक्स) के ऐतिहासिक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के बाद एलोन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए। अंतरिक्ष अन्वेषण, उपग्रह संचार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में काम करने वाली कंपनी ने लिस्टिंग के बाद अपने शेयरों में उछाल के बाद 2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का मूल्यांकन हासिल किया। स्पेसएक्स ने अपना आईपीओ 135 डॉलर प्रति शेयर पर लॉन्च किया, 150 डॉलर पर खुला और लगभग 161.11 डॉलर पर बंद हुआ, जिससे लगभग 75 बिलियन डॉलर जुटाए गए, जिससे यह इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ बन गया, जिसने सऊदी अरामको के 2019 के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। स्पेसएक्स में मस्क की हिस्सेदारी का मूल्य लगभग 866 बिलियन डॉलर था, जिससे उनकी कुल अनुमानित कुल संपत्ति 1.1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो गई

हाइलाइट

- व्यक्ति: एलोन मस्क
- उपलब्धि: दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर
- कंपनी: स्पेसएक्स
- IPO साइज़: US\$75 बिलियन (अब तक का सबसे बड़ा)
- कंपनी वैल्यूएशन: US\$2 ट्रिलियन से ज्यादा
- अनुमानित नेट वर्थ: US\$1.1 ट्रिलियन से ज्यादा

हुरुन इंडिया 500 रिपोर्ट 2026 में रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप पर

एक्सिस बैंक और बरगंडी प्राइवेट के साथ साझेदारी में जारी हुरुन इंडिया 500 रिपोर्ट 2026 ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) को ₹ 19.36 लाख करोड़ के मूल्यांकन के साथ भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी का दर्जा दिया। एचडीएफसी बैंक और भारती एयरटेल ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। रिपोर्ट से पता चला है कि शीर्ष 10 कंपनियों ने सभी 500 कंपनियों के कुल मूल्यांकन का 27% हिस्सा लिया, जबकि भारती एयरटेल पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक धन निर्माता के रूप में उभरी, जिसने ₹ 7.64 लाख करोड़ की संपत्ति पैदा की। रिपोर्ट ने भारत के कॉर्पोरेट परिदृश्य में वित्तीय सेवा क्षेत्र के बढ़ते प्रभुत्व पर भी प्रकाश डाला और कहा कि शीर्ष 10 कंपनियों का कुल मूल्यांकन पिछले दशक में 3.5 गुना बढ़ गया है।

हाइलाइट

- रिपोर्ट: हुरुन इंडिया 500 रिपोर्ट 2026
- एक्सिस बैंक और बरगंडी प्राइवेट के साथ जारी
- सबसे मूल्यवान कंपनी: रिलायंस इंडस्ट्रीज
- दूसरा: एचडीएफसी बैंक
- तीसरा: भारती एयरटेल
- सबसे ज्यादा संपत्ति बनाने वाला (2021-25): भारती एयरटेल

QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत 13वें स्थान पर भारत ने QS क्वैक्रेलेली साइमंड्स द्वारा जारी QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में वैश्विक स्तर पर 13वां स्थान हासिल किया, जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) संचालित अर्थव्यवस्था के लिए देश की बढ़ती तत्परता पर प्रकाश डाला। सूचकांक ने उच्च शिक्षा, श्रम बाजार, AI तत्परता और आर्थिक परिवर्तन से संबंधित संकेतकों का उपयोग करके 89 देशों का मूल्यांकन किया। भारत ने 100 में से 89.4 अंक हासिल किए और इसे अपने "असाधारण सिस्टम स्केल" के लिए मान्यता दी गई, जिसे एक बड़े डिजिटल कार्यबल, विस्तारित प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र, बढ़ते AI अपनाने और एक मजबूत स्टार्टअप वातावरण द्वारा समर्थित किया गया। भारत को फ्यूचर ऑफ वर्क स्तंभ में वैश्विक स्तर पर 5वां, स्किल्स अलाइनमेंट में 18वां, अकादमिक तत्परता में 22वां और आर्थिक परिवर्तन में 14 वां स्थान मिला,

हाइलाइट

- रिपोर्ट: QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027
- रिलीज़ करने वाले: QS क्वैक्रेलेली साइमंड्स
- भारत का स्थान: 13वां
- स्कोर: 89.4/100
- बेस्ट पिलर: फ्यूचर ऑफ वर्क (5वां)
- शीर्ष तीन देश: संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एनर्जी ट्रांज़िशन इंडेक्स 2026 जारी किया विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने ऊर्जा संक्रमण सूचकांक (ETI) 2026 जारी किया, जिसमें 44 संकेतकों का उपयोग करके ऊर्जा प्रणाली के प्रदर्शन और संक्रमण की तैयारी पर 120 देशों का मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट में भू-राजनीतिक तनावों और असमान स्वच्छ ऊर्जा निवेशों के कारण एक दशक से अधिक समय में पहली बार ऊर्जा संक्रमण की तैयारी में वैश्विक गिरावट देखी गई। स्वीडन ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा, उसके बाद फिनलैंड और डेनमार्क का स्थान रहा, जबकि भारत दो स्थान के सुधार के साथ 70वें स्थान पर आ गया, जिसमें साल-दर-साल 1.9% का सुधार दर्ज किया गया। भारत की प्रगति ऊर्जा बुनियादी ढांचे, सामर्थ्य, स्थिरता, वित्तीय निवेश और मानव पूंजी विकास में सुधार से प्रेरित थी। रिपोर्ट में 2024 के दौरान कम कार्बन वाली नौकरियों में 24% की वृद्धि भी दर्ज की गई, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा रोजगार 1.3 मिलियन तक पहुंच गया,

हाइलाइट

- रिपोर्ट: एनर्जी ट्रांज़िशन इंडेक्स (ETI) 2026
- जारीकर्ता: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF)
- भारत का स्थान: 70वां
- शीर्ष तीन देश: स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क
- भारत की खास ताकतें: एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, लो-कार्बन जॉब्स
- मुख्य ग्लोबल प्राथमिकताएं: एनर्जी सिक्योरिटी, ग्रिड का विस्तार, क्लीन एनर्जी में निवेश

रिपोर्ट

SIDE 2026 रिपोर्ट: भारत दुनिया की पांचवीं सबसे ज़्यादा डिजिटल अर्थव्यवस्था बन गया है

- **SIDE (स्टेट ऑफ़ इंडियाज़ डिजिटल इकॉनमी) रिपोर्ट 2026** के मुताबिक, भारत दुनिया की पांचवीं सबसे ज़्यादा डिजिटल इकॉनमी बन गया है, जो पिछले साल के आठवें नंबर से बेहतर है। रिपोर्ट में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनटेक इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और डिजिटल गवर्नंस में भारत की ज़बरदस्त तरक्की को हाईलाइट किया गया है। भारत ने **AI रेडीनेस में भी दुनिया भर में चौथा नंबर हासिल किया है**, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में तेज़ी से हो रही तरक्की को दिखाता है। रिपोर्ट ग्लोबल डिजिटल इकॉनमी में भारत की बढ़ती लीडरशिप और एक इनक्लूसिव और टेक्नोलॉजी-ड्रिवन समाज बनाने की उसकी कोशिशों को हाईलाइट करती है।

वर्ल्ड बैंक ने भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया

- वर्ल्ड बैंक ने अपनी लेटेस्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट में, FY2026-27 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर **6.6% कर दिया और FY2027-28 के लिए 7.2% ग्रोथ का अनुमान लगाया**। रिपोर्ट में भारत के मजबूत इकोनॉमिक आउटलुक का कारण मजबूत घरेलू डिमांड, लगातार पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी और बढ़ते प्राइवेट कंजम्प्शन को बताया गया। इसमें यह भी बताया गया कि ग्लोबल इकोनॉमिक अनिश्चितताओं और जियोपॉलिटिकल चुनौतियों के बावजूद भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी में से एक बना हुआ है।

फिच रेटिंग्स ने भारत के आर्थिक परिदृश्य में बदलाव किया

- ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी **फिच रेटिंग्स** ने FY2026-27 के लिए भारत के GDP ग्रोथ आउटलुक में बदलाव किया है, साथ ही जियोपॉलिटिकल टेंशन, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और ग्लोबल ट्रेड की अनिश्चितताओं से होने वाले रिस्क पर भी ज़ोर दिया है। इन बाहरी चुनौतियों के बावजूद, एजेंसी ने भारत की मजबूत घरेलू डिमांड, हेल्दी बैंकिंग सेक्टर, मजबूत मैक्रोइकोनॉमिक फंडामेंटल्स और लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पर ज़ोर दिया। फिच ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म और पॉलिसी स्टेबिलिटी से चलने वाले भारत के लॉन्ग-टर्म ग्रोथ पोटेंशियल पर भरोसा बनाए रखा।

एसएंडपी ग्लोबल ने भारत की मजबूत वृद्धि का अनुमान लगाया

- **S&P ग्लोबल रेटिंग्स** ने अनुमान लगाया है कि **FY2026-27 के दौरान** भारत की इकॉनमी 6.6% बढ़ेगी, जिसे मजबूत घरेलू खपत, बेहतर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, सरकारी कैपिटल खर्च और एक स्थिर फाइनेंशियल सेक्टर से सपोर्ट मिलेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि कई दूसरी एशियाई इकॉनमी की तुलना में एक्सपोर्ट पर भारत की निर्भरता काफी कम है, जिससे यह ग्लोबल इकॉनमिक स्लोडाउन के लिए ज़्यादा मजबूत है। लगातार सुधार, डिजिटलाइज़ेशन और मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ोतरी से लंबे समय तक लगातार ग्रोथ को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है।

भारतीय बैंक एशिया-प्रशांत के सबसे ज्यादा पूंजी वाले बैंकों में शामिल

- S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार , भारतीय बैंक एशिया-पैसिफिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा कैपिटल वाले बैंकों में शामिल हैं। कोटक महिंद्रा बैंक सबसे ज्यादा लेवरेज रेश्यो के साथ टॉप पर रहा, उसके बाद HDFC बैंक , ICICI बैंक और एक्सिस बैंक का स्थान रहा। रिपोर्ट में कैपिटल एडिक्विसी, एसेट क्वालिटी, बेसल III कम्प्लायंस और रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस में सुधार पर जोर दिया गया है, जो भारत के बैंकिंग सेक्टर की बढ़ती रेसिलिएंस और स्टेबिलिटी को दिखाता है।

लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप ग्रीन रेवेन्यू रिपोर्ट

- लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप (LSEG) ने अपनी लेटेस्ट ग्रीन रेवेन्यू रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि भारत ने 2025 के दौरान लगभग **US\$110 बिलियन** का ग्रीन रेवेन्यू कमाया। रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, क्लीन टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल मैनुफैक्चरिंग और वेस्ट मैनेजमेंट सबसे बड़े योगदानकर्ता के तौर पर उभरे। रिपोर्ट में ग्लोबल ग्रीन इकॉनमी में भारत की बढ़ती भूमिका और क्लाइमेट गोल, क्लीन एनर्जी ट्रांज़िशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पाने के उसके कमिटमेंट पर जोर दिया गया है।

नीति आयोग ने 8वीं ट्रेड वाच तिमाही रिपोर्ट जारी की

- नीति आयोग ने ट्रेड वाच क्वार्टरली का 8वां एडिशन जारी किया , जिसमें भारत के एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, इंपोर्ट ट्रेड्स, ग्लोबल ट्रेड डेवलपमेंट और उभरते मार्केट के मौकों का असेसमेंट दिया गया है। रिपोर्ट में एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, बेहतर लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, मजबूत सप्लाय चैन और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स (FTAs) के विस्तार पर जोर दिया गया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट, इंजीनियरिंग गुड्स और फूड प्रोसेसिंग जैसे हाई-ग्रोथ सेक्टरों को भी भारत के भविष्य के एक्सपोर्ट ग्रोथ के मुख्य ड्राइवर्स के तौर पर पहचाना गया है।

राज्य वित्त पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट

- कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (CAG) ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें भारतीय राज्यों के सामने आने वाली फ़ाइनेंशियल चुनौतियों पर रोशनी डाली गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, FY2024-25 के दौरान **18 राज्यों** ने ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GSDP) के 3% की सुझाई गई फ़ाइनेंशियल घाटे की लिमिट को पार कर लिया। सैलरी, पेंशन, सब्सिडी और ब्याज पेमेंट पर बढ़ते खर्च की वजह से ज्यादा उधार लेने की ज़रूरत पड़ी। रिपोर्ट में लंबे समय तक फ़ाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी पक्का करने के लिए मजबूत फ़ाइनेंशियल डिसिप्लिन, अच्छे खर्च मैनेजमेंट और बेहतर रेवेन्यू जुटाने की सलाह दी गई।

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति (SIDE) रिपोर्ट में AI की तैयारी पर प्रकाश डाला गया

- SIDE 2026 रिपोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में भारत की तेज़ी से हो रही तरक्की पर भी जोर दिया गया है , जिससे AI रेडीनेस में देश दुनिया में चौथे नंबर पर आ गया है। रिपोर्ट में इस कामयाबी का क्रेडिट भारत के बढ़ते डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्ड टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स की मौजूदगी, बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम, मददगार सरकारी पॉलिसी और हेल्थकेयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फाइनेंस और गवर्नेंस जैसे सेक्टरों में AI को बड़े पैमाने पर अपनाने को दिया गया है। इन नतीजों से भारत के ग्लोबल AI और डिजिटल इनोवेशन हब बनने के सपने को और पक्का किया गया है।

ग्लोबल डिजिटल पेमेंट्स रिपोर्ट में भारत की लीडरशिप पर रोशनी डाली गई

- एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट रिपोर्ट में भारत को दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट मार्केट बताया गया है , जिसकी वजह यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) का बड़े पैमाने पर अपनाया जाना है। भारत ने 2025 तक सबसे ज्यादा डिजिटल वॉलेट डाउनलोड किए और **228 बिलियन** से ज्यादा UPI ट्रांज़ैक्शन प्रोसेस किए। रिपोर्ट में भारत के सफल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल पर जोर दिया गया है, जो सुरक्षित, कम लागत वाले और सबको साथ लेकर चलने वाले डिजिटल पेमेंट सिस्टम के लिए एक ग्लोबल बेंचमार्क बन गया है।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जिला घरेलू उत्पाद (डीडीपी) दिशा-निर्देश जारी किए

- मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन (MoSPI) ने 2022-23 को बेस ईयर मानकर डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (DDP) का अनुमान लगाने के लिए नेशनल गाइडलाइंस जारी की हैं। यह फ्रेमवर्क जिलों में ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GDDP), नेट डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (NDDP), और पर कैपिटा इनकम की कैलकुलेशन को स्टैंडर्ड बनाता है। इन गाइडलाइंस से डिस्ट्रिक्ट-लेवल इकोनॉमिक प्लानिंग में सुधार, एविडेंस-बेस्ड पॉलिसीमेकिंग को सपोर्ट और पूरे देश में बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

नई थोक मूल्य सूचकांक (WPI) श्रृंखला जारी

- सरकार ने 2022-23 को नया बेस ईयर मानकर एक रिवाइज़्ड होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI) सीरीज़ जारी की है। अपडेटेड सीरीज़ में कमोडिटी बास्केट को 697 से बढ़ाकर 957 आइटम कर दिया गया है और इसमें रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एडवांस्ड मैनुफैक्चरिंग और डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे उभरते सेक्टर शामिल हैं। रिवाइज़्ड इंडेक्स होलसेल महंगाई का ज्यादा सही माप देता है और भारत की अर्थव्यवस्था में स्ट्रक्चरल बदलावों को बेहतर ढंग से दिखाता है।

रक्षा

- वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने वेस्टर्न नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ का पद संभाला। इंडियन नेवी में तीन दशकों से ज़्यादा की सर्विस के साथ, वे देश के सबसे ज़रूरी नेवल कमांड में से एक में बहुत ज़्यादा ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक अनुभव लेकर आए हैं। गनरी और मिसाइल सिस्टम के स्पेशलिस्ट, उन्होंने कई फ्रंटलाइन नेवल प्लेटफॉर्म को कमांड किया है और डिफेंस प्लानिंग, मॉडर्नाइजेशन और फोर्स डेवलपमेंट से जुड़े अहम लीडरशिप पदों पर काम किया है। उनके अपॉइंटमेंट से ऑपरेशनल तैयारी मज़बूत होने और भारत के समुद्री सुरक्षा लक्ष्यों में योगदान मिलने की उम्मीद है।
- एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी की जगह लेते हुए 27वें नेवल चीफ का पद संभाला। कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के स्पेशलिस्ट होने के नाते, उनके पास ऑपरेशनल, ट्रेनिंग और स्ट्रेटेजिक असाइनमेंट में लगभग चार दशकों का अनुभव है। उन्होंने INS विक्रमादित्य समेत बड़े वॉरशिप को कमांड किया है, और पहले वेस्टर्न नेवल कमांड को लीड किया है। जाने-माने मिलिट्री सम्मानों से पहचाने जाने वाले, उनके लीडरशिप से नेवल मॉडर्नाइजेशन, कैपेबिलिटी बढ़ाने और तेजी से मुश्किल होते सिक्योरिटी माहौल में भारत के समुद्री हितों को आगे बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
- जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) का पद संभाल लिया है। भारत सरकार के सबसे सीनियर मिलिट्री ऑफिसर और प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर के तौर पर, वे आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के बीच जॉइंट मिलिट्री प्लानिंग, डिफेंस रिफॉर्म और कोऑर्डिनेशन की देखरेख करेंगे। रीजनल सिक्योरिटी मामलों में अपनी एक्सपर्टिज़ के लिए जाने जाने वाले, उन्होंने कई ज़रूरी मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर काम किया है। उनके अपॉइंटमेंट से डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में तेज़ी आने, इंटीग्रेटेड मिलिट्री स्ट्रक्चर को मज़बूत करने और बदलती चुनौतियों के जवाब में नेशनल सिक्योरिटी की तैयारी को बढ़ाने की उम्मीद है।
- बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन (BRO) के प्रोजेक्ट UDAYAK ने 37 साल पूरे कर लिए हैं, जो भारत के स्ट्रेटेजिक नॉर्थ-ईस्ट इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इसके योगदान को दिखाता है। यह प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ हिस्सों में बड़े रोड नेटवर्क और स्ट्रेटेजिक पुलों को बनाए रखने, लाइन ऑफ़ एकचुअल कंट्रोल (LAC) और भारत-म्यांमार बॉर्डर के पास कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ज़िम्मेदार है। इसकी कोशिशें दूर के बॉर्डर इलाकों में ट्रांसपोर्टेशन, एक्सेसिबिलिटी और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाकर नेशनल सिक्योरिटी और रीजनल डेवलपमेंट दोनों में मदद करती हैं।
- एयर मार्शल तरुण चौधरी ने सेंट्रल एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ का पद संभाला। ऑपरेशनल, स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमैटिक भूमिकाओं में तीन दशकों से ज़्यादा के अनुभव के साथ, उन्होंने इंडियन एयर फ़ोर्स के अंदर डिफेंस एक्विजिशन, मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटिव और कैपेबिलिटी डेवलपमेंट में अहम योगदान दिया है। उनके अपॉइंटमेंट से देश के सबसे ज़रूरी एयर कमांड में से एक के अंदर ऑपरेशनल तैयारी और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को मज़बूती मिलने की उम्मीद है।
- वाइस एडमिरल विनीत मैकार्थी ने अंडमान और निकोबार कमांड (ANC) के कमांडर-इन-चीफ का पद संभाला, जो भारत का एकमात्र इंटीग्रेटेड ट्राई-सर्विस कमांड है। स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण मलक्का स्ट्रेट के पास मौजूद यह कमांड समुद्री सुरक्षा और इंडो-पैसिफिक स्थिरता में अहम भूमिका निभाता है। नेवल ऑपरेशन और ट्राई-सर्विस कोऑर्डिनेशन में बहुत अनुभव के साथ, वह आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के जॉइंट ऑपरेशन की देखरेख करेंगे, जिससे इस क्षेत्र में भारत की स्ट्रेटेजिक मौजूदगी और मज़बूत होगी।
- भारत ने DRDO और इंडियन एयर फ़ोर्स की बनाई रूद्रम-II एयर-टू-सरफेस मिसाइल का सफल टेस्ट किया। मिसाइल ने ऑपरेशनल कंडीशन में फ़्लाइट ट्रायल के दौरान अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाया, जिससे इसके गाइडेंस, नेविगेशन और टारगेटिंग सिस्टम की पुष्टि हुई। RCI हैदराबाद और कई DRDO लैब्स द्वारा बनाई गई, यह भारत की लंबी दूरी की सटीक स्ट्राइक क्षमता को बढ़ाती है। यह सिस्टम स्टैंडऑफ़ अटैक क्षमता को मज़बूत करता है, विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम करता है, और डिफेंस मैनुफ़ैक्चरिंग में आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करता है। यह तरक्की मॉडर्न युद्ध के हालात में भारत की स्वदेशी डिफेंस टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल ताकत को काफ़ी बढ़ाती है।
- INS सुदर्शनी लोकायन-26 अभियान के तहत एंटीगुआ और बारबुडा से रवाना हुआ, जिससे भारत की समुद्री पहुंच मज़बूत हुई। अपने पोर्ट कॉल के दौरान, इसने सहयोग बढ़ाने के लिए गैस्टन ब्राउन और सैन्य अधिकारियों सहित स्थानीय नेतृत्व से बातचीत की। जहाज ने भारत की समुद्री विरासत और सांस्कृतिक कूटनीति को दिखाया। यह मिशन भारत के MAHASAGAR विज्ञान और वसुधैव कुटुंबकम को सपोर्ट करता है। कुटुंबकम दर्शन। यह अगली बार अमेरिका में इंटरनेशनल नेवल रिव्यू और SAIL 250 सेलिब्रेशन में हिस्सा लेगा, जो अमेरिकी आज़ादी के 250 साल पूरे होने का जश्न मनाएगा, जिससे ग्लोबल नेवल कोऑपरेशन और मैरिटाइम पार्टनरशिप मज़बूत होगी।
- एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को एयर स्टाफ (IAF) का अगला वाइस चीफ अपॉइंट किया गया है, जो 1 जुलाई 2026 को ऑफिस संभालेंगे। 1986 में कमीशन हुए एक बहुत अनुभवी ऑफिसर, उनके पास 3,300 से ज़्यादा फ्लाईंग आवर्स हैं और एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग, फाइटर मॉडर्नाइजेशन और स्वदेशी डिफेंस प्रोजेक्ट्स में एक्सपर्टिज़ है। उनकी लीडरशिप भारत की एयर पावर मॉडर्नाइजेशन और स्ट्रेटेजिक एयर ऑपरेशन्स कैपेबिलिटी को मज़बूत करती है।

- SIPRI ईयरबुक 2026 के अनुसार, भारत के न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा पाकिस्तान के 170 वॉरहेड की तुलना में लगभग 190 वॉरहेड तक बढ़ गया है। रिपोर्ट में भारत की स्ट्रेटेजिक क्षमताओं के लगातार मॉडर्नाइजेशन पर जोर दिया गया है, खासकर लंबी दूरी के मिसाइल सिस्टम के डेवलपमेंट के ज़रिए। SIPRI ने यह भी बताया कि भारत रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स से पैदा होने वाली स्ट्रेटेजिक चुनौतियों पर तेज़ी से ध्यान दे रहा है। इसके अलावा, 2025 में भारत का डिफेंस खर्च 8.9% बढ़कर \$92.1 बिलियन हो गया, जिससे यह दुनिया का पाँचवाँ सबसे बड़ा मिलिट्री खर्च करने वाला देश बन गया। ये नतीजे नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस तैयारियों को मज़बूत करने पर भारत के बढ़ते ज़ोर को दिखाते हैं।
- इंडियन नेवी ने घरेलू डिफेंस मैनुफैक्चरर्स को INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत पर तैनात MiG-29K और MiG-29KUB कैरियर-बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए स्वदेशी 80-mm एयरो रॉकेट डेवलप और प्रोड्यूस करने के लिए इनवाइट किया है। नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टेरेट द्वारा जारी एक एक्सप्रेसन ऑफ इंटेंट के ज़रिए, नेवी का मकसद इम्पोर्टेड रॉकेट को लोकल लेवल पर डेवलप किए गए ऑप्शन से बदलना है। ये डुअल-पर्पस हथियार आर्मर्ड गाड़ियों, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और टूप कंसंट्रेशन को टारगेट करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। यह इनिशिएटिव आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करता है। कार्यक्रम, रक्षा को बढ़ाता है स्वदेशीकरण से घरेलू विनिर्माण क्षमताओं में मजबूती आएगी और नौसैनिक विमानन संपत्तियों की परिचालन तैयारी में सुधार आएगा।
- मरीन कमांडो (MARCOS) के लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर को राष्ट्रपति भवन में डिफेंस अलंकरण समारोह 2026 के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के तीसरे सबसे बड़े शांतिकालीन वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र से सम्मानित किया। उन्हें यह सम्मान नवंबर 2024 में बांदीपोरा जिले में किए गए एक संयुक्त आतंकवाद-रोधी ऑपरेशन, ऑपरेशन चुन्तावाड़ी के दौरान असाधारण साहस और प्रोफेशनलिज़्म दिखाने के लिए मिला। यह पुरस्कार भारत के सबसे बेहतरीन स्पेशल ऑपरेशन फोर्स में से एक में सेवा करते हुए उनकी बहादुरी, ड्यूटी के प्रति समर्पण और शानदार योगदान को मान्यता देता है, जो भारतीय सशस्त्र बलों के प्रोफेशनलिज़्म को दिखाता है।
- रक्षा मंत्रालय (MoD) ने भारतीय नौसेना के लिए 20 उन्नत क्षमता वाले वैश्विक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (ECGNSS) जैमर की खरीद के लिए एकाई सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ ₹ 449 करोड़ का अनुबंध किया। खरीदें (भारतीय-IDDMM) श्रेणी के तहत हस्ताक्षरित, इस परियोजना में कम से कम 75% स्वदेशी सामग्री अनिवार्य है, जो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल को मजबूत करता है। ये उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली सिग्नल हस्तक्षेप, स्पूर्फिंग और भ्रामक जैमिंग तकनीकों के माध्यम से दुश्मन के उपग्रह नेविगेशन को बाधित कर सकती हैं। इस अधिग्रहण से भारत की समुद्री सुरक्षा, परिचालन प्रभावशीलता और नौसेना की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
- रक्षा मंत्रालय ने इंडियन नेवी के लिए बाय (इंडियन-IDDMM) कैटेगरी के तहत एन्हांसड कैपेबिलिटी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (ECGNSS) जैमर खरीदने के लिए ₹ 449 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं। कम से कम 75% स्वदेशी कंटेंट के साथ डेवलप किया गया यह सिस्टम आत्मनिर्भर भारत पहल के साथ अलाइन है। ये एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम सिग्नल में दखल देकर, स्पूर्फिंग और धोखे वाली जैमिंग टेक्नीक से दुश्मन के सैटेलाइट नेविगेशन को डिस्टर्ब करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इन सिस्टम के डिप्लॉयमेंट से भारत की समुद्री निगरानी, ऑपरेशनल सिक्योरिटी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताओं में काफी बढ़ोतरी होगी, जिससे सेंसिटिव समुद्री क्षेत्रों में नौसेना की तैयारी मजबूत होगी और भारत का स्वदेशी डिफेंस मैनुफैक्चरिंग इकोसिस्टम मजबूत होगा।
- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी (DRDL) में डॉ. APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स के तहत एडवांस्ड वेपन सिस्टम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया, जिससे भारत की स्वदेशी मिसाइल टेक्नोलॉजी और डिफेंस इनोवेशन को मजबूती मिली। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO के वैज्ञानिकों की भूमिका की तारीफ की और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखाए गए आकाश मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल जैसे स्वदेशी सिस्टम पर जोर दिया। उन्होंने मिशन सुदर्शन चक्र पर भी जोर दिया, जिसका मकसद तीन-लेयर वाला मिसाइल डिफेंस शील्ड बनाना है, और डिफेंस मैनुफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर भारत के तहत AI, हाइपरसोनिक हथियारों और ऑटोनॉमस सिस्टम में तरक्की की अपील की।
- जेंडर इन्क्लूजन की तरफ एक अहम कदम उठाते हुए, 17 महिला NDA कैडेट्स के पहले बैच को मेल कैडेट्स के साथ कड़ी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जून 2026 में ऑफिसर्स के तौर पर कमीशन किया गया। इनमें से 9 इंडियन आर्मी में, 5 इंडियन एयर फोर्स में और 3 इंडियन नेवी में शामिल हुईं। 2022 में नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) में शामिल होने के बाद, कैडेट्स ने उन्हीं ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स और लीडरशिप प्रोग्राम्स को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह मील का पत्थर भारत के इक्वालिटी, मेरिट-बेस्ड सिलेक्शन और अपने मिलिट्री स्ट्रक्चर के मॉडर्नाइजेशन के कमिटमेंट को दिखाता है।
- डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) ने 15 जून 2026 को ओडिशा के डॉ. APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज़ मिसाइल (LRLACM) का सफल फ्लाइंग-टेस्ट किया। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत डेवलप की गई इस मिसाइल को लंबी दूरी पर स्ट्रेटेजिक ज़मीनी टारगेट पर बहुत सटीकता से हमला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइलों के उलट, यह कम ऊंचाई वाले गाइडेड फ्लाइंग पाथ को फ़ॉलो करती है, जिससे पता लगाना और इंटरसेप्शन मुश्किल हो जाता है। यह सफल ट्रायल भारत की लॉन्ग-रेंज प्रिसिज़न स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बढ़ाता है, स्वदेशी डिफेंस टेक्नोलॉजी को मजबूत करता है, और मॉडर्न युद्ध में क्रूज़ मिसाइलों की बढ़ती भूमिका को दिखाता है।

- इंडियन नेवी ने अर्नाला -क्लास एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट (ASW-SWC) के पांचवें वेसल INS अग्रे को शामिल किया। प्रोग्राम। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स का बनाया हुआ यह जहाज़ हल-माउंटेड सोनार , बेरिएबल डेप्थ सोनार (VDS) , एंटी-सबमरीन टॉरपीडो और रॉकेट से लैस है। 80% से ज़्यादा स्वदेशी सामग्री वाला , INS अग्रे आत्मनिर्भर भारत मिशन को सपोर्ट करता है और तटीय निगरानी, माइन वॉरफेयर और एंटी-सबमरीन ऑपरेशन को बढ़ाता है। इसके शामिल होने से भारत की समुद्री सुरक्षा, तटीय रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में रणनीतिक मौजूदगी मज़बूत होती है।
- इंडियन एयर फ़ोर्स (IAF) 20 जुलाई से 7 अगस्त 2026 तक ऑस्ट्रेलिया में होने वाली एक्सरसाइज़ पिच ब्लैक 2026 में हिस्सा लेगी। रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फ़ोर्स की होस्ट की हुई इस मल्टीनेशनल एक्सरसाइज़ में 19 देशों के 100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट और लोग शामिल होंगे। यह इवेंट एडवांस्ड एयर कॉम्बैट ऑपरेशन, इंटरऑपरेबिलिटी, टैक्टिकल इंटीग्रेशन और मल्टीनेशनल कोऑर्डिनेशन पर फोकस करेगा। इसमें हिस्सा लेने से पार्टनर देशों के साथ भारत का डिफेंस कोऑपरेशन मज़बूत होगा और मुश्किल कॉम्बैट माहौल में ऑपरेशनल तैयारी बढ़ेगी।
- 20 जून से 3 जुलाई 2026 तक मंगोलिया के उलानबटार में होने वाली एक्सरसाइज़ खान क्रेस्ट 2026 में हिस्सा लेगी। यह मल्टीनेशनल एक्सरसाइज़ यूनाइटेड नेशंस के पीसकीपिंग ऑपरेशन्स पर फोकस करती है , जिसमें जॉइंट प्लानिंग, पेट्रोलिंग, सिविलियन इवैक्युएशन, काउंटर-IED ड्रिल्स और कैजुअल्टी इवैक्युएशन शामिल हैं। इसमें हिस्सा लेने से पार्टनर सेनाओं के साथ इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ती है और ग्लोबल पीसकीपिंग और इंटरनेशनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन के लिए भारत का कमिटमेंट दिखता है।
- रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 1.25 मेगावाट के मरीन गैस टरबाइन जनरेटर (MGTG) के 12 सेटों की खरीद के लिए भारत फोर्ज लिमिटेड के साथ ₹ 425 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में हस्ताक्षरित यह अनुबंध खरीदें (भारतीय) श्रेणी के अंतर्गत आता है और 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री को अनिवार्य करता है। MGTG महत्वपूर्ण ऑनबोर्ड बिजली उत्पादन प्रणाली हैं जो प्रबंधन प्रणालियों, रडार और निगरानी उपकरण, संचार नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और उन्नत हथियार प्लेटफार्मों को बिजली प्रदान करते हैं। यह परियोजना सरकार की आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहलों का समर्थन करती है
- भारत ने 18 जून 2026 को भारतीय तटरक्षक बल में पहले स्वदेश निर्मित एयर कुशन वाहन (ACV) H-561 को शामिल करने के साथ समुद्री रक्षा में एक प्रमुख उपलब्धि हासिल की। गोवा में चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित , होवरक्राफ्ट तटरक्षक बल द्वारा आदेशित छह ACV में से पहला है। पारंपरिक जहाजों के विपरीत, यह शक्तिशाली लिफ्ट प्रशंसकों द्वारा उत्पन्न हवा के कुशन पर चलता है, जिससे उथले पानी, कीचड़, दलदली भूमि, रेतीले समुद्र तटों, मुहाना और आर्द्रभूमि पर आवाजाही संभव हो जाती है। यह क्षमता इसे भारत के 7,500 किलोमीटर के समुद्र तट को सुरक्षित करने के लिए आदर्श बनाती है। मेक इन इंडिया पहल के तहत निर्मित , H-561 भारत की

बढ़ती स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमताओं को प्रदर्शित करते हुए तटीय निगरानी, तीव्र प्रतिक्रिया संचालन और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेगा।

- भारतीय नौसेना तीन स्वदेश निर्मित युद्धपोतों - आईएनएस दूनागिरी , आईएनएस अग्रे और आईएनएस संशोधक को 21 जून 2026 को कोलकाता में कमीशन करेगी। भारतीय नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किए गए और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) द्वारा निर्मित ये जहाज रक्षा निर्माण में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता का प्रतिनिधित्व करते हैं। आईएनएस दूनागिरी , एक प्रोजेक्ट 17ए स्टील्थ-गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट , सतह, हवा और पनडुब्बी रोधी युद्ध में सक्षम है और ब्रह्मोस मिसाइलों को तैनात कर सकता है। आईएनएस अग्रे पानी के नीचे खतरे का पता लगाने के लिए उन्नत सोनार सिस्टम, टॉरपीडो और पनडुब्बी रोधी रॉकेट से लैस है। आईएनएस संशोधक , संधायक -क्लास कार्यक्रम का अंतिम पोत, स्वायत्त पानी के नीचे के वाहनों (एयूवी) और दूर से संचालित वाहनों (आरओवी) का उपयोग करके हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण, सीबेड मैपिंग और पानी के नीचे डेटा संग्रह के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- इंडियन एयर फ़ोर्स (IAF) अपने मौजूदा फ़्लीट के लिए स्पेयर पार्ट्स, इंजन और एवियोनिक्स पाने के लिए यूनाइटेड किंगडम से नौ रिटायर्ड SEPECAT जगुआर फ़ाइटर एयरक्राफ्ट खरीदेगी। ये एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल सर्विस में नहीं आएं, लेकिन भारत के पुराने जगुआर स्क्वाड्रन के मेंटेनेंस में मदद करेंगे। भारत अकेला ऐसा देश है जो फ्रंटलाइन सर्विस में जगुआर ऑपरेट कर रहा है, जिससे स्पेयर पार्ट्स कम हो गए हैं। यह खरीद तब तक ऑपरेशनल तैयारी बनाए रखेगी जब तक कि तेजस , और रफ़ाल फ़ाइटर और भविष्य के स्वदेशी एयरक्राफ्ट जैसे नए प्लेटफ़ॉर्म ज़्यादा संख्या में शामिल नहीं हो जाते।
- स्वदेश में बना एयरबस C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सितंबर 2026 में मिलेगा , जो आत्मनिर्भर भारत के तहत एक बड़ी उपलब्धि होगी। एयरबस के साथ पार्टनरशिप में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया , यह भारत का पहला प्राइवेट तौर पर बनाया गया मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। ₹ 21,935 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट के तहत, 56 एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे, जिनमें से 40 बड़ोदरा में बनेंगे। C295 71 सैनिकों या 9 टन कार्गो को ट्रांसपोर्ट कर सकता है और पुराने हो रहे एवरो फ़्लीट की जगह लेगा , जिससे सैनिकों के ट्रांसपोर्ट, आपदा राहत, मेडिकल इवैक्युएशन और स्वदेशी एयरोस्पेस मैनुफैक्चरिंग क्षमताओं में बढ़ोतरी होगी।
- DRDO की बनाई HELINA एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर (प्रचंड) के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। यह एक थर्ड-जेनरेशन की फायर-एंड-फॉरगेट मिसाइल है जिसमें इंफ्रारेड सीकर और 7 km की रेंज है। ALH पर पहले के टेस्ट के बाद HAL 2022 में लाइव ट्रायल कर रहा है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को सिस्टम और लॉन्चर के लिए ₹ 1,100 करोड़ से ज़्यादा के कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। HELINA सटीक स्ट्राइक क्षमता के साथ भारत की एंटी-आर्मर क्षमता को बढ़ाता है। यह स्वदेशी डिफेंस प्रोडक्शन को मजबूत करता है और भारतीय सेना और एयर फ़ोर्स की ऑपरेशनल तैयारी में मदद करता है।

- उदयपुर में इंडिगो एयरबस A320 का इस्तेमाल करके अपनी पहली GAGAN-बेस्ड जेट लैंडिंग सफलतापूर्वक की। GAGAN एक ISRO-AAI का डेवलप किया हुआ SBAS सिस्टम है जो GPS एक्यूरेसी को बेहतर बनाता है और सटीक लैंडिंग गाइडेंस देता है। यह LPV अप्रोच को सपोर्ट करता है, खासकर उन एयरपोर्ट पर जहां इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम नहीं हैं। DGCA ने 2021 से नए एयरक्राफ्ट के लिए GAGAN कम्पैटिबिलिटी को ज़रूरी कर दिया है। यह अचीवमेंट एविएशन सेफ्टी को बढ़ाता है, विदेशी नेविगेशन सिस्टम पर डिपेंडेंस को कम करता है, और एशिया-पैसिफिक रीजन में सैटेलाइट-बेस्ड एविएशन टेक्नोलॉजी में भारत की पोजीशन को मज़बूत करता है।
- HELINA मिसाइल इंटीग्रेशन Su-30MKI और LCH प्लेटफॉर्म के साथ आगे बढ़ रहा है। लगभग 40 Su-30MKI में अब ब्रह्मोस है, जबकि HELINA हेलीकॉप्टर-बेस्ड एंटी-टैंक क्षमता को मज़बूत करता है। DRDO द्वारा विकसित, यह इमेजिंग इंफ्रारेड गाइडेंस और फायर-

एंड-फॉरगेट टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। यह 7 km तक बख्तरबंद लक्ष्यों पर हमला कर सकता है। HAL LCH प्रचंड के साथ ट्रायल कर रहा है। यह सिस्टम युद्ध के मैदान की सटीकता में सुधार करता है और आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत के रक्षा आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों का समर्थन करता है।

- IAF ने करीब 40 Su-30MKI एयरक्राफ्ट के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को इंटीग्रेट किया है, जिससे लंबी दूरी की स्ट्राइक कैपेबिलिटी बढ़ गई है। भारत और रूस ने मिलकर यह मिसाइल बनाई है, इसकी रेंज 450 km है और स्पीड Mach 3 है। यह सिस्टम ज़मीन और नेवल टारगेट पर सीधे सटीक हमले करने में मदद करता है। HAL का बनाया Su-30MKI, IAF की रीढ़ है। भविष्य में इंटीग्रेशन से प्लूट की कैपेबिलिटी बढ़ेगी। ब्रह्मोस-NG को AI-बेस्ड गाइडेंस और बेहतर प्रिसिजन के साथ डेवलप किया जा रहा है।

विज्ञान प्रौद्योगिकी

- आकाशगंगा के केंद्र में स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल, सैजिटेरियस A* से बहने वाली हवाओं का पहला मजबूत सबूत खोजा है, जिससे लगभग पांच दशकों से चली आ रही एक पहली सुलझ गई है। चिली में अटाकामा लार्ज मिलीमीटर/सबमिलीमीटर एरे (ALMA) से 100 घंटे से ज़्यादा के ऑब्ज़र्वेशन का इस्तेमाल करते हुए, रिसर्चर्स ने एक कोन के आकार की कैविटी की पहचान की जिसमें ठंडी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस नहीं थी। नतीजों से पता चलता है कि ब्लैक होल से आने वाली हल्की गर्म हवाएं आसपास के मटीरियल को दूर धकेल रही हैं। द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में पब्लिश हुई यह स्टडी स्टार फॉर्मेशन और गैलेक्सी के विकास पर ब्लैक होल के असर की समझ को आगे बढ़ाती है।
- रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मेटा प्लेटफॉर्म्स ने गुजरात के जामनगर में भारत का पहला AI-इनेबल्ड हाइपरस्केल डेटा सेंटर बनाने के लिए पार्टनरशिप की घोषणा की। इस फैसिलिटी की शुरुआती कैपेसिटी 168 MW होगी और इसके दो साल में पूरा होने की उम्मीद है। मेटा अपनी बढ़ती AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा-प्रोसेसिंग ज़रूरतों को सपोर्ट करने के लिए कैपेसिटी लीज़ पर लेगा। रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाला और डीसैलिनेटेड समुद्री पानी से ठंडा होने वाला यह प्रोजेक्ट ग्लोबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की बढ़ती अहमियत को दिखाता है। रिलायंस इस प्रोजेक्ट के लिए डिज़ाइन, डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, ऑपरेशन, मटेनेंस और रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन की देखरेख करेगा।
- NASA ने 2027 में होने वाले ऐतिहासिक आर्टेमिस III मिशन के लिए कू की घोषणा कर दी है। मुख्य कू में रैंडी ब्रेसनिक, लुका परमिटानो, आंद्रे डगलस और फ्रैंक रुबियो शामिल हैं, और बॉब हाइन्स बैकअप के तौर पर काम करेंगे। यह मिशन स्पेस लॉन्च सिस्टम (SLS) से लॉन्च किए गए ओरियन स्पेसक्राफ्ट पर ज़रूरी रेंडीज़वस, डॉकिंग, नेविगेशन और कू-ट्रांसफर टेक्नोलॉजी को टेस्ट करेगा। आर्टेमिस III ब्लू ओरिजिन और स्पेसएक्स के लूनर लैंडर सिस्टम के साथ डॉकिंग डेमोंस्ट्रेशन भी करेगा। खास बात यह है कि लुका परमिटानो यूरोपियन स्पेस एजेंसी (ESA) के पहले एस्ट्रोनॉट हैं जिन्हें आर्टेमिस मिशन के लिए भेजा गया है।

- यूनाइटेड स्टेट्स ने लगातार स्पेस वेदर मॉनिटरिंग के लिए अपना पहला डेडिकेटेड सैटेलाइट SOLAR-1 शुरू किया। NOAA द्वारा ऑपरेट किया जाने वाला यह सैटेलाइट फाल्कन 9 पर लॉन्च किया गया था और इसे पृथ्वी से लगभग 1.6 मिलियन किलोमीटर दूर सन-अर्थ L1 पॉइंट पर रखा गया था। एडवांस्ड सेंसर और एक कोरोनाग्राफ से लैस, SOLAR-1 रियल टाइम में सोलर फ्लेयर्स, सोलर विंड और कोरोनाल मास इजेक्शन को मॉनिटर करता है। यह सिस्टम 30 मिनट के अंदर ज़रूरी डेटा भेज सकता है, जिससे सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क, पावर ग्रिड, एविएशन सिस्टम, GPS इंफ्रास्ट्रक्चर और एस्ट्रोनॉट्स को नुकसान पहुंचाने वाले स्पेस वेदर इवेंट्स से बचाने में मदद मिलती है।
- IIT भुवनेश्वर के रिसर्चर्स ने आर्सेनसेफ नाम का एक पोर्टेबल डिवाइस बनाया है, जो बिना लैब की मदद के पीने के पानी में आर्सेनिक कंटैमिनेशन का तेज़ी से पता लगा सकता है। नैनो सेमिक प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर बनाई गई इस टेक्नोलॉजी में बहुत सटीक टेस्टिंग के लिए रिड्यूस्ड ग्रेफीन ऑक्साइड फील्ड-इफेक्ट ट्रांजिस्टर (rGO -FET) सेंसर, नैनोटेक्नोलॉजी और मशीन लर्निंग को मिलाया गया है। यह डिवाइस सिर्फ 17.4 सेकंड में रिज़ल्ट देता है और 11.76 सेकंड में ठीक हो जाता है, जिससे यह ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों के लिए सही है। एनवायर्नमेंटल साइंस: नैनो में पब्लिश हुआ यह इनोवेशन पानी की क्वालिटी मॉनिटरिंग को बेहतर बनाने और आर्सेनिक से जुड़े हेल्थ रिस्क को कम करने के लिए एक सस्ता सॉल्यूशन देता है।
- H3-30 रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो JAXA और मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज द्वारा डेवलप किए गए इसके नेक्स्ट-जेनरेशन H3 लॉन्च व्हीकल का एक कम लागत वाला वेरिएंट है। तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च किए गए इस रॉकेट ने अपने पेलोड को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में डिप्लॉय कर दिया। H-IIA रॉकेट को रिप्लेस करने के लिए डिज़ाइन किया गया H3-30, तीन LE-9 लिक्विड-फ्यूल इंजन का इस्तेमाल करता है और कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट को कम करने के लिए सॉलिड रॉकेट बूस्टर को हटा देता है। 3D-प्रिंटेड कंपोनेंट्स और कमर्शियल टेक्नोलॉजी को शामिल करते हुए, इस रॉकेट से लॉन्च का खर्च लगभग 50% कम होने की उम्मीद है, जिससे ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट में जापान की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी।

- AIIMS, ICMR इंस्टिट्यूट और इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर (IARC) के रिसर्चर्स ने मोलबायो डायग्नोस्टिक्स द्वारा डेवलप किए गए भारत के स्वदेशी HPV स्क्रीनिंग टेस्ट Truenat HR-HPV-Plus को सफलतापूर्वक वैलिडेट किया है। इवैल्यूएट किए गए चार HPV DNA टेस्ट में से, यह WHO और IARC वैलिडेशन स्टैंडर्ड्स को पूरी तरह से पूरा करने वाला एकमात्र स्वदेशी टेस्ट था। यह टेस्ट लगभग 95% सर्वाइकल कैंसर के मामलों के लिए ज़िम्मेदार आठ हाई-रिस्क HPV स्ट्रेन्स का पता लगाता है और दुनिया भर में मान्यता प्राप्त टेस्ट्स के बराबर एक्यूरेसी दिखाता है। 1,159 सर्वाइकल सैंपल्स का इस्तेमाल करके इवैल्यूएट की गई यह सस्ती पॉइंट-ऑफ-केयर टेक्नोलॉजी ग्रामीण इलाकों में स्क्रीनिंग की पहुंच में काफी सुधार कर सकती है और भारत के सर्वाइकल कैंसर को खत्म करने की कोशिशों में मदद कर सकती है।
- अवतार.एआई ने इंडियाएआई मिशन के तहत एक स्वदेशी एआई-संचालित वीडियो जनरेशन मॉडल, वार्या को लॉन्च किया, जो भारत के कृत्रिम बुद्धिमत्ता पारिस्थितिकी तंत्र में एक बड़ी उन्नति का प्रतीक है। वार्या उपयोगकर्ताओं को काफी कम कम्प्यूटेशनल लागत पर टेक्स्ट और छवि इनपुट से उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो बनाने में सक्षम बनाता है, जिसका अनुमान वीडियो जनरेशन के प्रति सेकंड केवल 0.48 रुपये है। यह प्रणाली प्रसंस्करण चरणों को लगभग 50 से घटाकर 4 कर देती है, जिससे यह अग्रणी वैश्विक मॉडलों की तुलना में 10 गुना अधिक कुशल हो जाता है। शिक्षा, शासन, विज्ञापन, एमएसएमई और डिजिटल कहानी कहने में अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया, वार्या बहुभाषी और सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक सामग्री निर्माण का समर्थन करता है। नवाचार आत्मनिर्भर एआई बुनियादी ढांचे की ओर भारत के प्रयास को मजबूत करता है।
- भारत की तेज़ी से बढ़ती स्पेस इकॉनमी के अगले दशक में अभी के USD 8-9 बिलियन से बढ़कर लगभग USD 40-45 बिलियन होने का अनुमान है। RISE कॉन्क्लेव 2026 में बोलते हुए, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लिबरलाइज़ेशन सुधारों और सैटेलाइट, लॉन्च सिस्टम, AI-बेस्ड जियोस्पेशियल एनालिटिक्स और डाउनस्ट्रीम सर्विसेज़ में इनोवेशन को बढ़ावा देने वाले 400 से ज़्यादा स्पेस स्टार्टअप्स की भूमिका पर ज़ोर दिया। चंद्रयान-3 और आने वाले गगनयान मिशन जैसे बड़े मिशनों ने भारत की ग्लोबल स्थिति को मजबूत किया है। स्पेस टेक्नोलॉजी PM गति शक्ति जैसे गवर्नेंस इनिशिएटिव्स को भी सपोर्ट कर रही है, जो विकसित भारत 2047 के विज़न में योगदान दे रही है।
- फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) ने Kali365 के बारे में चेतावनी दी है, जो एक एडवांस्ड फिशिंग-एज-ए-सर्विस (PhaaS) प्लेटफॉर्म है और माइक्रोसॉफ्ट 365 यूजर्स को टारगेट करता है। पासवर्ड चुराने के बजाय, यह प्लेटफॉर्म डिवाइस-कोड ऑथेंटिकेशन अटैक के जरिए OAuth टोकन कैप्चर करता है, जिससे अटैकर मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) को बायपास कर सकते हैं और अकाउंट एक्सेस बनाए रख सकते हैं। Kali365 AI से जेनरेटेड फिशिंग टेम्प्लेट, ऑटोमेटेड टूल और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड देता है, जिससे कम स्किल वाले

क्रिमिनल्स के लिए एडवांस्ड साइबर अटैक एक्सेसिबल हो जाते हैं। यह खतरा क्लाउड-बेस्ड सिस्टम में आइडेंटिटी सिंक्योरिटी, एक्सेस कंट्रोल और साइबर सिंक्योरिटी अवेयरनेस की बढ़ती इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है।

- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे (IIT बॉम्बे) के नेतृत्व में, भारत ने इंडियाएआई मिशन के तहत एक संप्रभु बहुभाषी AI पारिस्थितिकी तंत्र भारतजेन को लॉन्च किया है। ₹ 10,000 करोड़ की सरकारी पहल द्वारा समर्थित, भारतजेन को सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में सामग्री को समझने और उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्लेटफॉर्म स्पीच-टू-टेक्स्ट, टेक्स्ट-टू-स्पीच, डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस और बहुभाषी सामग्री निर्माण जैसी क्षमताओं को एकीकृत करता है। विदेशी AI प्रणालियों पर निर्भरता कम करके, भारतजेन डिजिटल संप्रभुता का समर्थन करता है, स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देता है, और शासन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि और सार्वजनिक सेवाओं में AI अनुप्रयोगों को सक्षम बनाता है।
- उसुतु वायरस (USUV), जो वेस्ट नाइल वायरस और जापानी एन्सेफलाइटिस से जुड़ा एक मच्छर से फैलने वाला फ्लेविवायरस है, पहली बार स्कॉटलैंड में पाया गया है। आइल ऑफ़ एरन पर ब्लैकबर्ड्स में पाया जाने वाला यह वायरस मुख्य रूप से जंगली पक्षियों को प्रभावित करता है और पक्षियों में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और मौत का कारण बन सकता है। इंसानों में इसके इन्फेक्शन बहुत कम होते हैं और आमतौर पर हल्के होते हैं। यह खोज बदलते पर्यावरण और इकोलॉजिकल हालात में वन्यजीवों की निगरानी और उभरती हुई जूनोटिक बीमारियों की मॉनिटरिंग के महत्व को दिखाती है।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) एक उन्नत चंद्र लैंडर विकसित कर रहा है जो चंद्रमा पर 100-200 दिनों तक जीवित रह सकता है, जो चंद्रयान -3 के विक्रम लैंडर से काफी अधिक लंबा है। परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के सहयोग से विकसित, लैंडर -100 डिग्री सेल्सियस से नीचे के चरम चंद्र-रात्रि तापमान का सामना करने के लिए उन्नत थर्मल प्रबंधन प्रणालियों का उपयोग करेगा। परियोजना का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास दीर्घकालिक वैज्ञानिक अध्ययन की सुविधा प्रदान करना है, जिसमें जल बर्फ और चंद्र भूविज्ञान पर अनुसंधान शामिल है। यह भारत के अंतरिक्ष विजन 2047 का समर्थन करता है, जिसमें 2035 तक एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और 2040 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजना शामिल है।
- टेप्लिजुमैव नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) के तहत मंजूर पहली दवा बन गई है जो टाइप 1 डायबिटीज़ की शुरुआत को देर से करती है, जो प्रिवेंटिव हेल्थकेयर में एक बड़ी कामयाबी है। यह इम्प्यूनोथेरेपी 14-दिन के इंद्रावीनस इन्फ्यूजन के जरिए दी जाती है और इंसुलिन बनाने वाली बीटा सेल्स पर इम्प्यून सिस्टम के हमले को धीमा कर देती है, जिससे ज़्यादा जोखिम वाले लोगों में क्लिनिकल डायबिटीज़ लगभग तीन साल तक टल जाती है। पारंपरिक इलाजों के उलट, यह लक्षणों के मैनेजमेंट के बजाय बीमारी के शुरुआती इलाज पर ध्यान देती है। इस मंजूरी से इंसुलिन पर निर्भरता टलने, मुश्किलें कम होने और टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए जल्दी स्क्रीनिंग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

- फाइव आइज़ अलायंस — जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड शामिल हैं — ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से होने वाले साइबर सिक्योरिटी खतरों के बारे में चेतावनी दी है। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी (NSA) और साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी (CISA) जैसी एजेंसियों के सपोर्ट से, इस एडवाइज़री में AI की फ़िशिंग, मैलवेयर क्रिएशन, वल्लरबिलिटी एक्सप्लॉइटेशन और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर अटैक को मज़बूत करने की क्षमता पर ज़ोर दिया गया है। साथ ही, AI वल्लरबिलिटी डिटेक्शन और इंसिडेंट रिस्पॉन्स को बेहतर बना सकता है। अलायंस ने बदलते डिजिटल खतरों से निपटने के लिए मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन, रैपिड सॉफ्टवेयर पैचिंग, रेजिलिएंस टेस्टिंग और मज़बूत साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिस की सलाह दी।
- इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर (IN-SPACE) के ज़रिए एलिजिबल प्राइवेट फर्मों को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (PSLV) टेकनोलॉजी ट्रांसफर करने की घोषणा की, जिससे स्पेस सेक्टर में प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा मिलेगा। फाइनेंशियल और टेक्निकल क्लाइंट्स को पूरा करने वाली क्वालिफाइड भारतीय कंपनियां PSLV-बेस्ड लॉन्च सर्विसेज़ को डेवलप और ऑपरेट करेंगी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (ISRO) 30 महीने तक या दो सफल लॉन्च पूरे होने तक टेक्निकल सपोर्ट देगा। न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) के सपोर्ट से, यह पहल भारत की बढ़ती स्पेस इकॉनमी में कमर्शियलाइजेशन, इनोवेशन और कॉम्पिटिटिवनेस को मज़बूत करती है।
- भारत बेंगलुरु में ISRO और डिपार्टमेंट ऑफ़ स्पेस द्वारा ऑर्गनाइज़ की गई BRICS हेड्स ऑफ़ स्पेस एजेंसीज़ मीटिंग 2026 को होस्ट कर रहा है। सभी 11 BRICS देशों के रिप्रेजेंटेटिव सैटेलाइट एप्लीकेशन, अर्थ ऑब्ज़र्वेशन, स्पेस एक्सप्लोरेशन और नई टेकनोलॉजी में कोऑपरेशन पर चर्चा कर रहे हैं। मुख्य एजेंडा आइटम में स्पेस सस्टेनेबिलिटी, स्पेस डेब्रिस मिटिगेशन, ऑर्बिटल कंजेशन मैनेजमेंट और BRICS रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन का विस्तार शामिल है। डेलीगेट्स सदस्य देशों के बीच टेकनोलॉजी शेयरिंग, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, डिज़ास्टर मैनेजमेंट और कैपेसिटी-बिल्डिंग को मज़बूत करने के लिए BRICS स्पेस

काउंसिल बनाने पर भी विचार कर रहे हैं।

- चीन का लाइनशाइन दुनिया का सबसे तेज़ सुपरकंप्यूटर बन गया है, जो 2.198 एक्सफ्लॉप्स की परफॉर्मेंस के साथ 67वीं TOP500 रैंकिंग में टॉप पर है। शेन्जेन के नेशनल सुपरकंप्यूटिंग सेंटर में इंस्टॉल किया गया, इसने यूनाइटेड स्टेट्स के एल कैपिटन सिस्टम को पीछे छोड़ दिया। CPU-ओनली मशीन में लगभग 13.79 मिलियन प्रोसेसिंग कोर हैं जो एक कस्टम 304-कोर प्रोसेसर से चलता है और लगभग 42.2 मेगावाट बिजली खर्च करता है। प्रति सेकंड दो क्विंटिलियन से ज़्यादा कैलकुलेशन करने में सक्षम, लाइनशाइन 2017 के बाद पहली बार ग्लोबल सुपरकंप्यूटिंग रैंकिंग में टॉप पर चीन की वापसी को दिखाता है।
- दूसरा पैक्स सिलिका समित वाशिंगटन, DC में हुआ, जहाँ भारत समेत 35 देशों ने ज़िम्मेदार और इनोवेशन-फ़्रेडली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए AI के मौके पर जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन किए। US की लीडरशिप वाली यह पहल भरोसेमंद AI गवर्नेंस, मज़बूत सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इंटरनेशनल टेकनोलॉजी कोऑपरेशन पर फोकस करती है। खास घोषणाओं में सुरक्षित AI ट्रेड के लिए पैक्स पास सिस्टम और AI-स्किल्ड प्रोफेशनल्स को डेवलप करने के लिए US फंडिंग से सपोर्टेड फाउंड्री स्कूल शामिल थे। भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेकनोलॉजी मिनिस्ट्री (MeitY) के अधिकारियों के ज़रिए हिस्सा लिया, जिससे ग्लोबल AI गवर्नेंस और डिजिटल पॉलिसी फ्रेमवर्क में उसकी भूमिका मज़बूत हुई।
- भारत ने कॉपर-क्लोरीन साइकिल का इस्तेमाल करके, कलपक्कम में IGCAR में दुनिया की पहली न्यूक्लियर हीट-बेस्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी का उद्घाटन किया। BARC द्वारा डेवलप किया गया, यह क्लीन हाइड्रोजन बनाने के लिए फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर (FBTR) से हीट का इस्तेमाल करता है। यह सिस्टम ज़ीरो-कार्बन फ्यूल बनाता है और भारत के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को सपोर्ट करता है। यह बिजली बनाने के अलावा एडवांस्ड न्यूक्लियर एप्लीकेशन दिखाता है और एनर्जी सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और डीकार्बोनाइजेशन की कोशिशों को बढ़ाता है। यह प्रोजेक्ट भारत को न्यूक्लियर-बेस्ड क्लीन एनर्जी टेकनोलॉजी में लीडर बनाता है।

खेल

- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने फाइनल में गुजरात टाइटन्स को हराकर IPL 2026 का अपना टाइटल सफलतापूर्वक डिफेंड किया। यह जीत विराट कोहली की नाबाद पारी की वजह से मिली, जिन्होंने सफल रन चेज़ में अहम भूमिका निभाई। इस सीज़न के दौरान कई खिलाड़ियों को इंडिविजुअल ऑनर मिले, जो बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग कैटेगरी में शानदार परफॉर्मेंस को दिखाते हैं। इस जीत ने फ्रैंचाइज़ी के लिए एक और माइलस्टोन बनाया और लीग के कॉम्पिटिटिव को बढ़ाते हुए फ्रैंचाइज़ी क्रिकेट के सबसे ऊंचे लेवल पर अपनी कंसिस्टेंसी दिखाई।
- RCB ने चैंपियनशिप मैच में गुजरात टाइटन्स को पांच विकेट से हराकर लगातार अपना दूसरा इंडियन प्रीमियर लीग टाइटल जीता। RCB के शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस ने गुजरात को एक मैनेज करने लायक टोटल तक रोक दिया, जिसके बाद RCB ने सफलतापूर्वक चेज़

किया। दोनों डिपार्टमेंट के खास खिलाड़ियों के योगदान से टीम ने पूरे मैच में कंट्रोल बनाए रखा। इस जीत ने टूर्नामेंट में RCB का दबदबा और पक्का किया और फ्रैंचाइज़ी के रिकॉर्ड में एक और ऐतिहासिक कामयाबी जोड़ी, जबकि गुजरात टाइटन्स ने शुभमन गिल की लीडरशिप में सीज़न का अंत डिज़र्विंग रनर-अप के तौर पर किया।

- भारतीय बैडमिंटन स्टार सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन 2026 मेन्स डबल्स टाइटल जीतकर इतिहास रच दिया। यह जोड़ी एक कड़े फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी को हराकर यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय डबल्स टीम बन गई। इस जीत ने एक बड़े BWF वर्ल्ड टूर टाइटल के लिए दो साल का इंतजार खत्म किया और उनके करियर में एक और बड़ी उपलब्धि जोड़ दी। उनकी सफलता इंटरनेशनल बैडमिंटन में भारत की बढ़ती साख को मज़बूत करती है और ग्लोबल लेवल पर डबल्स इवेंट्स में देश की बढ़ती कॉम्पिटिटिवनेस को दिखाती है।

- इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने गवर्नर्स और मॅबरशिप के गंभीर उल्लंघन की वजह से क्रिकेट कनाडा को सस्पेंड कर दिया। यह फैसला गवर्नर्स में गडबडी, एडमिनिस्ट्रेटिव गलत काम और इंस्टीट्यूशनल अस्थिरता से जुड़ी चिंताओं के बाद लिया गया। सस्पेंशन के बावजूद, कनाडा की पुरुष और महिला टीमों ICC की देखरेख में इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए एलिजिबल हैं। क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए लगातार फंडिंग पर ICC नज़र रखेगा, जबकि इसे फिर से शुरू करना गवर्नर्स सुधारों को लागू करने, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के तरीकों और इंटरनेशनल क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन स्टैंडर्ड के पालन पर निर्भर करेगा।
- हीरो मोटोकॉर्प ने भारत की पहली फ्लेक्स-फ्यूल मोटरसाइकिल, स्लेंडर प्लस फ्लेक्स फ्यूल और HF डीलक्स फ्लेक्स फ्यूल लॉन्च की हैं। ये बाइक E20 से E85 इथेनॉल ब्लेंड पर चलती हैं, जिससे फ्यूल इंपोर्ट और कार्बन एमिशन कम होता है। 97.2cc इंजन से चलने वाली ये बाइक भारत के बायोफ्यूल और क्लीन मोबिलिटी लक्ष्यों को सपोर्ट करती हैं। जुलाई 2026 में इनकी बिक्री शुरू होगी, जो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट में एक बड़ा कदम है।
- इंडियन ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञानंद ने क्लासिकल चैस में मैग्रस कार्लसन को तीन बार हराया, जिसमें नौवें चैस 2026 में दो बार शामिल है। इस कामयाबी ने उन्हें दुनिया के एलीट प्लेयर्स में शामिल कर दिया है। एक पुराने शतरंज के टैलेंटेड खिलाड़ी और बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट के विनर, वह ग्लोबल चैस एक्सीलेंस में इंडिया की जगह को मज़बूत कर रहे हैं।
- पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जो योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट के तौर पर पहचान दिलाने के लिए दुनिया भर में एक कोशिश है। यह इवेंट इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देता है और फिटनेस, डिसिप्लिन और पूरी सेहत में योग के रोल पर रोशनी डालता है। यह योग को एक ग्लोबल स्पोर्टिंग डिसिप्लिन के तौर पर बढ़ावा देने में भारत की कल्चरल लीडरशिप को मज़बूत करता है।
- आर. प्रज्ञानंद नौवें चैस 2026 का टाइटल जीतने वाले पहले भारतीय बने, उन्होंने मैग्रस कार्लसन समेत दुनिया के टॉप खिलाड़ियों को दो बार हराया। उनकी जीत भारतीय चैस के इतिहास में एक बड़ा मील का पत्थर है, जो दुनिया भर के चैस में भारत के बढ़ते दबदबे को दिखाता है और इंटरनेशनल खेलों में भारत की साख को मज़बूत करता है।
- काकामिगाहारा में हुए फाइनल में मेज़बान देश जापान को 4-1 से हराकर भारत पुरुषों के U18 एशिया कप 2026 का चैंपियन बना। भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और अटैकिंग ताकत दिखाई। फाइनल में उनके ज़बरदस्त प्रदर्शन ने गोल्ड मेडल पक्का किया, जबकि जापान को सिल्वर और पाकिस्तान को ब्रॉन्ज़ मेडल मिला। यह जीत यूथ हॉकी में भारत की बढ़ती ताकत को दिखाती है और इसके ज़मीनी स्तर के डेवलपमेंट प्रोग्राम की सफलता को दिखाती है। इस जीत ने भारत को एशियाई हॉकी में U18 लेवल पर लीडिंग टीम बना दिया है।
- फाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर SAFF विमेंस चैंपियनशिप 2026 जीती। इस जीत ने भारत का टाइटल के

लिए सात साल का इंतज़ार खत्म किया और रिकॉर्ड छठी बार SAFF विमेंस चैंपियनशिप का ताज हासिल किया। प्यारी ज़ाक्सा, सैनफिदा के गोल। नॉगुम और लिंडा कोम सेटों ने जीत पक्की कर दी। भारत पूरे टूर्नामेंट में बिना हारे रहा, उसने चारों मैच जीते, 18 गोल किए और सिर्फ़ एक गोल खाया। सैनफिदा नॉगुम को MVP चुना गया, पंथोई चानू एलांगबाम को बेस्ट गोलकीपर चुना गया, और अवेका सिंह टूर्नामेंट की टॉप स्कोरर रहीं।

- इटैलियन ड्राइवर किमी एंटोनेली ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 जीता, इस सीज़न में अपनी लगातार पांचवीं Formula 1 जीत हासिल की और ड्राइवर्स चैंपियनशिप स्टैंडिंग में अपनी बढ़त बढ़ाई। पोल पोर्जीशन से शुरुआत करते हुए, मर्सिडीज ड्राइवर ने देर से रेड फ्लैग और स्टैंडिंग रीस्टार्ट के बावजूद शुरू से आखिर तक रेस को कंट्रोल किया। लुईस हैमिल्टन फेरारी के लिए दूसरे स्थान पर रहे, जबकि इसाक हज़र ने तीसरा स्थान हासिल किया। चैंपियनशिप के दावेदार मैक्स वर्स्टापेन और लैंडो नॉरिस ने रेस से रिटायरमेंट ले लिया, जिससे एंटोनेली के टाइटल जीतने की उम्मीदें और मजबूत हो गईं। मोनाको Formula 1 के सबसे प्रतिष्ठित और डिमांडिंग सर्किट में से एक बना हुआ है।
- पेरिस के रोलैंड-गैरोस में फ्रेंच ओपन 2026 में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां देखने को मिलीं। अलेक्जेंडर ज़ेबरेव ने पुरुषों की सिंगल्स चैंपियनशिप जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता, जबकि 19 साल की मीरा एंड्रीवा ने महिलाओं के सिंगल्स में अपना पहला ग्रैंड स्लैम ताज हासिल किया। डबल्स में, मार्सेल ग्रेनोल्स और होरासियो ज़ेबालोस ने पुरुषों का खिताब सफलतापूर्वक बचाया, जबकि कैटरिना सिनियाकोवा और टेलर टाउनसेंड ने महिलाओं की डबल्स चैंपियनशिप जीती। मिक्स्ड डबल्स में, सारा एरानी और एंड्रिया वावसोरी ने अपना खिताब बरकरार रखा, जो 2019 के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली जोड़ी बन गई।
- EKA एरिना में आयोजित पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में ओवरऑल चैंपियन बना। भारतीय दल ने कॉम्पिटिशन में अपना दबदबा बनाया, और 102 गोल्ड, 9 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज़ मेडल सहित 114 मेडल के साथ मेडल टेबल में टॉप पर रहा। चैंपियनशिप में 79 देशों के 522 एथलीटों ने ट्रेडिशनल, आर्टिस्टिक, रिदमिक और स्पेशलाइज़्ड योगासन इवेंट्स में हिस्सा लिया। जापान दूसरे नंबर पर रहा, जबकि अर्जेंटीना ने तीसरा स्थान हासिल किया। इस इवेंट ने योगासन की बढ़ती ग्लोबल एक्सेप्टेंस को हाईलाइट किया और दुनिया भर में अपनी पुरानी योग विरासत को बढ़ावा देने में भारत की लीडरशिप को मज़बूत किया।
- भारतीय शतरंज खिलाड़ी सविता श्री भास्कर ने नौ राउंड में 7.5 पॉइंट्स के बिना हारे प्रदर्शन के बाद मंगोलिया के उलानबटार में एशियन महिला इंडिविजुअल शतरंज चैंपियनशिप 2026 जीत ली। छठी सीड के तौर पर टूर्नामेंट में उतरते हुए, उन्होंने टॉप कॉम्पिटिटर्स के खिलाफ शानदार कंसिस्टेंसी और धैर्य दिखाया। हालांकि वह उज़्बेकिस्तान की अफरुज़ा खामदापोवा के बराबर पॉइंट्स पर रहीं, लेकिन उन्होंने बेहतर टाईब्रेक स्कोर के ज़रिए गोल्ड मेडल हासिल किया। यह जीत उनके शतरंज करियर की सबसे बड़ी कामयाबी है और इससे उन्हें FIDE महिला वर्ल्ड कप 2027 के लिए क्वालिफ़ाई करने में मदद मिली, जिससे इंटरनेशनल महिला शतरंज में भारत की बढ़ती मौजूदगी और मज़बूत हुई।

- न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन ने 16 साल के शानदार करियर के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की। उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट में एक शानदार विरासत छोड़ी है। उन्होंने 110 मैचों में 54 से ज्यादा की औसत से 9,515 टेस्ट रन बनाए, साथ ही ODI और T20I में भी अहम योगदान दिया। कप्तान के तौर पर, उन्होंने न्यूजीलैंड को 2021 ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जीत दिलाई, जो देश की सबसे बड़ी खेल उपलब्धियों में से एक है। विराट कोहली, स्टीव स्मिथ और जो रूट के साथ क्रिकेट के "फैब फोर" का हिस्सा माने जाने वाले विलियमसन अपनी टेक्निकल काविलियत, लगातार अच्छा खेलने, लीडरशिप और खेल भावना के लिए जाने जाते थे। उनके रिटायरमेंट से न्यूजीलैंड क्रिकेट में एक युग का अंत हुआ है और इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास पर इसका गहरा असर पड़ा है।
- सात बार के फॉर्मूला वन चैंपियन लुईस हैमिल्टन ने बार्सिलोना-कैटालुन्या ग्रैंड प्रिक्स 2026 में स्कुडेरिया फरारी के लिए अपनी पहली जीत हासिल की, जिससे मर्सिडीज़ का हालिया दबदबा खत्म हो गया। हैमिल्टन ने जॉर्ज रसेल से आगे रहने के लिए एक सफल थ्री-स्टॉप स्ट्रैटेजी अपनाई, जबकि लैंडो नॉरिस ने तीसरा स्थान हासिल किया, जिससे 1968 के बाद पहला ऑल-ब्रिटिश पोजिशन बना। चैंपियनशिप के दावेदार किमी एंटोनेली टेक्निकल दिक्कतों की वजह से देर से रिटायर हुए, जिससे टाइटल की रेस और तेज़ हो गई। यह नतीजा फरारी की वापसी को दिखाता है और हैमिल्टन के चैंपियनशिप कैंपेन को और तेज़ी देता है।
- केंद्र सरकार ने नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस (NSG) एक्ट, 2025 के तहत एक सर्च-कम-सिलेक्शन कमेटी बनाई है, जो नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड के लिए कैंडिडेट रिकमेंड करेगी। टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता वाली इस कमेटी में जाने-माने स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी और एडमिनिस्ट्रेटर शामिल हैं। प्रस्तावित बोर्ड भारत के सबसे बड़े स्पोर्ट्स गवर्नेंस रेगुलेटर के तौर पर काम करेगा, जो स्पोर्ट्स फेडरेशन, गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स, फाइनेंशियल ट्रांसपैरेंसी और एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन की देखरेख करेगा। यह पहल देश में ज्यादा ट्रांसपैरेंट, प्रोफेशनल और अकाउंटेबल स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
- स्मृति मंधाना TIME100 मोस्ट इन्फ्लुएंसियल पीपल इन स्पोर्ट्स 2026 लिस्ट में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय एथलीट बन गईं। इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी असाधारण उपलब्धियों के लिए पहचानी जाने वाली, वह तीनों फॉर्मेट— टेस्ट, ODI और T20I में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। मंधाना महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक बनाने का रिकॉर्ड भी शेयर करती हैं और उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फ्रेंचाइजी की कप्तान के तौर पर काफी सफलता हासिल की है। उनका शामिल होना महिला क्रिकेट के बढ़ते ग्लोबल प्रभाव और इस खेल में भारत की प्रमुखता को दिखाता है।
- दीप्ति शर्मा ने ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान अपना 355वां इंटरनेशनल विकेट लेकर विमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के रिकॉर्ड की बराबरी की। अब वह झूलन गोस्वामी और कैथरीन साइवर-ब्रंट के साथ यह रिकॉर्ड शेयर करती हैं। यह उपलब्धि दीप्ति की कंसिस्टेंसी, लंबे समय तक खेलने और भारतीय क्रिकेट के लिए उनके महत्व को दिखाती है, जिससे विमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की बढ़ती रेप्युटेशन और मज़बूत होती है।
- ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (IOA) के साथ मिलकर डोपिंग के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए क्लीन स्पोर्ट्स कैंपेन शुरू किया। इस पहल में एथलीट के नेतृत्व में आउटरीच, वर्कशॉप, डिजिटल एजुकेशन टूल और जमीनी स्तर के प्रोग्राम शामिल हैं। इसका मकसद एथलीटों को बैन की गई चीजों के बारे में जानकारी देना, नैतिक खेल के तरीकों को बढ़ावा देना और भारत की खेल में पहचान को मजबूत करना है, खासकर तब जब देश 2036 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करने के अपने सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहा है।
- हरमनप्रीत कौर मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत के महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 मैच के दौरान 200 T20 इंटरनेशनल (T20I) खेलने वाली पहली क्रिकेटर बनीं, चाहे वह पुरुष हो या महिला। 2009 में अपने इंटरनेशनल डेब्यू के बाद से, उन्होंने लगातार अच्छे प्रदर्शन और असरदार लीडरशिप से खुद को भारत की सबसे अच्छी कप्तानों और बल्लेबाजों में से एक के रूप में स्थापित किया है। इस माइलस्टोन मैच से पहले, उन्हें हेड कोच अमोल मजूमदार और उप-कप्तान स्मृति मंधाना ने सम्मानित किया। यह उपलब्धि उनकी लंबी उम्र, कंसिस्टेंसी, लीडरशिप और महिला क्रिकेट में उनके बहुत बड़े योगदान को दिखाती है।
- भारतीय महिला हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर FIH नेशंस कप 2026 जीता 21 जून 2026 को फाइनल में 2-0 से जीत मिली। नवनीत कौर और सुनीता टोप्पो ने विजयी गोल किए, जिससे भारत को 2022 में पहली जीत के बाद अपना दूसरा नेशंस कप खिताब जीतने में मदद मिली। भारत पूरे टूर्नामेंट में अजेय रहा, उसने अमेरिका, जापान, उरुग्वे, चिली और न्यूजीलैंड को हराया। इस जीत ने भारत को प्रतिष्ठित FIH प्रो लीग में प्रमोशन दिलाया, जिससे उसे ज्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला और दुनिया की महिला हॉकी में देश की स्थिति मजबूत हुई।
- टीनएज बैटर वैभव सूर्यवंशी ने इंडिया A और श्रीलंका A के बीच रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम में ट्राई-सीरीज़ फाइनल के दौरान सिर्फ 11 गेंदों में हाफ सेंचुरी बनाकर लिस्ट-A का सबसे तेज़ फिफ्टी बनाया। उन्होंने 12 गेंदों में हाफ सेंचुरी बनाने का पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, जो 2005-06 से कौशल्या वीरत्ते के नाम था। उनकी ज़बरदस्त पारी ने काफ़ी शांत टूर्नामेंट के बाद मैच का रुख बदल दिया और क्रिकेट एक्सपर्ट्स से खूब तारीफ़ पाई। इस शानदार कामयाबी ने सूर्यवंशी को इंडिया के सबसे होनहार युवा बैटिंग टैलेंट में से एक बना दिया, जिनमें भविष्य की बहुत संभावनाएँ हैं।
- अर्जेटीना ने न्यूक्लेन प्रांत के मैनुअल सैवियो में फुटबॉल के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। 26 मीटर ऊंची और लगभग 70 टन वज़नी इस स्मारक में मेसी को अर्जेटीना की नेशनल जर्सी पहने हुए FIFA वर्ल्ड कप ट्रॉफी पकड़े हुए दिखाया गया है। अर्जेटीना के कलाकार एल्डो बेरोइसा द्वारा डिज़ाइन की गई यह संरचना मेसी की उपलब्धियों का जश्र मनाती है, जिसमें 2022 FIFA वर्ल्ड कप जीत भी शामिल है। फुटबॉल के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक को सम्मान देने के अलावा, इस स्मारक से टूरिज्म, स्थानीय आर्थिक गतिविधि और खेल विरासत के माध्यम से अर्जेटीना की सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

• लियोनेल मेसी 2026 FIFA वर्ल्ड कप के दौरान ऑस्ट्रिया के खिलाफ दो गोल करके FIFA वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए, जिससे उनके गोलों की संख्या 18 हो गई और उन्होंने मिरोस्लाव क्लोस के 16 गोलों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। इससे पहले, मेसी ने अल्जीरिया के खिलाफ हैट्रिक भी बनाई, जिससे टूर्नामेंट में उनके पांच गोल हो गए। उनका वर्ल्ड कप का सफर 2006 से 2026 तक है, जिसमें 2022 का एडिशन उनका सबसे शानदार रहा। इस मील के पत्थर ने अर्जेंटीना के कैंपेन को मज़बूत किया और मेसी की शानदार फुटबॉल विरासत को और मज़बूत किया।

• क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2026 FIFA वर्ल्ड कप के दौरान छह अलग-अलग FIFA वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बनकर फुटबॉल इतिहास रच दिया। उन्होंने यह उपलब्धि पुर्तगाल की उज़्बेकिस्तान पर 5-0 की जीत के दौरान हासिल की, जिसमें उन्होंने दो गोल किए। 41 साल और 138 दिन की उम्र में, रोनाल्डो वर्ल्ड कप के इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन गए। उनके गोलों ने वर्ल्ड कप में उनके गोलों की संख्या 10 कर दी, जिससे उन्होंने पुर्तगाली दिग्गज यूसेबियो के नौ गोलों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, जिससे फुटबॉल के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक के रूप में उनकी पहचान और मज़बूत हुई।

पुस्तकें और लेखक

भारत का ओलंपिक गोल्ड: एमस्टर्डम में हॉकी की जीत जारी

भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की अध्यक्ष पीटी उषा और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप टिकी ने नई दिल्ली में इंडियाज़ ओलंपिक गोल्ड: हॉकी ट्रायम्फ एट एमस्टर्डम नामक पुस्तक का विमोचन किया। प्रसिद्ध हॉकी इतिहासकार के. अरुमुगम द्वारा लिखित इस पुस्तक को हॉकी इंडिया और स्टिक2हॉकी द्वारा हॉकी में भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक की 98वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रकाशित किया गया था। यह 1928 के एमस्टर्डम ओलंपिक में भारत की ऐतिहासिक जीत को याद करता है, जहां भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान नीदरलैंड को हराकर अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। लॉन्च समारोह में दिग्गज हॉकी खिलाड़ी हरबिंदर सिंह, जगबीर सिंह, जफर इकबाल और अशोक कुमार ने भाग लिया, जबकि यह प्रकाशन भारतीय हॉकी इतिहास पर के. अरुमुगम द्वारा लिखित 16वीं पुस्तक है।

एयर चीफ ने एस्ट्रोनाट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की याद में लिखी किताब जारी की

वायु सेना प्रमुख, एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने नई दिल्ली में संस्मरण द सेकंड ऑर्बिट: बिलीफ ऑफ ए मैन... ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हार्ट्स का विमोचन किया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला द्वारा लिखित इस संस्मरण में

भारतीय वायु सेना के लड़ाकू पायलट से लेकर अंतरिक्ष यात्री बनने तक की उनकी प्रेरक यात्रा का वर्णन है, जो एक्सओम-4 मिशन के हिस्से के रूप में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) के उनके ऐतिहासिक मिशन के साथ समाप्त हुई। पुस्तक के विमोचन के अवसर पर एक्सओम-4 मिशन की पहली वर्षगांठ भी मनाई गई, जिसे 25 जून को प्रक्षेपित किया गया था, जिसमें मानव अंतरिक्ष उड़ान के क्षेत्र में भारत की बढ़ती उपलब्धियों और आकांक्षाओं पर प्रकाश डाला गया।

उपराष्ट्रपति ने भवैया लोक संगीत विरासत पर पुस्तक का विमोचन किया
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने संस्कृति रत्न भंडार : भौवैयार पुस्तक का विमोचन किया इतिब्रिटो (भवैया : एक सांस्कृतिक खजाना और इसकी ऐतिहासिक यात्रा) का विमोचन उपराष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में किया गया। यह किताब उत्तर बंगाल, असम और आस-पास के इलाकों से जुड़े पारंपरिक लोक संगीत शैली भवैया की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक विकास के बारे में बताती है। इस कार्यक्रम में बोलते हुए, उपराष्ट्रपति ने भारत की अलग-अलग लोक परंपराओं को बचाए रखने के महत्व पर जोर दिया और कहा कि देश की सांस्कृतिक विरासत को बचाना इसकी सभ्यता की पहचान को मज़बूत करने और इन अनमोल परंपराओं को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी है।

निधन

राजा रणधीर सिंह का 79 साल की उम्र में निधन हो गया

मशहूर भारतीय शूटर, पांच बार के ओलंपियन और अनुभवी स्पॉर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर राजा रणधीर सिंह का 79 साल की उम्र में नई दिल्ली में निधन हो गया। 18 अक्टूबर 1946 को पंजाब के पटियाला में जन्मे, वे भारत के सबसे काबिल शूटर में से एक थे और उन्होंने पांच ओलंपिक गेम्स — मेक्सिको सिटी (1968), म्यूनिख (1972), मॉन्ट्रियल (1976), मॉस्को (1980), और लॉस एंजिल्स (1984) में देश को रिप्रेजेंट किया था। उन्होंने 1964 के टोक्यो ओलंपिक्स में रिज़र्व शूटर के तौर पर भी काम किया था।

1978 के एशियन गेम्स में मेन्स ट्रैप शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया, और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय शूटर बने। 1979 में अर्जुन अवॉर्ड से सम्मानित, उन्होंने बाद में इंडियन ओलंपिक

एसोसिएशन (IOA) के सेक्रेटरी जनरल के तौर पर काम किया और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया (OCA) के पहले भारतीय प्रेसिडेंट बने। एक एथलीट और स्पॉर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर, दोनों के तौर पर उनका योगदान बेमिसाल है।

केपी धनपालन का 76 साल की उम्र में निधन हो गया

कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व सांसद केपी धनपालन का 76 साल की उम्र में केरल में निधन हो गया। केरल स्टूडेंट्स यूनियन (KSU) से अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करने के बाद, वे बाद में एक जाने-माने कांग्रेस लीडर बने और 15वीं लोकसभा (2009-2014) में चालकुडी चुनाव क्षेत्र को रिप्रेजेंट किया। उन्होंने एनाकुलम डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी (DCC) के प्रेसिडेंट और MILMA के चेयरमैन के तौर पर भी काम किया, और केरल के पॉलिटिकल और कोऑपरेटिव सेक्टर में अहम योगदान दिया।

सुमन कल्याणपुर का 89 साल की उम्र में निधन हो गया

मशहूर प्लेबैक सिंगर सुमन कल्याणपुर का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। वे इंडियन म्यूज़िक में एक शानदार विरासत छोड़ गई हैं। अपनी सुरीली आवाज़ के लिए मशहूर, वे 1960 और 1970 के दशक की सबसे सम्मानित सिंगर्स में से एक थीं और उन्होंने हिंदी, मराठी और कई रीजनल फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ में बहुत बड़ा योगदान दिया। 1954 में अपने प्लेबैक करियर की शुरुआत करते हुए, वे टाइमलेस गानों और मोहम्मद रफ़ी के साथ यादगार डुएट के लिए मशहूर हुईं। फ़िल्म म्यूज़िक के अलावा, उन्होंने भक्ति गीतों, ग़ज़लों और ठुमरियों में भी बेहतरीन काम किया। 2023 में, उन्हें इंडियन म्यूज़िक में उनके शानदार योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।

पीबो ब्रायसन का 75 साल की उम्र में निधन हो गया

मशहूर R&B सिंगर पीबो ब्रायसन, जो दो बार ग्रैमी अवॉर्ड जीत चुके थे, 75 साल की उम्र में गुज़र गए। "ए होल न्यू वर्ल्ड" और "ब्यूटी एंड द बीस्ट" जैसे डिज़्नी क्लासिक्स के लिए सबसे ज्यादा जाने जाने वाले, वे आज के R&B की जानी-मानी आवाज़ों में से एक बन गए। 1970 के दशक में अपने करियर की शुरुआत करते हुए, उन्होंने रॉबर्टा फ्लैक और एंजेलो बोफिल जैसे मशहूर कलाकारों के साथ काम किया, और एक हमेशा रहने वाली म्यूज़िकल विरासत छोड़ गए।

मार्सिया लुकास का 80 साल की उम्र में निधन हो गया

एकेडमी अवार्ड विजेता फिल्म एडिटर मार्सिया लुकास का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें ओरिजिनल स्टार वार्स ट्रायोलॉजी के संपादन के लिए जाना जाता था, उन्होंने स्टार वार्स: एपिसोड IV - ए न्यू होप के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन का एकेडमी अवार्ड जीता था। उन्होंने अमेरिकन ग्रैफ़िटी और टैक्सी ड्राइवर पर भी काम किया। उनकी अग्रणी संपादन शैली ने आधुनिक सिनेमाई कहानी और हॉलीवुड फिल्म निर्माण को काफी प्रभावित किया।

पहलाज निहलानी का 76 साल की उम्र में निधन हो गया

CBFC के पूर्व चेयरपर्सन पहलाज निहलानी का 76 साल की उम्र में लिवर से जुड़ी बीमारी की वजह से निधन हो गया। उन्होंने इल्ज़ाम, आँखें, आग ही आग और रंगीला राजा जैसी कई सफल फ़िल्में बनाईं, और एक्टर गोविंदा का बॉलीवुड करियर भी शुरू किया। उन्होंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फ़िल्म सर्टिफ़िकेशन (2015-2017) के चेयरपर्सन के तौर पर काम किया और भारतीय सिनेमा में एक जाने-माने लेकिन विवादित इंसान बने रहे।

डॉ. सुभाष सी. कश्यप का 97 साल की उम्र में निधन हो गया

पूर्व लोकसभा सेक्रेटरी-जनरल और जाने-माने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट डॉ. सुभाष सी. कश्यप का 97 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें भारतीय संविधान और पार्लियामेंट्री सिस्टम के जाने-माने एक्सपर्ट के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने 100 से ज्यादा किताबें लिखीं और "वन नेशन, वन इलेक्शन" पहल सहित कॉन्स्टिट्यूशनल सुधारों में अहम भूमिका निभाई। उनका काम स्टूडेंट्स, लॉमेकर्स और सिविल सर्विस की तैयारी करने वालों के लिए एक बहुत कीमती रिसोर्स के तौर पर काम करता है।

बलविंदर सिंह धालीवाल का 67 साल की उम्र में निधन हो गया

अर्जुन अवॉर्ड और एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले शॉट पुटर बलविंदर सिंह धालीवाल का 67 साल की उम्र में निधन हो गया। 10 बार के नेशनल

चैंपियन, उन्होंने 1982 के एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज़ मेडल जीता, 1986 में एशियन रिकॉर्ड बनाया और बाद में युवा एथलीटों को कोचिंग देने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उनके शानदार योगदान के लिए उन्हें अर्जुन अवॉर्ड, महाराजा रणजीत सिंह अवॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स में जगह मिली।

जगन्नाथ प्रसाद दास का 90 साल की उम्र में निधन हो गया

प्रख्यात ओडिया लेखक, पूर्व IAS अधिकारी और प्रतिष्ठित सांस्कृतिक व्यक्तित्व जगन्नाथ प्रसाद दास का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने ओडिया साहित्य, सार्वजनिक प्रशासन और सामाजिक कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, विशेष रूप से कालाहांडी में अकाल राहत पहल के माध्यम से, जिससे पूरे ओडिशा में व्यापक सम्मान अर्जित किया।

मरजाने सत्रापी का 56 साल की उम्र में निधन हो गया

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित ग्राफ़िक उपन्यासकार, फिल्म निर्माता और चित्रकार मरजाने सत्रापी का 56 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अपनी आत्मकथात्मक ग्राफ़िक उपन्यास पर्सेपोलिस के लिए सबसे ज्यादा जानी जाने वाली, उन्होंने पहचान, क्रांति, स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के विषयों की खोज की, जिससे वैश्विक साहित्य और सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ी।

ए.सी. श्रीहरि का 56 साल की उम्र में निधन हो गया

प्रसिद्ध मलयालम कवि, शिक्षाविद और साहित्यिक आलोचक ए.सी. श्रीहरि का 56 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आधुनिक मलयालम कविता, साहित्यिक आलोचना और उच्च शिक्षा में उनके योगदान ने केरल के साहित्यिक और शैक्षणिक परिदृश्य को समृद्ध किया।

सलीम कुमार का 56 साल की उम्र में निधन हो गया

मशहूर मलयालम एक्टर, कॉमेडियन, राइटर और फिल्ममेकर सलीम कुमार का 56 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने एक मिमिक्री आर्टिस्ट के तौर पर अपना करियर शुरू किया, और 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और मलयालम सिनेमा के सबसे अच्छे कलाकारों में से एक बन गए। उन्होंने 'आदमिंते मकान अबू' के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवॉर्ड जीता और कई केरल स्टेट फिल्म अवॉर्ड्स जीते, और इंडियन सिनेमा में एक शानदार विरासत छोड़ गए।

भारतीराजा का 84 साल की उम्र में निधन हो गया

मशहूर फिल्ममेकर भारतीराजा का 84 साल की उम्र में चेन्नई में निधन हो गया। तमिल सिनेमा में गांव की कहानी कहने के पायनियर माने जाने वाले भारतीराजा ने गांव की ज़िंदगी को असली तरीके से दिखाकर भारतीय फिल्ममेकिंग को बदल दिया। कई दशकों के करियर में, उन्होंने 40 से ज्यादा फिल्मों में डायरेक्ट कीं, छह नेशनल फिल्म अवॉर्ड जीते, कई फिल्मफेयर अवॉर्ड साउथ और कई तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवॉर्ड जीते, और भारत के सबसे महान फिल्ममेकरों में से एक बन गए।

जसपाल राणा का 49 साल की उम्र में निधन हो गया

पद्म श्री, अर्जुन अवॉर्ड और द्रोणाचार्य अवॉर्ड पाने वाले जसपाल राणा का 49 साल की उम्र में निधन हो गया। भारत के सबसे मशहूर पिस्टल शूटर में से एक, उन्होंने एक बहुत सम्मानित शूटिंग कोच बनने से पहले एशियन गेम्स और एशियन चैंपियनशिप में कई मेडल जीते। हाई-परफॉर्मेंस पिस्टल कोच के तौर पर, उन्होंने मनु भाकर और सौरभ चौधरी जैसे एथलीटों को गाइड किया, और भारत की इंटरनेशनल शूटिंग में सफलता में अहम भूमिका निभाई।

डेविड हॉकनी का 88 साल की उम्र में निधन हो गया

मशहूर ब्रिटिश कंटेम्पररी आर्टिस्ट डेविड हॉकनी का 88 साल की उम्र में लंदन में निधन हो गया। **पाँप आर्ट मूवमेंट** के एक जाने-माने व्यक्ति, वे अपनी शानदार स्विमिंग पूल पेंटिंग, फोटोग्राफी, कोलाज, स्टेज डिजाइन और नए डिजिटल आर्टवर्क के लिए दुनिया भर में मशहूर हुए। उनके आर्टिस्टिक इनोवेशन दुनिया भर में कंटेम्पररी आर्ट को प्रभावित करते रहते हैं।

फ्रांस्वा एंगलर्ट का 93 साल की उम्र में निधन हो गया

बेल्जियम के थ्योरेटिकल फ़िज़िसिस्ट और **2013 के नोबेल प्राइज़** विजेता फ़्रांस्वा एंगलर्ट का 93 साल की उम्र में निधन हो गया। **पीटर हिग्स** के साथ, उन्होंने **ब्राउट-एंगलर्ट-हिग्स मैकेनिज़्म डेवलप किया**, जिसमें बताया गया कि फंडामेंटल पार्टिकल्स हिग्स फ़ील्ड के ज़रिए कैसे मास हासिल करते हैं। **2012 में CERN में हिग्स बोसोन** की खोज से इस थ्योरी की एक्सपेरिमेंटली पुष्टि हुई, जो मॉडर्न पार्टिकल फ़िज़िक्स में सबसे बड़े माइलस्टोन में से एक बन गया।

लेफ्टिनेंट जनरल विजय ओबेरॉय का 84 साल की उम्र में निधन हो गया

पूर्व उप सेना प्रमुख (VCOAS) लेफ्टिनेंट जनरल विजय ओबेरॉय का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। **1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध** के दौरान अपना दाहिना पैर खोने के बावजूद, वे भारतीय सेना के सबसे सम्मानित अधिकारियों में से एक बन गए। उन्होंने कारगिल के बाद सैन्य सुधारों में अहम भूमिका निभाई, **DGMO** और **वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ** के तौर पर काम किया, और बाद में **सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़ (CLAWS)** और **वॉर वुंडेड फाउंडेशन** की स्थापना की।

रॉबर्ट एएफ थर्मन का 84 साल की उम्र में निधन हो गया

तिब्बती बौद्ध धर्म के जाने-माने अमेरिकी विद्वान और पद्म श्री अवार्डी **रॉबर्ट एएफ थर्मन** का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। एक जाने-माने लेखक,

शिक्षक और ट्रांसलेटर, वे **14वें दलाई लामा** के तहत **तिब्बती बौद्ध परंपरा में दीक्षित होने वाले पहले अमेरिकी** बने। उन्होंने **20 से ज़्यादा किताबें लिखीं, तिब्बत हाउस US** को-फाउंड किया, और **बौद्ध स्टडीज़ और लिटरेचर** को बढ़ावा देने के लिए **2020 में पद्म श्री** से सम्मानित हुए।

कृष्णस्वामी भाग्यराज का 73 साल की उम्र में निधन हो गया

जाने-माने तमिल फिल्ममेकर, एक्टर, स्क्रीनराइटर और डायरेक्टर **कृष्णस्वामी भाग्यराज** का 73 साल की उम्र में निधन हो गया। **"स्क्रीनप्ले किंग"** के नाम से मशहूर, उन्होंने **25 से ज़्यादा फिल्में डायरेक्ट कीं, 75 से ज़्यादा फिल्मों में** एक्टिंग की और अपनी अनोखी कहानी कहने की स्टाइल से फिल्ममेकर्स की कई पीढ़ियों को प्रभावित किया।

राजकुमारी बजरकितियाभा माहिडोल का 47 साल की उम्र में निधन हो गया

थाईलैंड की **राजकुमारी बजरकितियाभा माहिडोल** का 47 साल की उम्र में निधन हो गया। **UN की गुडविल एंबेसडर** होने के नाते, उन्हें **न्याय सुधार, जेल रिहैबिलिटेशन और महिलाओं के अधिकारों** में उनके काम के लिए **इंटरनेशनल लेवल पर पहचान** मिली। उन्होंने **UN बैंकॉक रूल्स** को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई और जेल में बंद महिलाओं की भलाई के लिए **कामलांगजई कैपेन** शुरू किया।

गवरी देवी का 98 साल की उम्र में निधन हो गया

मशहूर **मांड लोक गायिका गवरी देवी** का 98 साल की उम्र में **राजस्थान** में निधन हो गया। **"केसरिया बालम"** गाने के लिए जानी जाने वाली, उन्होंने राजस्थान की समृद्ध लोक संगीत परंपरा को बचाने के लिए लगभग **आठ दशक समर्पित किए**। भारतीय लोक संगीत में उनके शानदार योगदान के लिए उन्हें **संगीत नाटक अकादमी अवॉर्ड, राजस्थान रत्न अवॉर्ड** और कई लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड मिले।

महत्वपूर्ण दिन

तारीख	दिन / पालन	थीम / विवरण
2 जून	तेलंगाना स्थापना दिवस	2014 में भारत के 29वें राज्य के तौर पर तेलंगाना के बनने की याद में मनाया जाता है। यह के. चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में राज्य के आंदोलन की सफलता और आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइज़ेशन एक्ट, 2014 को लागू करने का जश्न मनाता है।
3 जून	विश्व साइकिल दिवस	विषय: "ग्रीन फ्यूचर के लिए साइकिलिंग।" यह दिन साइकिलिंग को इको-फ्रेंडली, सस्टेनेबल और हेल्दी ट्रांसपोर्ट के तरीके के तौर पर बढ़ावा देता है, साथ ही पर्यावरण की सुरक्षा और सस्टेनेबल शहरी मोबिलिटी को भी बढ़ावा देता है।
5 जून	विश्व पर्यावरण दिवस	विषय: "प्रकृति से प्रेरित: क्लाइमेट के लिए। हमारे भविष्य के लिए।" अज़रबैजान (बाकू) द्वारा होस्ट किया गया यह कार्यक्रम क्लाइमेट एक्शन, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, प्रदूषण कंट्रोल और बायोडायवर्सिटी कंज़र्वेशन पर फोकस था।
8 जून	विश्व महासागर दिवस	विषय: "रीइमेजिन: उस दुनिया से आगे जिसे हम जानते हैं, हमारे महासागर के साथ एक नया रिश्ता।" इस दिन महासागर संरक्षण, समुद्री बायोडायवर्सिटी, क्लाइमेट रेगुलेशन और SDG-14 (पानी के नीचे जीवन) को पाने के महत्व पर ज़ोर दिया गया।
12 जून	विश्व बाल श्रम निषेध दिवस	विषय: "रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर: बच्चों के लिए फेयर प्ले, बड़ों के लिए डिसेंट वर्क।" यह दिन बाल मजदूरी के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और अच्छे रोजगार के मौकों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है।
15 जून	वैश्विक पवन दिवस	विषय: "विंड एनर्जी: एम्बिशन से एक्सेलरेशन तक।" इस दिन विंड एनर्जी में भारत की प्रोग्रेस पर ज़ोर दिया गया, जहाँ इंस्टॉलड कैपेसिटी 56.09 GW तक पहुँच गई , जिससे यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विंड एनर्जी प्रोजेक्टर बन गया।

तारीख	दिन / पालन	थीम / विवरण
17 जून	विश्व मगरमच्छ दिवस	विषय: "हर लेवल पर विरासत।" यह कार्यक्रम मगरमच्छों के संरक्षण को बढ़ावा देता है और घड़ियाल, मगर मगरमच्छ और खारे पानी के मगरमच्छों के लिए भारत के सफल संरक्षण प्रयासों को दिखाता है।
17 जून	विश्व मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने का दिवस	विषय: "रेंजलैंड्स: पहचानें। सम्मान करें। ठीक करें।" इस कार्यक्रम का मकसद बायोडायवर्सिटी, फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट रेजिलिएंस को मजबूत करने के लिए घास के मैदानों और रेंजलैंड्स को ठीक करना था।
18 जून	ऑटिस्टिक गौरव दिवस	विषय: "रिकग्निशन, रिप्रेजेंटेशन, और रिफॉर्म।" यह दिन दुनिया भर में ऑटिस्टिक लोगों की न्यूरोडाइवर्सिटी, इनक्लूजन, समान अवसरों और एक्सेप्टेंस को बढ़ावा देता है।
19 जून	विश्व सिकल सेल दिवस	विषय: "सर्वाइवल गैप को कम करना: सिकल सेल बीमारी में बराबरी।" यह कार्यक्रम सिकल सेल बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाता है और भारत के नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन को सपोर्ट करता है, जिसका टारगेट 2047 तक इसे खत्म करना है।
20 जून	विश्व शरणार्थी दिवस	विषय: "जब तक सब सुरक्षित न हो जाएं।" यह दिन शरणार्थियों की हिम्मत को पहचानता है और सुरक्षा, हेल्थकेयर, शिक्षा, रोजगार, सम्मान और मानवीय मदद पर ज़ोर देता है।
23 जून	ओलंपिक दिवस	विषय: "आप यह कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।" यह दिन इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी (IOC) की स्थापना की याद में मनाया जाता है और फिटनेस, सबको साथ लेकर चलने और ओलंपिक मूल्यों को बढ़ावा देता है।
23 जून	संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस	विषय: "पब्लिक इंस्टीट्यूशन्स को बदलना: इनोवेशन, पार्टिसिपेशन और इन्क्लूजन को आगे बढ़ाना।" यह दिन पब्लिक सर्वेंट्स के योगदान को पहचान देता है और इनोवेशन, ट्रांसपेरेंसी और सिटिजन-सेंट्रिक गवर्नेंस को बढ़ावा देता है।
24 जून	कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस	डिप्लोमेसी, शांति स्थापना, झगड़े सुलझाने और इंटरनेशनल सहयोग में महिलाओं के योगदान को पहचानने और डिप्लोमैटिक लीडरशिप में जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए यह दिन मनाया जाता है।
25 जून	विश्व विटिलिगो दिवस	विषय: "कलंक से ताकत तक।" स्लोगन: "कई शेड्स, एक आवाज़।" यह दिन विटिलिगो के बारे में जागरूकता बढ़ाता है, जल्दी डायग्नोसिस को बढ़ावा देता है, स्टिग्मा से लड़ता है, और सोशल इन्क्लूजन को सपोर्ट करता है।
26 जून	नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस	यह दिन ड्रग्स के गलत इस्तेमाल के बारे में जागरूकता बढ़ाने, रोकथाम, रिहैबिलिटेशन और गैर-कानूनी ड्रग्स की तस्करी के खिलाफ इंटरनेशनल सहयोग को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है।
26 जून	संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय यातना पीड़ितों के समर्थन दिवस	टॉर्चर को खत्म करने, न्याय को बढ़ावा देने, रिहैबिलिटेशन, अकाउंटेबिलिटी और ह्यूमन राइट्स की सुरक्षा के लिए दुनिया भर के कमिटमेंट को पक्का करने के लिए मनाया जाता है।
27 जून	विश्व एमएसएमई दिवस	विषय: "इनोवेशन और सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ज़रिए MSMEs को मजबूत बनाना।" यह दिन रोजगार पैदा करने, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ में MSMEs के योगदान को पहचान देता है।

स्टेटिक टेकअवे

पहलू	विवरण
म्यांमार	राष्ट्रपति: मिन आंग ह्लाइंग राजधानी : नेपीता
कंबोडिया	प्रधानमंत्री: हुन मानेट राजधानी : नोम पेन्ह
वेनेज़ुएला	राष्ट्रपति: डेल्सी रोड्रिगेज राजधानी : काराकास
नाँर्वे	प्रधानमंत्री: जोनास गहर स्टोर राजधानी : ओस्लो
फ्रांस	राष्ट्रपति: इमैनुएल मैक्रों राजधानी : पेरिस
यूनाइटेड किंगडम (इंग्लैंड)	प्रधानमंत्री: कीर स्टारमर राजधानी : लंदन
जर्मनी	चांसलर: फ्रेडरिक मर्ज़ राजधानी : बर्लिन

पहलू	विवरण
जापान	प्रधानमंत्री: फुमियो किशिदा राजधानी : टोक्यो
नेपाल	प्रधानमंत्री: बालेन शाह राजधानी : काठमांडू
संयुक्त राज्य अमेरिका	राष्ट्रपति: डोनाल्ड ट्रम्प
इटली	प्रधानमंत्री: जॉर्जिया मेलोनी
कर्नाटक	मुख्यमंत्री: डीके शिवकुमार राज्यपाल : थावर चंद गहलोत राजधानी : बेंगलुरु
महाराष्ट्र	मुख्यमंत्री: देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल : जिष्णु देव वर्मा राजधानी : मुंबई
असम	मुख्यमंत्री: हिमंत बिस्वा सरमा राज्यपाल : लक्ष्मण प्रसाद आचार्य राजधानी : दिसपुर
गुजरात	मुख्यमंत्री: भूपेंद्र पटेल राज्यपाल : आचार्य देवव्रत राजधानी : गांधीनगर
दिल्ली	मुख्यमंत्री: रेखा गुप्ता उपराज्यपाल : तरनजीत सिंह
पश्चिम बंगाल	मुख्यमंत्री: सुबेंदु अधिकारी राज्यपाल : आरएन रवि राजधानी : कोलकाता
उत्तर प्रदेश	मुख्यमंत्री: योगी आदित्यनाथ राज्यपाल : आनंदीबेन पटेल राजधानी : लखनऊ
तमिलनाडु	मुख्यमंत्री: जोसेफ विजय राज्यपाल: आर. आर्लेकर राजधानी : चेन्नई
केरल	मुख्यमंत्री: वीडी सतीशन राज्यपाल : आर. आर्लेकर राजधानी : तिरुवनंतपुरम
ओडिशा	मुख्यमंत्री: मोहन माझी राज्यपाल : हरि बाबू कंभमपति राजधानी : भुवनेश्वर
बिहार	मुख्यमंत्री: सम्राट चौधरी राज्यपाल : आरिफ खान राजधानी : पटना
झारखंड	मुख्यमंत्री: हेमंत सोरेन राज्यपाल : संतोष गंगवार राजधानी : रांची
आंध्र प्रदेश	मुख्यमंत्री: एन. चंद्रबाबू नायडू राज्यपाल : एस. अब्दुल नजीर राजधानी: अमरावती
मध्य प्रदेश	मुख्यमंत्री: मोहन यादव राज्यपाल: मंगूभाई पटेल कैपिटल : भोपाल
मेघालय	मुख्यमंत्री: कॉनराड के. संगमा राज्यपाल : सीएच विजयशंकर राजधानी : शिलांग
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)	राज्यपाल: संजय मल्होत्रा
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)	अध्यक्ष: तुहिन कांता पांडे
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी)	अध्यक्ष: जय शाह
विश्व बैंक	अध्यक्ष: अजय बंगा
गृह मंत्रालय	मंत्री: अमित शाह
वित्त मंत्रित्व	मंत्री: निर्मला सीतारमण
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	मंत्री: पीयूष गोयल
विदेश मंत्रालय	मंत्री: एस. जयशंकर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	मंत्री: शिवराज सिंह चौहान
फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पश्चिमी नौसेना कमान	वाइस एडमिरल: संजय वात्स्यायन
नौसेना स्टाफ के प्रमुख (27वें)	एडमिरल: कृष्णा स्वामीनाथन
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ	जनरल: एनएस राजा सुब्रमणि
कमांडर-इन-चीफ, अंडमान और निकोबार कमांड (20वीं)	वाइस एडमिरल: विनीत मैकार्थी
एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, मध्य वायु कमान	एयर मार्शल: तरुण चौधरी